

# विकेन्द्रित नियोजन

वार्षिक - योजना

(प्रस्ताव)

वर्ष १९८७-८८



जिला सेक्टर योजना

जनपद-भाँती

- 5423,111  
309 " 22-16  
619 111... V

- 2131  
~~PIN-4~~  
~~ATT-V~~





54231  
309.26  
UTT-V

**Sub. National Systems Unit,**  
**National Institute of Educational**  
**Planning and Administration**  
**7-B, Sardar Bhai Marg, New Delhi-110016**  
CC. No. 3814  
Date 16/01/87

:: प्रस्तावना ::  
=====

प्रदेश में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली वर्ष 1982-83 से चल रही है। प्रदेशीय आयोजनागत वजट के 30 प्रतिशत भाग में जनपद झांसी को वर्ष 1982-83 में 294-8, वर्ष 1983-84 में 309-54, 1984-85 में 331-21, 1985-86 में 368-36 लाख रुपये की जिला स्तरीय योजना बनाई गई तथा क्रियान्वित की गई। चालू वर्ष 1986-87 के लिये 428-99 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया तथा इस स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 1987-88 हेतु शासन द्वारा 490-14 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसके लिये योजना बनाकर प्रस्तुत है। जनपद विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह परिव्यय बहुत कम है, जिसके कारण नई योजनाओं की आवश्यकता होते हुए भी बहुत कम धन उपलब्ध हो सका तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुना गया।

2- जिला सेक्टर योजना हेतु प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए जनपद झांसी की वर्ष 1987-88 की जिला योजना 4,90-14 लाख रुपये की निम्न विन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित की गई।

॥१॥ राज्य योजना आयोग एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त निर्देश एवं मार्गदर्शन।

॥२॥ जनपद के जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों से प्राप्त मांग पत्र।

॥३॥ जनपद में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताएँ।

॥४॥ जनपद स्थित विकास विभागों के विगत वर्षों के क्रियाकलाप।

3- शासन की नीति के अनुसार मैं यह भी प्रमाणित कर रही हूँ कि:

॥१॥ जिला स्तरीय स्तरीय समितियों का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

॥२॥ अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक प्राविधान कर लिया गया है।

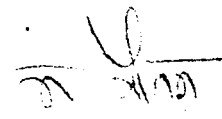
131 जनपद में चल रही केन्द्र पुरोनिधानित/वाहरी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिये राज्यांश के रूप में प्राविधान कर लिया गया है ।

141 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की मदों हेतु यथेष्ट प्राविधान सुनिश्चित कर लिया गया है ।

151 शासन को प्रस्तुत की जा रही जिला योजना में स्थल चयन का उल्लेख, नई योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं औचित्य, निर्माणा एजेंसी का नाम प्रस्तावित कर दिया गया है ।

4- इस योजना की संरचना में श्री रुद्र शेखर मिश्र, अपर जिलाधिकारी विकास, श्री सतीश चन्द्र सक्सेना, जिला संख्याधिकारी, श्री राग प्रसाद गुप्त, सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारीका प्रयास सराहनीय है, जिन्होंने विशेष लगन एवं परिश्रम से इसे तैयार करने में सहयोग दिया है ।

5- योजना के ठंण एवं छपाई में विकास कार्यालय के लिपिक श्री वी० आर० करकरे एवं राजेन्द्र कुमार पटैरिया तथा संख्याधिकारी कार्यालय के लिपिक श्री रमेश चन्द्र टेलर व श्री गुन्नालाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का योगदान भी प्रशंसनीय है ।

  
 मंजुलिका गौतम  
 आर० आर० आर० आर०  
 जिलाधिकारी,  
 झांसी ।

अध्याय-1

1. भूमिका  
=====

1.0 :- जनपद झांसी उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिम कोने में 25.3 और 24.57 उत्तरी अक्षांश एवं 78.40 और 79.25 देशांतर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में जनपद जालौन, पूर्व में हमीरपुर, दक्षिण में ललितपुर तथा सम्पूर्ण पश्चिमी भाग और दक्षिण का कुछ भाग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद 4 तहसीलों में विभाजित है। जनपद में कुल 758 <sup>आवाड़</sup> ग्रामों को 602 गांव सभाओं के अधीन रखा गया है।

1.1 :- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रसाद एवं संचालन हेतु जनपद में 8 विकास खण्ड प्रत्येक विकास खण्ड में 10 ग्राम विकास अधिकारी कार्यरत हैं। प्रत्येक तहसील में 2 विकास खण्ड हैं। विकास खण्डवार ग्रामों का विवरण निम्न है।

क्रम सं०	विकास खण्ड का नाम	तहसील का नाम	कुल आवाड़ ग्रामों की संख्या	कुल गांव सभायें
1.	वड़ागांव	झांसी	82	67
2.	ववीना	,,	73	64
3.	वामौर	गरौठा	100	82
4.	गुरसराय	,,	107	83
5.	मउरानीपुर	मउरानीपुर	83	71
6.	वंगरा	,,	82	68
7.	मोंठ	मोंठ	124	86
8.	चिरगांव	,,	107	81
	योग		758	602

1.2 :- प्राकृतिक संरचना के अनुसार जनपद दो सम्भागों में विभाजित हो सकता है। प्रथम उत्तरी सम्भाग, जिसमें अधिकांश मैदानी क्षेत्र है, मार, कांवर, एवं पडुवा की मिट्टी पायी जाती है। मार काली मिट्टी है जिसकी सतह चिकनी और एवं चूने से मिश्रित है। कृषि के दृष्टिकोण से उपजाऊ माना जाता है और गेहूं, चना, मटर, ज्वार मुख्य फसलें होती हैं। इसके अन्तर्गत चिरगांव, मोंठ, वामौर, गुरसराय एवं मउरानीपुर 5 विकास खण्ड हैं। द्वितीय सम्भाग में विकास खण्ड वंगरा, वड़ागांव एवं ववीना है। विन्ध्याचल पहाड़ के श्रंखला के कारण भूमि पठारी है। यहां पीले और भूरे प्रकार की मिट्टी



है। यह बेतवा एवं पहूज नदियों के बेसिन में पायी जाती है। इस भाग में पहाड़ झाड़ियों वाले जंगल और ढंजर भूमि मिलती है। कांवर, मार और पड़वा का मिश्रण 40 से 50 प्रतिशत मिट्टी चिकनी होती है। इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता है। इसमें गेहूँ, चना, मटर और ज्वार एवं अलसी मुख्यता पैदा होती है। रांकर मिट्टी जो पहाड़ियों पर पायी जाती है और कृषि के दृष्टिकोण से कम उपयोगी होती है। बेतवा एवं पहूज तथा सुखनई यहीं की मुख्य नदियाँ हैं।

### जलवायु

1.3 :-

जनपद की जलवायु विशेषता यह है कि ग्रीष्म काल में अधिक गर्मी तथा शीतकाल में अधिक ठंडा होता है। मध्य नवम्बर से जनवरी तक अधिक ठंडक तथा गर्मी एवं जून में अधिक गर्मी होती है। गर्मियों में आर्द्रता 20 प्रतिशत से कम हो जाती है और हवा अधिक गरम चलती है। जनपद में वर्षा का सामान्य औसत 1101 मि०मी० है, परन्तु वास्तविक रूप से वर्षा किसी वर्ष काफी अधिक और किसी वर्ष काफी कम हो जाती है। विंध्याचल की पहाड़ी श्रंखला होने के कारण वार्षिक होने पर शीघ्र ठंडी और घूम होने पर शीघ्र गर्मी का आभास होता है।

1.4 :- गत 1980-81 से 1984-85 तक तापमान एवं वर्षा की स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है।

वर्ष	तापमान		वर्षा मि०मी० में	
	उच्चतम	न्यूनतम	सामान्य	वास्तविक
1980-81	45.3	4.2	1101.0	1138.0
1981-82	44.6	3.4	981.0	718.0
1982-83	44.5	1.2	848.0	1194.0
1983-84	46.4	4.0	848.0	1313.0
1984-85	48.2	4.1	944.0	623.0

1.5 नदियाँ एवं जल निकास :-

बेतवा, धसरन, लखेरी एवं पहूज यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। बेतवा जनपद की सबसे लम्बी नदी है। यह भोपाल इ.प्र. से निकलकर ललितपुर की पश्चिमी सीमा बनाती हुई जनपद के दक्षिण पश्चिम कोने से प्रवेश करती है। तथा गाताटीला कड़ागाँव पारीक्षा होते हुए जालौन जनपद में प्रवेश करती है।

समें नत्रजन तथा फासफोरस की कमी तथा पोटैश की अधिकता होती है । संकुचित जल निकास इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यह निचले भूभागों में पायी जाती है ।

1.7 भूमि उपयोगिता :-

जनपद झांसी की वर्ष 1983-84 में भूमि उपयोगिता का विवरण पुस्तिका के आधार भूत आंकड़ों के प्रथम अनुच्छेद में दिया गया है । वर्तमान समय में 63.0 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है । जिसमें विगत वर्षों से लगभग 3 प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

1.8 भू गर्भ जल :-

जनपद झांसी में विन्ध्याचल की पहाड़ी श्रंखला होने के कारण एक विशेष भौतिक संरचना पायी जाती है । भूगर्भ जल का उपयोग सुगमता से कुछ क्षेत्रों में हो पाता है परन्तु अल डी 0 टी 0 रिंग मशीन तथा इनवेल रिंग द्वारा इस कठिनाई को दूर कर दिया गया है । इसके प्रयोग से जनपद में व्यक्तिगत नलकूप खोदे जाने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है । जनपद राजकीय नलकूप भी इसी आधार पर लगाये जा रहे हैं । भू गर्भ सर्वेक्षण हेतु रिपोर्ट सेन्स यूनिट स्थापित है, जो शीघ्र सर्वे करके जल भण्डारण की भूचना स्थान पर बताती है । यह यूनिट अपना कार्य कर रहा है ।

1.9 वन :-

जनपद झांसी में वर्ष 1983-84 में 32544 है० भूमि वन के अन्तर्गत आच्छादित रही जो प्रतिवेदित क्षेत्र का 6.6 प्रतिशत है । यहां के जंगलों में बबूल, गहुआ, तेंदू तथा ढाक अच्छी मात्रा में पायी जाती है । जंगल का 50 प्रतिशत से अधिक भाग ईंधन वाले वृक्षों के अन्तर्गत है । विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण एवं आर्थिक महत्व के प्रजातियों के वृक्षारोपण कार्यक्रम सुखतरा चलाया जा रहा है । जनपद में विकास खाण्डवार जंगलों का वितरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है ।

क्षेत्र हेक्टेअर में

1. चिरगांव	5141	2. गऊरा नीपुर	264
3. झोंठ	4236	4. लंगरा	2935
5. गुरतरांव	3487	6. बवीना	6131
7. वामौर	10229	8. बड़गांव	221

1.10 खनिज सम्पदा :-

खनिज सम्पदा के रूप में जनपद में ग्रेनाइट, पाहरो-पिलाइट, फ्लैशाल पाये जाते हैं । झांसी तहसील में ग्रेनाइट तथा झोंठ तहसील में पाहरोपिलाइट एवं फ्लैशाल ग्रेनाइट विशेष रूप से पाया जाता है । झारखण्ड की गिरिद्वारा सड़कों के निर्माण एवं फ्लैशाल का विभिन्न विद्युत

वेतवा नदी पर 3 बांध हैं। पारीक्षा सिंचाई बांध है जिससे भांडेर एवं गुरसराय नहरें निकाली गयी है, जिसकी लम्बाई 387 एवं 251 कि०मी० है। दूसरा बांध सुकुवा टुकुवा है। यह पारीक्षा की पीडिंग रिजरवायर है। सबसे नवीन बहुउद्देशीय बांध माताटीला है। यह ललितपुर जनपद में स्थित है।

धसान नदी पर पहाड़ी बांध सररानीपुर छतरपुर सड़क पर स्थित है। इस नदी पर ही लहचूरा सिंचाई बांध है जिससे धसान नहर प्रणाली निकली है। इसके अतिरिक्त सिंचाई कार्य हेतु कपलासागर, पडूज बांध तथा गढ़गऊ, बरअसासागर, बड़वार, स्यावरी, पचवारा, क्यन्हे, बलीना झीलें हैं। सिंचाई विभाग द्वारा डोंगरी एवं सपरार बांधों का निर्माण किया जा रहा है।

#### 1.6 :- मृदा :-

जनपद की मिट्टी मुख्यतः काली, पीली व काली है। लाल मिट्टी की रचना कणाशय तथा सफटिक से संबंधित है तथा यह अधिकांश उच्च भागों पर मिलती है। इसे दो उप श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

11। राकड़ :- यह साधारणतः लाल रंग छिदली, कंकरीली तथा बनावट में बहुत हल्की होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। इसके अंदर प्रागैरिक द्रव्य, नत्रजन तथा फासफोरस की गहृत कमी होती है।

12। पडुवा :- यह मिट्टी रंग में हल्की भूरी बनावट में मध्यम वर्गीय अच्छी जल उत्पादित तथा खरीफ की फसल के लिये उपयुक्त है। यह मिट्टी 40 से०मी० से 70 से०मी० तक गहरी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता 100 से 250 मि०मी० है। इसमें नत्रजन तथा फासफोरस की कमी पायी जाती है। काली मिट्टी अच्छी तथा जल ग्रहण क्षमता वाली तथा उपजाऊ होती है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

11। कांवर :- यह मिट्टी निचले समतल भूभागों में मिलती है। इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में कंकड़ कम पाया जाता है। फिर भी यह संतता एवं दृढ़ होती है।

12। मार :- यह मिट्टी रंग में अधिकांश काली होती है तथा इसमें कंकड़ के पिंड पाये जाते हैं। बनावट में अच्छी तथा अधिक जल धारण वाली होने के कारण यह मिट्टी रबी की फसल जैसे गेहूं व चना उगाने के लिये अधिक उत्तम होती है।

वर्तन बनाने का उपयोग में होता है। इसके अतिरिक्त नदियों से काफी बालू प्राप्त होती है।

### 1.11. पशुधन :-

पशुधन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पशु गणना प्रदेश में पांच वर्ष में करायी जाती है। अंतिम पशु गणना वर्ष 1982 में की गयी थी। वर्ष 1982 की पशुगणना के अनुसार जनपद में कुल 759314 पशु थे। जिनमें सबसे अधिक पशुं गरौठा तहसील में तथा सबसे कम पशु 160292 गोंठ तहसील में हैं। जनपद में दूधा देने वाली गायें व भैंसें 120589 व 60292 हैं। जनपद में 239369 भेड़ें व बकरियाँ पाली जाती हैं। सबसे अधिक भेड़े बकरियों गरौठा तहसील में हैं। सबसे कम भेड़े बकरियों गोंठ तहसील में हैं।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में पशुधन का भार प्रदेश की तुलना में कम है। क्योंकि जनपद का कुल पशुधन का घनत्व 130 है तथा प्रदेश का घनत्व 178 है।

जनपद में 79375 कुक्कुट है। इसकी जनपद में घनत्व 12 है जबकि प्रदेश में घनत्व 19 है। इस तरह कुक्कुट का भी घनत्व कम है।

जनपद में महश्रि वंशीय व गोवंशीय पशुओं की संख्या का कुल पशुओं की संख्या लगभग 73 प्रतिशत है।

पशुपालन व्यवसाय को आर्थिक महत्व देने की दिशा में यह आवश्यक है कि पशुओं की नस्ल सुधार, <sup>स्वास्थ्य</sup> रक्षा एवं उनकी उचित मात्रा में पोषक आहार की समुचित व्यवस्था की जाय ताकि उनकी दुग्ध उत्पादकता में विकास हो सके। जनपद में इस संबंध में जो कार्य किये गये हैं उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1.	पशुचिकित्सालय	15
2.	पशुधन विकास केन्द्र	16
3.	कृत्रिम गर्भाधान एवं उपकेन्द्र	20
4.	पशु प्रजनन फार्म	1
5.	भेड़ विकास केन्द्र	8
6.	सुअर विकास केन्द्र	11

जनपद में चारे की समस्या तथा इसी क्षेत्र में अनुसंधान हेतु एक भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कार्यरत है।

1.12 :- जनपद में राजकीय जलाशयों में मत्स्य पालन हेतु 5.88 हे० क्षेत्र क्लिप्त गया है । जिसमें जिस नर्सरी कार्यरत है । जनपद में गढ़गऊ, सिसौरै, तरुआसागर, गणखारा एवं कोंछाभांवर झील एवं तालाब हैं । पारखवासी जलाशय मुख्यतः लंगरा, मऊरानीपुर, चिरगांव एवं गुरसरांग विकास खाण्डों में हैं । जनपद में मछली उत्पादन क्षेत्रों में मछलीकेजीरा उत्पादन हेतु पाण्डन, रेगन, शाल, सीफार, फीओं आदि पाली जाती हैं । मत्स्य उद्योग के विकास के लिये 6 मछुआ सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं ।

1.13 जनशक्ति :- जनगणना 1971 के अनुसार झांसी जनपद कुल जनसंख्या 8.70 लाख थी जो वर्ष 1981 में 11.37 हो गई है । वर्ष 1971 में 4.63 लाख पुरुष एवं 4.07 लाख स्त्री है जो वर्ष 1981 में बढ़कर 6.08 लाख पुरुष तथा 5.29 लाख स्त्री हो गयी है । वर्ष 1981 जनसंख्या वृद्धि दर 30.67 रहा । तुलनात्मक जनसंख्या कक्ष विवरण निम्न प्रकार है ।

1.14 तहसील वार जनसंख्या :-

तहसील का नाम		वर्ष 1971 की जनगणना अनुसार [लाखों में]	वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार [लाखों में]
झांसी	नगरीय	2.79	4.31
	कुल जनसंख्या	8.70	11.37
गोंठ	नगरीय	0.21	0.35
	कुल जनसंख्या	1.34	2.16
गरौठा	नगरीय	0.09	0.26
	कुल जनसंख्या	1.71	2.09
मऊरानीपुर	नगरीय	0.33	0.50
	कुल जनसंख्या	1.82	2.32
झांसी	नगरीय	2.16	3.20
	कुल जनसंख्या	3.45	4.79

1.15 :-

इस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 30.21 रही ।

1.16 :- घनत्व :-

5024 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र वाले इस जनपद में 1971 की जनसंख्या आधार पर घनत्व 173 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जबकि 1981 की जनसंख्या के आधार पर इसका बढ़कर 226 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गयी ।

जनपद का सबसे ज्यादा घनत्व वाला क्षेत्र तहसील झांसी है। सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में लदीना तथा बागौर क्षेत्र हैं तथा वड़ागांव विकास क्षेत्र सबसे बड़ा घनत्व वाला है।

1.17 ग्रामीण तथा नगरीय आवादी :- 1981 के अनुसार जनपद की 76.9 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती थी। 1981 की जनगणना-नुसार यह प्रतिशत 62.3 रह गया। स्पष्ट है कि नगर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है जिसका कारण नगर क्षेत्रों की घीषणा तथा जनता का ग्रामों से नगरों की ओर सुविधा दृष्टिकोण पलायन रहा है।

1.18 पुरुषा तथा स्त्रियों का अनुपात :- वर्ष 1981 की जनगणनानुसार पुरुष 6.08 एवं 6.29 लाख स्त्रियां हैं। प्रति हजार पुरुषों में 868 स्त्रियां हैं।

1.19 अनुसूचित जातियां :- वर्ष 1981 की जनगणनानुसार 3.25 लाख अनुसूचित जातियों के लोग निवास करते हैं जो कि कुल आवादी का 28.7 प्रतिशत है। 1971 से 1981 दशक में जनपद की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत स्थिर रहा।

1.20 श्रम शक्ति [कर्मकार] :- जनपद में कर्मकारों के 1971 व 1981 के तुलनात्मक आंकड़े निम्न तालिका में दिये जा रहे हैं।

कर्मकार की श्रेणी	1971 की जनगणनानुसार	1982 की जनगणनानुसार प्रतिशत
1. कृषक	47.4	48.6
2. कृषक मजदूर	18.1	12.5
3. पारिवारिक उद्यमों में लगे मजदूर	8.2	5.8
4. अन्य कर्मकार	26.3	33.1
कुल कर्मकारों का प्रतिशत जनसंख्या से	28	28

प्रदेशा में कर्मकारों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

1. कृषक	58
2. कृषक मजदूर	16.3
3. पारिवारिक उद्यम	4.4
4. अन्य	21.3

इस तरह जनपद में कृषक कर्मकार प्रदेशा के औसत से कम है और अन्य कार्यों में प्रतिशत अधिक है।

1.21 साक्षरता :-

जनपद में 1981 की जनगणना के अनुसार 36.7 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। कुल ग्रामीण आबादी की 28.1 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है तथा कुल नगरीय आबादी का 50.9 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। प्रदेश का साक्षरता का 27.4 प्रतिशत है। इस तरह प्रदेश के स्तर से अधिक व्यक्ति जनपद में साक्षर हैं। जनपद में 50.3 प्रतिशत पुरुष तथा 21.0 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। प्रदेश में 38.9 प्रतिशत पुरुष तथा 14.4 स्त्रियां साक्षर हैं।

## अध्यय-2

2-0 संचार साधन:- किसी भी क्षेत्र के विकास में संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण योग है। संचार व्यवस्था की पर्याप्तता क्षेत्र के विकास स्तर की संकेतक है। जनपद में उपलब्ध संचार व्यवस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

2-1 रेल व्यवस्था:- झांसी मध्य रेल का मंडलीय मुख्यालय है। झांसी रेल द्वारा बम्बई, मुगलसराय, कलकत्ता, देहली जम्मू, जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों से सम्बद्ध है। जनपद में 171 कि०मी० ब्राडगेज रेल मार्ग है। तथा 15 रेलवे स्टेशन, हॉल्ट सहित, स्थित है। जनपद के वर्तमान 746 आबाद ग्रामों में से 51 ग्रामों को 1 से 3 कि०मी० की दूरी पर 58 ग्रामों को 3 से 5 कि०मी० की दूरी पर तथा शेष 637 ग्रामों को 5 कि०मी० से अधिक दूरी पर रेल सेवा उपलब्ध है।

2-2 सड़क:- सड़क व्यवस्था के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग स्थानीय निकायों की पक्की सड़कों तथा ग्रामीण अंचलों में गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने हेतु असमतल सड़क है। मार्च 1985 तक जनपद में 776.78 कि०मी० विपत मार्ग 362.69 कि०मी० खड़जा मार्ग 173 कि०मी० मिट्टी स्तर के कार्य निर्मित हैं। स्थानीय निकायों की 133 कि०मी० लम्बी पक्की सड़कें हैं।

2-2 इन पक्की सड़कों पर आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिये केवल सरकार बस 90 कि०मी० केवल निजी बस 450 कि०मी० तथा निजी बस 450 कि०मी० तथा निजी और सरकारी बस 202 कि०मी० सड़कों पर चलती हैं।

ग्रामीण अंचल की आवागमन की सुविधा निम्नवत है:-

विवरण	ग्राम में	1 कि०मी० से कम	1 कि०मी० से 3 कि०मी० तक	3 कि०मी० से 5 कि०मी० तक	5 कि०मी० से ऊपर	योग
1-पक्की सड़कें	161	35	164	165	221	746
2-बस स्टाप	79	30	85	135	417	746

आवागमन एवं सामग्री की पूर्ति परामर्श एवं ज्ञान प्राप्त करने हेतु ग्रामीण अंचल का मुख्य केन्द्र विकास कार्यालय है। 31 मार्च 85 तक आबादी के अनुसार सड़कों से जुड़े ग्रामों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

आबादी के अनुसार ग्राम सं०	सड़क से जुड़े
1500 से अधिक	55
1000 से 1499 तक	53
500 से 999 तक	107
500 से कम	111



2-4 डाक एवं तार व्यवस्था:- वर्ष 1984-85 में जनपद में 200 डाकघरों की संख्या थी। जिसमें 160 ग्रामीण अंचल तथा 40 नगरीय क्षेत्र में थी। इन डाकघरों में बचत बैंक की सुविधा उपलब्ध है। इन डाकघरों में 31 केन्द्रों 12 ग्रामीण तथा 19 नगरीय केन्द्रों पर सर्व साधारण को तार की व्यवस्था उपलब्ध है। ग्रामीण अंचल में डाक एवं तार की व्यवस्था की सुविधा निम्नवत है:-

विवरण	ग्राम में सुविधा	सुविधा केन्द्रों से ग्रामों की दूरी				योग
		1 किमी० से कम	1-3 कि० मी० तक	3-5 कि० मी० तक	5 किमी० या अधिक	
1-पोस्ट आफिस एवं बचत बैंक	149	17	162	202	216	746
2-तारघर	12	3	38	70	623	746

2-5 क्रय विक्रय सम्बन्धी सुविधायें:- दैनिक जीवन के उपभोग हेतु सामग्री का क्रय विक्रय बाजारों के माध्यम से होता है। जनपद में नियंत्रित एवं अनियंत्रित बाजार प्रतिदिन एवं साप्ताहिक बाजार लगते हैं। मुख्य बाजारों का विवरण निम्नवत है:-

तहसील का नाम	बाजार संख्या	वस्तुओं की बिक्री
1- सोठ	10	प्रतिदिन उपभोग की वस्तुएं
2- गरौठा	23	“ “ “ “
	1	पशुओं की बिक्री
3- मकरानीपुर	27	प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुएं
	1	पशुओं की बिक्री ।
	2	प्रतिदिन उपभोग एवं कपड़े
4- झांसी	5	प्रतिदिन उपभोग एवं कपड़े
	1	पशुओं की बिक्री ।

2-6 क्रय-विक्रय समितियाँ:- जनपद में 6 क्रय विक्रय समितियाँ हैं जो कृषक सदस्यों को कृषि उपज की उचित मूल्य पर क्रय विक्रय भण्डारण की व्यवस्था की कार्य करती हैं। इन समितियों में 3 ग्रामीण क्षेत्र तथा 3 नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन समितियों द्वारा कृषकों को उपज की सीधी खरीद का कार्य किया जाता है। जितने धीरे-धीरे विद्योक्तियें समाप्त हो जायेंगे।

2-7 उपभोक्ता समितियों की स्थापना जन साधारण को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं के उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से हुयी है। इस जनपद में केन्द्रीय उपभोक्ता भन्डार जो बड़ागाँव एवं बबीना विकास खण्ड में सहकारी समितियों के समिति के रूप में कार्य कर रही है। उपभोक्ता भन्डार खाद्यान्न एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को आपूर्ति नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को करती है। जनपद में 26 प्राथमरी उपभोक्ता भन्डार की स्थापना हुयी है। वर्ष 1984-85 में जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण अंचल में कुल 334 सस्ते गल्ले को दुकानें रही ।

2-8 नियंत्रित बाजार:- विपणन व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद में 5 नियंत्रित बाजार हैं। इनका विवरण निम्नवत है:-

मण्डी का नाम	अधिनियम लागू होने का दिनांक	मण्डी की श्रेणी	मण्डी की वस्तुओं की उपलब्धता
1-मऊरानीपुर	नवम्बर 1960	ए	प्रतिदिन के उपभोग की वस्तुओं
2-चिरगाँव	जुलाई 1968	ए	,,
3-मोठ	जुलाई 1968	बी	,,
4-गुरसराय	जुलाई 1969	बी	,,
5-झाँसी	दिसम्बर 1970	बी	,,

2-9 संग्रहण एवं डेयर हाऊसिंग:- जनपद में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम हैं। इसका विवरण निम्नवत है:-

	संख्या	क्षमता (मै0टन)
1- निजी खाद्य गोदाम	5	18340
2- किराये पर झाँसी में	4	9170
3- किराये पर मऊरानीपुर में	2	5000
4- किराये पर परीछा में	3	15000
योग:-	14	47510

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय भण्डारगार निगम के 2 गोदाम किराये पर झाँसी एवं चिरगाँव में हैं। जिनकी क्षमता क्रमशः 4878 एवं 3669 मै0टन है। केन्द्रीय भण्डारगार के एक डेयर हाऊस का निर्माण चल रहा है ।

जनपद में 700 मैटन की क्षमता का एक शोत गोदावरी है। इसके अतिरिक्त दो कोल्ड स्टोरज एवं आइस फ़ैक्ट्री कार्यरत हैं ।

2-10 सिंचाई:- जनपद में सिंचाई की सुविधाएँ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं। शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत भाग में ही सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वर्तमान साधनों में नहरों का स्थान सर्वप्रथम है। वर्ष 84-85 तक जनपद में 198 कि०मी० लम्बी नहरें 52 राजकीय नलकूप 27548 सिंचाई कूप 11783 रहद 13355 पम्प सेट तथा 554 निजी नलकूप उपलब्ध है ।

वर्ष 1984-85 के अभिलेखानुसार राजकीय नहरों से 57347 हे०भूमि में सिंचाई की गई है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 64 प्रतिशत है। शेषक्षेत्र में निजी लघु सिंचाई साधनों से सिंचाई की जा रही है ।

2-11 जनपद में वर्ष 80-81 तक राजकीय नलकूपों की सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी, पर शतशं प्रयास करके वर्ष 84-85 तक 52 राजकीय नलकूप लगाये जा चुके हैं। जो एक विशेष उपलब्धि है ।

2-12 विद्युत:- कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र में विकास लाने के दृष्टिकोण से विद्युत का महत्वपूर्ण स्थान है। जनपद में वर्ष 84-85 में कुल 105795 कि०घ० विद्युत का उपयोग हुआ जिसमें 27.6 प्रतिशत घरेलू प्रकाश 26.4% लघु विद्युत शक्ति 354.010 शक्ति 0.49 प्रतिशत सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था 8.8 प्रतिशत सिंचाई एवं जल निस्तारण 1-58 प्रतिशत सार्वजनिक जलकल एवं प्रवाह तथा शेष विविध प्रयोग हेतु व्यय हुआ । वर्ष 84-85 में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपयोग 93 कि०घ० रहा ।

2-13 विद्युत लाइनों की लम्बाई एवं विद्युतीकरण गाँव/नगर:- विद्युत लाइनों की लम्बाई एवं विद्युतीकृत नगर एवं ग्राम जनपद झारखी में वर्ष 81 की जन गणना के अनुसार 16 नगरीय क्षेत्र हैं। जो सभी विद्युतीकृत हैं। कुल 750 गाँवों में से 372 गाँव विद्युतीकरण हैं। इस प्रकार कुल विद्युतीकरण गाँवों की संख्या 49 प्रतिशत है। अब तक 380 हरिजन वस्तियों को विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

2-14 बैंक एवं ऋण सुविधाएँ :- जनपद झारखी में वर्ष 84-85 में कुल 96 बैंक शाखाएँ कार्यरत रही हैं। जिनमें 62 व्यवसायिक, 12 सहकारिता, 4 ग्रामीण विकास बैंक तथा 20 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाएँ हैं। इन बैंक शाखाओं द्वारा नगरीय क्षेत्रों तथा अग्रम्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, अल्प सिंचाई, उद्योग एवं सौवाएँ हेतु ऋण वितरण की योजना बनायी गयी है और ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से ऋण वितरण का कार्य किया जाता है। विकास कार्य हेतु बैंकों द्वारा

ऋण योजनायें बनायीं गयीं हैं। ऋण योजना का विवरण निम्नतालिका में दिया गया है :-

₹ हजार रु० में

अद्वय का नाम	1981		1982	1983-84
	लक्ष्य	पूर्ति		
1-कृषि का सर्वांगीकरण	51897	60668	61995	53922
2-गांधीजयंती कृषि उद्योग	1895	2061	3176	8748
3-लघु उद्योग	3812	3059	2085	638348
4- अन्य	10479	47336	15027	638348

00000=-----=00000

000=-----=000

00=-----=00

0=-----=0

0=-----=0

:: प्रशासनिक एवं संस्थागत ढाँचा ::

=====

3-0 प्रशासन की दृष्टिकोण से जनपद झारखंड मुख्यालय के अतिरिक्त चार तहसीलों में बँटा है। सम्पूर्ण जनपद का प्रशासनिक कार्य जिलाधिकारी के आदेशानुसार कार्यान्वित होता है। जिलाधिकारी के सहयोग के लिये एक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सेंटेलरिंट आफ़ीसर (चक्रवर्ती) नगर प्रशासन के लिये सिटी मजिस्ट्रेट तथा तहसील मुख्यालय पर परगनाधिकारी नियुक्त हैं।

3-1 तहसील मुख्यालयों पर परगनाधिकारी प्रशासनिक कार्य एवं शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त कृषि, पशुपालन के सर्वेक्षण कार्य कराये जा सके भूराजस्व, बैंक वकाया सिचाई देय, इत्यादि की वसूली दृष्टकों के अपस में भू-आवंटियों संबंधी मामलों का निस्तारण आवश्यक वस्तुओं के वितरण 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी परगनाधिकारी का है।

3-2 राजस्व संबंधी कार्यों के सम्पादन में परगनाधिकारी के सहायतार्थ प्रत्येक तहसील पर तहसीलदार नायब तहसीलदार एवं आवश्यकतानुसार कानूनगों को तवायें उपलब्ध हैं। ग्रास स्तर पर राजस्व कार्य के लिए अमीन एवं भूमि का लेखा-जोखा रखन हेतु लेखपाल नियुक्त हैं।

3-3 शांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जनपद में पुलिस व्यवस्था है। जनपद में 21 थाने कार्यरत हैं जिसमें 15 ग्रामीण एवं 6 नगरीय क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस चौकियाँ अपने सीमित क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करती हैं। शांति एवं व्यवस्था को सम्पन्न बनाने हेतु पुलिस एवं प्रशासन पारस्परिक सहयोग रखते हैं।

3-4 कानून व्यवस्था एवं प्रशासन के अतिरिक्त जनपद के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में नगर पालिकाएँ एवं टाउन एरिया पर्यावरण की स्वच्छता नगरों के अंदर सड़कों निर्माण सड़कों का रखरखाव भवन निर्माण साधारण प्रशासन तथा राजस्व एकत्रीकरण जल सम्पूर्ति, प्रकाश एवं शिकारत की व्यवस्था नियंत्रणों के अधीन कर के जनपद के जिलापरिषद के अतिरिक्त 5 नगरपालिकाएँ, 8 नगर क्षेत्र समितियाँ नोटी फ़ाइड एरिया एवं 2 केन्ट बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

3-5 न्याय वंचायते एवं गाँव सभायें :-

वर्तमान विकास प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विकास नागरिक सुविधा

उपलब्ध कराने, एवं पर्यावरण स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के पहुँचाने में जनपद को गाँव सभाओं में विभक्त किया गया है। छोटे-2 निश्चित प्रकार के कोज-दारी दीवानी संबंधी झगड़ों एवं विवादों को निपटाने हेतु जनपद में 65 न्याय पंचायतें कार्यरत हैं। गाँव सभाओं का कार्य पेयजल हेतु हेण्डपम्प, पेयजल कूप सड़कों पर खड़ंगा की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था एवं सार्वजनिक भ्रमण यंत्रों के रखरखाव है।

3-6 ग्राम स्तर पर एक भूमि प्रबंधक समिति का गठन किया गया है। जिसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान एवं सचिव केबल होता है। इस समिति का मुख्य कार्य जमींदारी उन्मूलन के प्रयात ग्राम समाज के अधिकात्थ में दी गयी जमीन तालाओं एवं पेड़ों एवं जंगलों का प्रबंध करने के साथ-साथ भू-आवंटन करना है।

3-7 ग्राम सभाओं की आय पंचायत कर तालावों का नीताय भवन कर गाँव सभाओं के स्थाई सम्पत्ति से आय एवं सरकारी सहायकता द्वारा होती है।

3-8 सहकारिता:- जिला स्तर पर सहकारी बैंक प्रादेशिक सहकारी संघ झाँसी उपभोक्ता संघ तथा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार कार्यरत हैं। जिला सहकारी बैंक तथा इसकी शाखा से संबंध समितियों के माध्यम से कृषकों को अल्प कालीन मध्य कालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने हिस्से का पूंजी का 10 गुना ऋण नगद एवं वस्तुओं के रूप में भिलाकर प्राप्त कर सकता है। अल्प कालीन ऋण की वसूली को 6 मास बाद है। मध्य कालीन ऋण की वसूली 5 वर्षों में की जाती है।

3-9 प्रादेशिक सहकारी संघ:- प्रादेशिक सहकारी संघ का मुख्य कार्य कृषकों की समितियों के माध्यम से उर्वरक उपलब्ध कराना। गेहूँ और खाद्यान्न का क्रय विक्रय करना तथा ऋण आदि की आपूर्ति करना भी इनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

3-10 उपभोक्ता संघ तथा केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार:- उपभोक्ता संघ तथा उपभोक्ता केन्द्रीय भण्डार उपभोक्ता समितियाँ, सहकारी संघों कृषक सेवा समितियों के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग सामग्री जैसे, कपड़ा चीनी, दिवातलाई, साबुन आदि वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 110 ग्रामीण एवं 141 नगरीय क्षेत्र, नगरपालिका, टाउन एरिया में उपभोक्ताओं को शीघ्र सावग्री एवं अन्य दैनिक उपभोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराता है ।

3-2-2 ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, कृषि उत्पादन निम्न वर्गों के आर्थिक उत्थान विकास कार्यों से संबंधित सशक्त विभागों में सामंजस्य रखने का उत्तरदायित्व अपर जिलाधिकारी ॥ विकास ॥ का होता है ।

00000====00000  
000====000  
00====00  
0====0  
0====0

अध्याय-4

=====

:: आर्थिक कार्यकलाप ::

=====

4-0. आर्थिक कार्यकलाप के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों की जनगणना के अनुसार कार्यकलाप में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न रूप में रही है ।

कुल जनसंख्या	1961	1971	1981
1- कार्यकलाप में लगे हुए व्यक्ति	207250	248124	316431
2- कुल जनसंख्या	714484	370130	1137031
3- कुल जनसंख्या का प्रतिशत	29	29	28

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न जनगणना के साथ कार्यकलापों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

इन कर्मचारों का विभाजन विभिन्न वर्गों में निम्न है:-

वर्ग का नाम	वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार		वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार	
	कुल	कुल कर्मकार का प्रतिशत	कुल	कुल कर्मकार का प्रतिशत
1- कृषक	117494	47.4	153238	48.6
2- कृषक सजदूर	44833	10.1	39437	15.5
3- पशुपालन जंगल लगीना वृक्षारोपण	2078	8.8	--	--
4- खान एवं उद्योग	402	0.2	--	--
5- पारिवारिक उद्योग	11346	4.6	16362	5.3
6- पारिवारिक उद्योग के अतिरिक्त उद्योग	3992	3.6	--	--
7- निजी कार्य	1889	0.8	--	--
8- व्यापार एवं वाणिज्य	13523	5.4	104887	33.1
9- यातायात संग्रहण एवं संचार	16194	6.5	--	--
10- अन्य सेवाएं	31373	12.6	107371	--
योग:-	248124	100.0	316431	100.0



4-1 कर्मकारों का आर्थिक वर्गीकरण:- कुल कर्मकारों को विभिन्न आर्थिक श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार 3 आर्थिक वर्गीकरण किये गये हैं। प्रथम वर्गीकरण में कृषि पशुपालन, वन, मत्स्य, खान एवं खनन सम्मिलित है। द्वितीय के अन्तर्गत विद्युत, गैस, पानी, जलाम्पूरति तीसरे वर्गीकरण में अन्य सम्मिलित हैं। विकास खण्डवार वर्गीकरण निम्न प्रकार है:-

	कर्मकारों की संख्या एवं प्रतिशत						
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	योग			
1- चिरगाँव	18043	90.6	706	3.5	1163	5.9	19912
2- मोठ	22532	89.0	901	3.6	1884	7.4	25317
3- गुरसराय	21455	91.1	1000	4.2	1106	4.7	23561
4- जामौर	21873	90.5	882	3.7	1401	5.8	24156
5- मऊरानीपुर	20350	88.0	1413	6.2	1136	4.9	28899
6- तंगरा	19243	88.0	1439	6.6	1179	5.4	21861
7- बखीना	15831	82.2	858	4.5	2506	13.0	1019
8- बड़ागाँव	17487	80.9	1397	6.5	2710	12.6	2159
समस्त नगरीय	7993	11.9	13631	19.6	48005	68.0	6962
योग:-	164807	66.4	22227	9.0	61090	24.8	24812

उपरोक्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि प्रथम सेक्टर में मोठ गुरसराय, जामौर एवं मऊरानीपुर में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या अधिक है। द्वितीय सेक्टर में विकास खण्ड बड़ागाँव, तंगरा एवं मऊरानीपुर में कार्यरत व्यक्तियों की अधिक है। द्वितीय सेक्टर नगर व क्षेत्र में केन्द्रित होने के कारण कुल नगरीय क्षेत्र के कर्मकार का 19.6 प्रतिशत है। तृतीय सेक्टर अधिकांशतः नगरीय क्षेत्र में है जिनमें नगरीय क्षेत्र के कुल कर्मकार का 8.9 प्रतिशत है। विकास खण्ड के अन्तर्गत बखीना में 13.0 प्रतिशत बड़ागाँव में 12.6 प्रतिशत कर्मकार अन्य सेवा में लगे हुए हैं।

4-5 उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल कर्मकार का 66.4 प्रतिशत कृषि 9.6 उद्योग एवं 24.6 प्रतिशत अन्य सेवाओं में लगे हुए हैं। ज्ञाती एक कृषि प्रधान क्षेत्र होने पर भी कृषि क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसका मापदण्ड निम्न तालिका से स्पष्ट होता है।

:: मुख्य फसलों का औसत उत्पादन वर्ष 1982-84 क्वन्टल प्रति हे०।

फसल का नाम	झांती
1- धान	9.64
2- गेहूँ	16.86
3- जौ	10.83
4- ज्वार	8.24
5- बाजरा	7.87
6- मक्का	12.34
7- उद	2.12
8- मूंग	1.95
9- अरहर	10.04
10- चना	6.68
11- लाही सरसों	5.03
12- मूंगफली	6.48
13- गन्ना	396.46
14- आलू	177.48

4-6 रासायनिक उर्वरक का वितरण:- प्रदेश का उर्वरक उपयोग तथा जनपद झांती में उर्वरक उपयोग बहुत ही कम है। निम्न तालिका में प्रदेश एवं झांती के उर्वरक उपयोग दिया जा रहा है।

प्रदेश	81-82	83-84
--------	-------	-------

कुल घोषा गया क्षेत्र 1000हे०। 342660 337207

2-उर्वरक वितरण 1000मी०टन।

अ। जयपुर	3701	4667
ब। फातफोरत	1950	2805
स। पोटेशिक	342	359
योग:-	5993	7831

4-7 कृषि कार्य हेतु निवेश के रूप में खाद, बीज, एवं कीटनाशक दवाओं के विक्री हेतु जनपद में 112 बीज एवं उर्वरक केन्द्र कार्यरत हैं जिनकी संग्रहण क्षमता 9822 मी०टन फसल सुरक्षा हेतु जनपद में 11 कीटनाशक दवा के भण्डार

1982-83 में 94.7 करोड़ रुपये के निवेश के अन्तर्गत 112 बीज एवं उर्वरक केन्द्रों का निर्माण किया गया है।

है जिनकी कुल क्षमता 640 मीटन है इसके अतिरिक्त एगो कण्डस्ट्रिबल के 8 खाद एवं बीज भण्डार भी वितरण को सुविधा उपलब्ध करते हैं ।

4-8 जनपद में 6 क्रय एवं विक्रय सभितियां है जिनका मुख्य उद्देश्य कृषकों से खाद्यान्न खरीदना, अनाज बंधक रखना एवं उत भाल पर कृषकों को अग्रिम भुगतान करना है। यह सभितियां तार्वजनिक प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता साज्गी का वितरण निर्धारित मूल्य पर करती है। इन सभितियों द्वारा वर्ष 80-81 में 75,55,000 रु० की वस्तु लेन-देन की गयी है । बीज उत्पादन के लिये जनपद में कृषि फार्म है जिनका कुल क्षेत्र 10 हेक्टे० हैं। उन्नतिशील प्रकार के बीजों का उत्पादन वर्ष 80-81 में 1500 मीटन है ।

4-9 ऋण वितरण:- ऋण वितरण कार्य हेतु जिला सहकारी बैंक की 12 हैं। इन शाखाओं में से 5 ग्रामीण एवं 7 नगरीय क्षेत्र हैं। विकास खण्ड चिर-गाँव, नररानीपुर, बड़ागाँव में कोई बैंक शाखा नहीं है। यह बैंक अपने सभितियों के माध्यम से अल्पकालीन एवं मध्य कालीन ऋण का वितरण करती हैं । वर्ष 1982-83 में 56 व्यवसायिक बैंक की शाखायें थीं। विकास खण्ड चिर-गाँव, गुरतराय एवं नररानीपुर के ग्रामीण अंचल में कोई शाखा नहीं है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण क्षेत्र में 3 शाखायें खोल दी हैं ।

दीर्घ कालीन ऋण के वितरण हेतु जनपद में 4 भूमि विकास बैंक की शाखायें हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक द्वारा ऋण वितरण का कार्य किया जाता है ।

:: विभिन्न बैंको द्वारा ऋण वितरण ₹1000रु० ::

वर्ष 1981-82	व्यवसायिक बैंक	सहकारी बैंक	भूमि विकास बैंक	भूमि विकास बोग
1- कृषि कार्य हेतु	22792	27175	7573	57540
2- कृषि संबंधीय	3128	--	--	3128
3- उद्योग:-				
1। ग्रामीण एवं परम्परागत उद्योग	2061	--	--	2061
2। लघु उद्योग	2949	110	--	3059
4- अन्य उद्योग:-				
1। स्वतः रोजगार प्राप्त प्राप्त	21002	26334	--	47336
योग:-	51932	53619	7573	113124

4-10 भण्डारण:- जनपद झांसी कृषि के दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है। कृषक अपने उत्पादित माल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक रूप में संग्रहण करने में अक्षम हैं। उत्पादन होते ही माल को तुरन्त बाजार में लाते हैं। लेकिन विचौतिये द्वारा उन्हें उचित मूल्य नहीं दिया जाता है। सहकारिता विभाग द्वारा 6 क्रय-विक्रय स्थापित कर कृषकों को मोक्ष से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक क्रय समितियों का वर्तमान भण्डारण क्षमता 200 मी०टन है। परन्तु फिर भी अधिक भण्डारण सुविधा का होना आवश्यक है।

4-11 माल की आपूर्ति:- ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सभी समितियाँ उर्जरक चीजें ज़ाद्यन्त, चीनी, सिट्टी का तेल एवं अन्य दैनिक उपयोग के वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति निर्धारित मूल्य पर करती हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समितियाँ यहाँ कार्य कर रही हैं।

00000=-----=00000

000=-----=000

00=-----=00

0=-----=0

0=-----=0

5-0 सेवायोजन सम्बन्धी सुविधायें:-

सेवायोजन का सम्बन्ध श्रम शक्ति के अन्तर्गत आने वाले रोजगार एवं बेरोजगार व्यक्तियों से है। उत्थानतभी सम्भव हो सकता है जबकि श्रम शक्ति के अन्तर्गत आने वाले पुरुष एवं स्त्री आर्थिक रूप से कार्यरत रहें। श्रम शक्ति के अन्तर्गत 15 से 59 वर्ष के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों से है। 15 वर्ष से नीचे और 59 वर्ष से ऊपर जितने कुल: उच्चे सुडे हैं। श्रम शक्ति की परिधि के बाहर हैं। वर्ष 15 से 59 के मध्य आने वाले व्यक्तियों की आश्रित महिलायें विद्यार्थी विकलांग इत्यादि श्रम शक्ति के परिधि के बाहर होते हैं।

5-1 वर्ष 1971 एवं 1981 के जनगणना के आँकड़े श्रम शक्ति से सम्बन्धित अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं। परन्तु प्राप्त सूचनाओं को आधार पर श्रम शक्ति का अनुमान निम्न प्रकार लगाया जाता है:-

वर्ग	1971	1981
1- कुल जनसंख्या	370130	1137031
2- एक वर्ष से 14 वर्ष के आयु के मध्य	568722	740530
3- 14 से 59 वर्ष के आयु के मध्य	299849	390432
अ) आश्रित व्यक्ति	29961	73848
ब) अध्ययन कार्य	25872	32639
स) विकलांग अथवा कार्य में अक्षम	3256	2026
द) अन्य कारण 60 वर्ष से ऊपर	30651	54456
4- कुल कार्य करने वाले वर्ष के अन्तर्गत व्यक्ति	256814	3277
5- कुल कार्यरत व्यक्ति	248124	316481
6- बेकार व्यक्तियों की संख्या	8690	11230

5-2 उपरोक्त तालिका से यह अनुमान लगाया जाता है कि आश्रित महिलाओं की संख्या अधिक है यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में से महिलायें रुढ़िवादिता के कारण आर्थिक कार्य सम्पादन कराना सामाजिक परम्परा के विपरित माना जाता है। निरवल वर्ग की महिलायें केवल आर्थिक उत्पादन का कार्य करती हैं इतना प्रकार जनपद में बेकारों की संख्या है। व्यक्ति

अर्ध रोजगार एवं पूर्ण रोजगार की तलाश में रहते हैं। इन रोजगारियों का मुख्य कारण कृषि में सम्पूर्ण वर्ष कार्य उपलब्ध न होना तथा उद्योगों के दृष्टि को से पिछड़ा होना है।

5-3. सेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय-8 का योगदान मुख्य है। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक स्वतः कार्य योजना के अन्तर्गत इच्छुक व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। सेवायोजना की समस्या एवं निश्चिन्ता को सन्तुष्ट करने के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास योजना एवं स्थान कम्योनेन्ट योजना कार्यरत है।

5-4. ग्रामीण नौजवानों को स्वतः रोजगार स्थापित करने और उसे संभाल रखने हेतु इच्छुक ग्रामवासियों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न रोजगारों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार नेहरू युवक केन्द्र झांसी द्वारा ग्रामवासियों को हस्तकला में प्रशिक्षित किया जाता है।

5-5. सेवायोजन कार्यालय रोजगार तलाश करने वाले अभ्यर्थियों को सहयोग देता है तथा साथ ही व्यवसायिक निर्देशन देने का भी कार्य करता है। व्यवसायिक निर्देशन के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को उनके रुचि के अनुसार प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर से अवगत कराया जाता है।

5-6. सेवायोजन के माध्यम से वर्ष 1980 में 703 एवं 81-82 में 586 अभ्यर्थियों को रोजगार दिलाया गया।

5-7. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय झांसी में कोचिंग क्वेश्चन गार्ड सेन्टर की स्थापना हेतु इस सेन्टर का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को टंकण/आगुलिप्रिक, सेक्रेट्रियल मैकेनिक्स तथा सामान्य ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष में दो सत्र चलाये जाते हैं। सत्र आरम्भ होने की तिथियाँ एक जनवरी एवं जुलाई है। एक सत्र में 30 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष में दो सत्र चलाये जाते हैं। तकनीकी प्रशिक्षण देने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्था की क्षमता 660 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की है। इस संस्था द्वारा निम्न विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है :-

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1- आगुलिप्रिक (हिन्दी) | 2- रेडियो मैकेनिक्स |
| 3- ड्राफ्ट्स मैक       | 4- प्लम्बर          |
| 5- इलेक्ट्रीशियन       | 6- फिटर             |

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 7- पैल्डर       | 8- आशुलिपिक उग्रीजी  |
| 9- इलेक्ट्रोनिक | 10- टर्नर            |
| 11- मशीनस्ट     | 12- स्टूडेंट मैकेनिक |
| 13- वायर मैन    | 14- मोटर मैकेनिक     |

15-0 रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंको से वित्तीय सहायकता एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के ट्राइसेस एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से दिये जा रहे हैं। तकनीकी प्रशिक्षण के कारण लोगों में अपना रोजगार स्थापित करने की प्रगति उत्पन्न हो रही है ।

00000=-----=00000  
 000=--- --=-----=000  
 00=-----=00  
 0=-----=0  
 0=---=0

## अध्याय-6

=====

## 6-0 पिछड़े समुदाय की समस्या:-

=====

वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद प्रदेश एवं देश की पिछड़ी समुदाय की तुलना निम्न तालिका से किया जा सकता है।

00 जनसंख्या हजार में 00

विवरण	सम्पूर्ण जनसंख्या	अनुसूचित जाति प्रतिशत	अनुसूचित जनजाति प्रतिशत
1- भारत	547950	799960 14.6	38015 6.9
2- उत्तर प्रदेश	58341	78549 21.0	199 0.2
3- कुन्देशखण्ड क्षेत्र	4219	1086 25.3	0.3 0.0
4- जनपद झाँसी	870	240 27.6	-- --

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की संख्या भारत में 14-6 प्रतिशत, प्रदेश में 21-0, प्रतिशत ङल में 25-3 प्रतिशत तथा जनपद में 27-6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की संख्या झाँसी जनपद में शून्य है।

जनपद में विकास खण्ड वार एवं नगरीय क्षेत्र में पिछड़े समुदाय की तुलना निम्न तालिका में दिया गया है:-

विकास खण्ड	1971 की जनगणना के अनुसार		
	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति एवं जन जाति	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1- चिरगाँव	68337	20274	30
2- भौंठ	85008	26571	31
3- गुरसराय	79170	27607	35
4- बाजोर	82480	26464	32
5- बरुनीपुर	76246	26759	35
6- बंगरा	72563	24421	34
7- बकीना	58723	13210	22
8- बड़ागाँव	68284	15518	23
योग:-	670138	240001	28



उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विकास खण्ड गुरसराय, मोठ, पासीर, मऊरानीपुर में पिछड़े समुदायों की संख्या अधिक है। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या गुरसराय, मऊरानीपुर तथा सबसे अधिक जनसंख्या मसीना विकास खण्ड में। कुल नगरीय क्षेत्र में पिछड़े समुदाय का प्रतिशत 21 है।

6-1 इन पिछड़े समुदाय की मुख्य समस्या निर्धनता एवं पिछड़ापन है। इन पिछड़े समुदाय को जीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषि एवं अन्य स्थानों पर मजदूरी करना है। जनपद में 34625 परिवारों के पास 9985 हे० भूमि है। जो प्रति परिवार में 0-26 हे० आती है। 20925 हे० भूमि 28370 परिवारों के मध्य आती है। जो प्रति परिवार 0-74 हे० आती है।

6-2 'हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा शैक्षिक योजनाओं पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु पहल की गयी है। इस समय पिछड़े वर्ग के लोगों को विभिन्न छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। शिक्षा केंद्रों के तहत निम्न विभिन्न वर्गों में छात्रवृत्तियाँ दी गयी है।

विवरण	छात्रवृत्तियों की संख्या		
	79-80	80-81	81-82

1- सामान्य शिक्षा के लिये 5612 6806 9477

2- व्यवसाय प्रशिक्षण हेतु 511 594 647

6-3 आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों द्वारा आर्थिक कार्यक्रमों की स्थापना हेतु वित्तीय-सुविधा कम व्याज पर दी जाती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि आवंटन, कृषि, मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण मधुआ मजदूरों की छुटकारा जल सम्पूर्ति की व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम चलाया जाता है। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वर्ष 1982 की योजना आर्थिक दशा सुधारने हेतु निम्नवत

तनायी गयी है :-

क्रमांक	विवरण	अभ्यर्थियों की संख्या	धनराशि
1-	कृषि कार्य हेतु	1716	2277
2-	कृषि-संवर्धन कार्य	662	2583
3-	श्रीजीव एवं कुटीर उद्योग	527	1271
4-	लघु उद्योग	27	718
5-	अन्य कार्य स्वतः रोजगार प्राप्तियों हेतु	569	6019
योग:-		3501	32768

6-4 हरिजन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु 50 प्रतिशत भारजन कमी के रूप में सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बैंकों द्वारा वर्ष 1981 तक निम्न प्रगति पायी गयी :-

क्र०सं०	श्रेणियों का नाम	अभ्यर्थियों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1-	कृषि	221	54570
2-	अन्य सिंचाई	89	402650
3-	पशुपालन	273	17400
4-	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग	953	2732442
5-	व्यापार	15	33500
6-	अन्य	26	64250
योग:-		1577	4595042

6-5 स्वीकृत ग्राम विकास के अन्तर्गत निर्गल वर्ग एवं अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पौनेन्ट प्रोजेक्ट चलायी जा रही है ।

00000-----00000  
 000-----000  
 00-----00  
 0-----0  
 0-----0

:: कृषि विभाग वर्ष 1987-88 हेतु प्रस्तावित चालू योजनायें ::

-: कृषि विभाग :-

कृषि विभाग की वर्ष 86-87 हेतु निम्न योजनाओं को प्रस्तावित किया जा रहा है।

7-1-1 प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन सयंत्र की स्थापना:-

उन्नतिशील प्रमाणित बीजों को उपलब्ध कराने हेतु उनका विधायन आवश्यक ही नहीं अपितु बीज अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणित बीज की उपलब्धता की दिशा में प्रथम प्रक्रिया है। बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं का सम्पादन बीज विधायन सयंत्र मऊरानोपुर में किया जा रहा है। साथ ही प्रगतिशील कृषकों के बीजों के विधायन की भी व्यवस्था है। कृषकों से 10/= प्रति कुन्टल विधायन चार्ज भी लेने का प्राविधान है। इस प्रकार इस योजना से एक ओर कृषकों को उन्नतिशील प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं, साथ ही राज्य को राजस्व की प्राप्ति होने की भी व्यवस्था है।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में 1-35 लाख रु पया व्यय किया गया था वर्ष 1986-87 हेतु 70 हजार रूपये का परिव्यय स्वीकृत है तथा वर्ष 87-88 में इसे चालू रखने के लिए 75 हजार रु पये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

7-1-2 प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों सम्बर्द्धन संग्रहण एवं वितरण:-

कृषि उत्पादन के वांछित लक्ष्य की पूर्ति में शुद्ध एवं उन्नतिशील प्रजातियों के गुणात्मक बीजों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्नतिशील कृषि विज्ञान की मान्यता के अनुसार उन्नतिशील बीजों के प्रयोग से 15-20 प्रतिशत उत्पादन में वृद्धि लायी जा सकती है। यह तभी सम्भव है जबकि क्षेत्रीय अनुकूलता एवं उपयुक्तता के परिपेक्ष्य में स्थानीय प्रक्षेत्रों पर उन्नतिशील बीजों के सम्बर्द्धन एवं संग्रहण की व्यवस्था की जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस जनपद में कुल 3 राजकीय प्रक्षेत्र-लखावटी, घिसौली एवं टाँडा बपरौली कार्यरत हैं। लखावटी स्थित प्रक्षेत्र बहुत पुराना है, घिसौली एवं टाँडा-बपरौली छठी पंचवर्षीय योजना अंश में स्थापित किये गये हैं। नव स्थापित प्रक्षेत्रों में संसाधनों की कमी है इनके सुदृढीकरण के लिये निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

**131-** कृषि प्रक्षेत्र घिसौली पर ट्रेक्टर गेरिज का निर्माण:-  
 इस प्रक्षेत्र में एक ट्रेक्टर गेरिज का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर 40 हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है।  
 प्रक्षेत्र घिसौली में ही उपलब्ध है तथा इसका निर्माण विभाग की मदद से ही किया जायेगा। वर्ष 86-87 में गेरिज का निर्माण प्रस्तावित किया गया था।  
 कृषि प्रक्षेत्र घिसौली पर भूसा/ग्रेन गोदाम का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर 60 हजार रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये विभाग की पाठ भूमि उपलब्ध है तथा निर्माण विभागीय एजेंसी द्वारा कराया जायेगा।

**132-** घिसौली पर नाली निर्माण:-

इस नवसृजित प्रक्षेत्र में सिंचन सुविधाओं के विस्तार के अन्तर्गत 40 मीटर पक्की नाली बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सिंचाई हेतु उपलब्ध जल का भरपूर उपयोग किया जा सके। इसकी अनुमानित लागत 40 हजार रुपये है।

**133-** नवसृजित प्रक्षेत्र टांडा बमरोली हेतु 15 हॉर्सपावर के पावर थ्रसर का

उत्पादित फलाल की समय में मड़ाई एवं औताई के लिये पावर थ्रसर का उपयोग करना परम आवश्यक है जिस पर 10 हजार रुपये व्यय का अनुमान है।

**134-** प्रक्षेत्र टांडा बमरोली ट्रेक्टर गेरिज का निर्माण:-

कृषि प्रक्षेत्र टांडा बमरोली पर एक ट्रेक्टर गेरिज का निर्माण प्रस्तावित है जिस पर 40 हजार रुपये व्यय होने का अनुमान है।

**135-** टांडा बमरोली क्षेत्र में भूसा/ग्रेन गोदाम का निर्माण:-

घिसौली प्रक्षेत्र की भाँति इस प्रक्षेत्र पर ही भूसा एवं अनाज के भण्डारण के लिये 60 हजार रुपये की लागत से मध्यम साइज का गोदाम बनाने का प्रस्ताव है।

सिंचाई सुविधा हेतु 400 मीटर की पक्की नाला बनाने का प्रस्ताव है जिस पर अनुमान: 40 हजार रुपये व्यय सम्भावित है ।

इसी योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड बड़गाँव के ब्रह्मआरागर नामक स्थान पर तथा विकास खण्ड बंगरा के तकरार नामक स्थान पर कृषि बीज अण्डार बनाया जाना प्रस्तावित है जिसको विभागीय मानकों के अनुसार 3-50 लाख की लागत आती है ।

इस प्रकार कुल निर्माण कार्यों पर 6-40 हजार रुपये व्यय किया जायेगा तथा 1-60 हजार रुपये माल सम्पूर्ति एवं प्रक्षेत्रों को मजदूरी पर व्यय करने के लिए प्रस्तावित है। पूरी योजना पर वर्ष 87-88 में 8 लाख रुपये व्यय होंगे।

7-1-3 केन्द्र द्वारा पुरोनिधिमिन्त्रालय के उत्पादन की योजना:-

कृषकों तक संस्तुत कृषि तकनीकी एवं शस्य विधियों को पहुँचाने तथा उनको ग्रहण किये जाने का सरल ठोस एवं प्रभावो प्राध्यम प्रदर्शन" ही है। जिसे कृषकों के खेतों पर आयोजित कर उनकी उपस्थिति में संस्तुत मात्रा में कृषि निवेश, कीटनाशक दवायें, राईजोवियम कल्चर शस्य क्रियायें कराई जाती हैं । आलोच्य वर्ष में 200 प्रदर्शन किये जाने का लक्ष्य है। इसके लिये 50 हजार रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-1-4 प्रदेश के पैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा की योजना :-

कृषि रक्षा कार्यक्रम के तत्काल संचालन एवं कृषि रक्षा, रसायनों के वैज्ञानिक अण्डारण व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रत्येक विकास खण्ड क्षेत्र में कृषि रक्षा रसायन अण्डार गृह का निर्माण आवश्यक है। अब तक विगत खण्ड बलीना के अतिरिक्त कहीं विभागीय अण्डार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 85-86 में विकास खण्ड बड़गाँव के लिये झारसी मुख्यालय पर एक अण्डारगृह स्वीकृत किया गया था जो निर्माणाधीन है। वर्ष 86-87 में विकास खण्ड मोठ में कीटनाशक अण्डार का प्राविधान कराया गया है इस प्रकार तहसील झारसी एवं मोठ में कृषि रक्षा रसायनों के अण्डारण की सुविधा उपलब्ध हो गयी । तहसील प्रऊरानीपुर एवं गरौठा के क्षेत्र में भी सुविधा उपलब्ध कराने जाने के उद्देश्य से वर्ष 87-88 में विकास खण्ड गुरतराय के मुख्यालय पर एक अण्डार गृह बनाये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 1-25 लाख रुपये व्यय होनेका अनुमान है। इसके लिए भूमि उपलब्ध है। कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत रेखाकृति के अनुसार परि-व्यय रखा गया है । निर्माण विभागीय स्वीकृति करेगी ।

इस प्रकार वर्ष 87-88 हेतु कृषि विभाग की 10-50 लाख रूपयों की

-: उद्यान एवं फल संरक्षण :-  
=====

7-2-0 प्रदूषण निवारण एवं प्रौद्योगिकी फलों की स्थानीय उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से औद्योगिकी कार्यक्रमों को तथा उपलब्ध फलों के संरक्षण प्रक्रिया एवं रख रखाव तथा खाद्य विज्ञान की प्रशिक्षण के प्रसार की दृष्टिकोण से जिला योजना 87-88 में सीमित परिव्यय के बावजूद भी उद्यान एवं फल संरक्षण विभाग की योजनाओं हेतु वित्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उद्यान एवं फलोपयोग विभाग के निम्न कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया जा रहा है।

क- उद्यान:-  
=====

7-2-1 वर्तमान उद्यानों, प्रक्षेत्रों/पोधशालाओं के सुधार की योजना:-  
=====

वर्तमान में जनपद झाँसी में राजकीय उद्यान नारायण बाग, झाँसी नगर/तथा राजकीय उद्यान बरुआलागर में स्थित है। झाँसी स्थित राजकीय उद्यान के चारों ओर बाऊन्ड्री बाल नहीं है, जिससे आवारा जानवरों से उद्यान की काफी नुकसान पहुंचता है। इसके चारों ओर चाहरदीवारों होना परभावकर है यह दीवार 2500 मीटर लम्बी होगी। इसका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से कराया जायेगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा इसका 6-34 लाख रुपये का अनुमानित व्यय आगणित किया है। जो विभागाध्यक्ष को भेज दिया गया है। वर्ष 87-88 हेतु कुल 3-00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।

7-2-2 प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन एवं बीज विधायन इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण :-  
=====

यह एक चालू योजना है, जिसके अन्तर्गत 1,80,000 फलदार पौध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना हेतु 1-0 लाख रुपये का परिव्यय 87-88 हेतु प्रस्तावित है।

7-2-3 प्रदेश के प्रमुख एवं पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिकी विकास की योजना  
=====

इस योजना के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य प्रस्तावित है:-

11-	नये उद्यानों का रोपण-	60 हेक्टेयर
12-	आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	55 हेक्टेयर
13-	ससाले के अन्तर्गत क्षेत्रफल-	55 हेक्टेयर
14-	शाकभाजी के अन्तर्गत क्षेत्रफल	35 हेक्टेयर

**7-3-3**

इस योजना हेतु 1-00 लाख रुपयों का परिव्यय प्रस्तावित है। इस प्रकार औद्योगिकी कार्यक्रम हेतु कुल 7-06 लाख रुपयों का परिव्यय प्रस्तावित है।

**7-2-3** फलसंयोजन :-

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में निम्न दो कार्यक्रम चलाये गये हैं :-

7-2-3-1 कल संरक्षण केन्द्र :- कुल 88-18 छात्रों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

7-2-3-2 खादय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र :- कुल 88-18 छात्रों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कल संरक्षण केन्द्रों के अन्तर्गत छात्रों की स्थिति का निरीक्षण किया जा रहा है। कुल 87-88 में 35 हजार छात्रों के संरक्षणों एवं 500 छात्रों को कल संरक्षण विधियों के प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए 25 हजार रुपयों का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-2-4 जनपद मुख्यालय पर स्थित राजकीय खादय विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र उद्यान एवं फलोपयोग विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें निम्न दो कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

7-2-4-1 24 साप्ताहिक बेकरी, कुकरी तथा खादय संरक्षण का प्रशिक्षण।

7-2-4-2 30 द्वितीय पाककला, प्याठी तथा सौम्यलित कोर्स का प्रशिक्षण।

उक्त केन्द्र द्वारा 86-87 में प्रथम कोर्स में 50 तथा द्वितीय कोर्स में 80 प्रशिक्षार्थिनियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्थानीय जनता में इस कार्यक्रम के प्रति लोकप्रियता बढ़ रही है। वर्ष 87-88 में उक्त दोनों कोर्सों हेतु कुल 30-90 छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इन योजना में 2-15 लाख रुपयों का व्यय प्रस्तावित है।

इस प्रकार उद्यान एवं फलसंरक्षण के संयुक्त कार्यक्रम हेतु कुल 6-00 तथा 2-40 कुल 8-40 लाख रुपयों का परिव्यय प्रस्तावित है।

**7-3-0** कृषि विधायन :-

जनपद झारसी की गंडी परबट चिरगाँव एवं भडरानीपुर में निर्माणधीन ग्रामीण गोदामों को पूरा करने के लिये वर्ष 1987-88 में 2-71 लाख रुपयों का परिव्यय राज्यांश प्रस्तावित किया गया है। गत वर्ष उक्त योजना में 1-24 लाख रु.0 स्वीकृत था। यह केन्द्र पुरोनिधातित योजना है।

**7-4-0** भूमि सुधार :-

सीलिंग से प्राप्त भूमि, भूमिहीनों, हरिजन एवं निर्मल वर्ग के लोगों में बाँटी जाती है। ऐसे आबंटियों को कृषि करने हेतु शासन द्वारा तलाश

की जाती है। यह केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है। इसके लिये 50 हजार रु का परिव्यय वर्ष 87-88 हेतु रखा गया है ।

:- निजी लघु सिंचाई:-

7-5-0 अनुदान:-

शासन द्वारा निजी लघु सिंचाई विभाग के कार्यक्रमों का निम्न अनुदान देने का प्रस्ताव है ।

	<u>₹</u> <u>₹</u>
11- साभान्त कृषकों को अनुदान	1500-00
12- ब्लास्टिंग से कम गहरा करने हेतु अनुदान	200-00
13- पठारी क्षेत्रों में ट्यूबवेल निर्माण	600-00
14- निःशुल्क बोरिंग में डी0आर0डी0ए0 के अन्तर का अनुदान।	100-00
	-----
योग:-	2400-00
	-----

7-5-1 बोरिंग गोदामों का निर्माण:- इस योजना के अन्तर्गत जिला गोदाम पर ब्लास्टिंग रिंग इकाई हेतु ट्यूबलर रोड का निर्माण पूर्व में किया जा चुका है इसकी सुरक्षा हेतु आऊन्ड्री बाल के लिये वर्ष 87-88 हेतु 1-00 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है। यद्यपि वर्ष 86-87 में राज्य योजना आयोग से बोरिंग गोदाम मद से कोई परिव्यय नहीं स्वीकृत था तथापि विभाग द्वारा 1-00 लाख रुपये को स्वीकृति प्रदान कर दी थी ।

7-5-2 लघु सीमान्त कृषकों को निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम:-

जनपद के सभी विजास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम तम्मादित कराया जाना है एवं ब्लाक बडीना में इनवेल बोरिंग मशीन द्वारा निःशुल्क बोरिंग कराया जाएगा । इस हेतु 1-00लाख रुपये का प्राविधान रखा गया। अन्वयय मद से ब्लास्टिंग यूनिट एवं रिंग मशीनों पर कार्यरत स्टाफ का वेतन एवं भत्ता पर 3-50 लाख रु परिव्यय रखा गया है। सत्रि एवं उपकरण हेतु 1-00 लाख रु का परिव्यय रखा गया है ।

इस विभाग के लिये वर्ष 83-84 हेतु 29-50 लाख रु का परिव्यय रखा गया है।

:- राजकीय लघु सिंचाई :-

7-6-0 वर्ष 87-88 में स्थल ओवर नलकूपों पर 3 नलकूपों का अनीकरण, 8 कि०मी० पक्की गूल, पी०वी०सी० पाइप लाइन, 180कि०मी० डी०डी०, 2 कि०



हाऊस का निर्माण, 5 एसीयेटेड टैंक्स का निर्माण तथा 3 पंपसेट को लोआरिंग प्रस्तावित है। इस कार्य के लिये 10-50 लाख रु० का प्राविधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 9-50 लाख रु० का प्राविधान नये नलकूप के लिये रखा गया है। धनाभाव के कारण इस कार्यक्रम की आवश्यकता रहते हुये भी इसमें अतिरिक्त धन का प्राविधान नहीं किया जा सका ।

--: भूमि एवं जल संरक्षण:--

7-7-0 जनपद की पठारी संरचना एवं अनियंत्रित जल प्रवाह के कारण यहाँ भूक्षरण एक नियमित समस्या है। वर्ष 85-86 तक जनपद में केवल एक इकाई ही कार्य करती थी। फरवरी 86 से विकास खण्ड बाऔर, गुरतरांव एवं मऊरानीपुर क्षेत्र में डी०पी०ए०पी० स्थापित कर दी गई है। जो मुख्यतः डी०पी०ए०पी० कार्यक्रम से वित्त पोषित होती है। इस कार्ड के द्वारा सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भी भूमि संरक्षण का कारिका जाता है। गत वर्ष 86-87 में जिला योजना वित्त से केवल 16-00 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था, जिसे उप निदेशक भूमि संरक्षण झाँसी ने कृषि निदेशालय के निर्देशानुसार दोनों इकाईयों झाँसी सामान्य इकाई एवं डी०पी०ए०पी० इकाई में से कुल परिव्यय 14-00 लाख एवं 2-00 लाख के क्रमः दोनों इकाईयों में बाँटवा दिया था। इस वर्ष भी उ०नि०भूमि अधिकारियों की सहमति पर 20-00 लाख रूपया झाँसी सामान्य इकाई के लिये तथा 5 लाख रूपया डी०पी०ए०पी० इकाई के लिये रखा गया है। इन इकाईयों को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सेक्टरियल प्लान से भी वित्त उपलब्ध कराया जाता है। जी०एन०-3 में दशांश भौतिक लक्ष्य इकाई की क्षमता के अनुसार समस्त श्रौतों से प्राप्त वित्त से पूरे किये जायेंगे ।

--: पशुपालन :-

7-3-0 वर्ष 1986-87 में पशुपालन विभाग को इस जनपद में चालू कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु 10-81 लाख रु० का परिव्यय रखा गया था। आलोचना वर्ष हेतु 10-50 लाख रु० का परिव्यय निम्न योजनाओं के संवाहन, सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु प्रस्तावित है ।

7-8-1 पशुचिकित्सालय:- पशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत 227-80 ह०रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया जिसका कार्यवार विवरण निम्न प्रकार देखा गया है:-

क्र	विवरण	परिचय ₹000
111-	वर्तमान पशुचिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों हेतु औद्योगिक, साज-सज्जा ।	50-00
121-	पूँछ'डों का क्लान डिस्पेन्सरी हेतु वेतन मंहगाई भत्ता व यात्रा भत्ता ।	22-70
131-	पशु चिकित्सालय तकर तथा सीमा चौकी नौवीं के भवन का निर्माण कुल लागत 7-00 लाख ₹0 में 87-88 हेतु स्वीकृत परिचय	155-10
योग:-		227-80
7-8-2	131 खुरपका, मुंहयका रोग की रोकथाम हेतु प्रस्तावित परिचय	4-00
	132 पशुधन प्रक्षेत्र पर प्रजनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना के अंतर्गत कार्परत प्रक्षेत्र पर सिंचाई कार्य हेतु 2 कि०मी० पक्की गूल के निर्माण हेतु ।	50-00
	133 प्रदेश में कृ०ग०भाधान केन्द्रों के सुदृढीकरण की योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य पूरे किये जाने का लक्ष्य है ।	54-00
14-	केटिल्स का क्रय नग 6	10-00
121-131	आकस्मिक व्यय- 3 गा०सु०ब० पर दर । ₹000 प्रति खंड	3-00
3-131	13 कृ०ग० केन्द्रों हेतु दर-50₹000	6-50
131-	वी०ओ०एल० 3 मोटर साइकिलों एवं जीप हेतु	5-00
141-	18 गा० सं० इकाइयों पर साज-सज्जा फर्नीचर आदि का क्रय दर प्रति इकाई 750/₹0	13-50
151-	8 विदेशी वधियाकरण यन्त्रों का क्रय	16-00
योग:-		54-00
1द1-	अतिदिलीकृत वी०प० द्वारा कृ०ग०कार्यक्रम के सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना चालू केन्द्रों का रख रखाव हेतु ।	186-00
1य1-	नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृढीकरण-	102-00
	1- वेतन-	32-00
	2- मंहगाई	24-00
	3-यात्राभत्ता	02-00
	4- आहार	

6- पक्षियों का रख-रखाव	10-00
7- प्रकीर्ण व्यय	10-00
8- ताज-तज्जा	5-00

कुल:- 102-00

121- संपुक्त राष्ट्र बाल आघात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार की योजना-विकास खण्ड-चिरगाँव 4-00

131- राज्य में बकरी प्रजनन सुविधाओं का विस्तार के अन्तर्गत 22 बकरीयों का क्रय 9-00

141- भेड़ प्रजनन सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य सेवा में-नायक योजना के अन्तर्गत ।

111- भेड़ एवं उन प्रसार केन्द्र बर्बोना हेतु । 370-00

121- 50 भेड़ें खरीदना 15-00

131- भेड़ों को दवाखान 66-00 118-00

118-00

151- प्रदेश में ऊन विश्लेषण श्रेणीकरण तथा विभाजन केन्द्रों का सुदृढीकरण एवं प्रचार की योजना 271-00 के अन्तर्गत निम्न मदों पर व्यय हेतु ।

111-अधिकारी का वेतन 28-00

121-कर्मचारियों का वेतन 118-00

131-कार्यालय व्यय 25-00

141-कार्यालय भवन निर्माण 100-00

योग 271-00

161- सूकर प्रजनन सुविधाओं के प्रसार एवं सुदृढीकरण की योजना- मरेठ, झाली, मऊरानीपुर एवं गुरतराँव में सूकरों का रख रखाव । 8-00

171- प्रशुधन विकास संबंधी प्रसार कार्यक्रम की योजना 4-20

111- दो प्रदर्शनियोजक व्यय 2-20

121- प्रदर्शनी खण्ड पर व्यय 2-00

181- चारा/चारागाह, बीड के विकास की योजना 10-00 चारा बीज क्रय ।

योग:- 1050-00

:- मत्स्य पालन :-  
=====

7-9-77 :- मत्स्य पालन विभाग <sup>की</sup> ~~की~~ मत्स्य विकास अभिकरण के कार्यक्रमों हेतु वर्ष 86-87 में कुल 4-50 लाख रु० का परिव्यय दिया गया था, जिसमें से अभी तक केवल 2-25 लाख रु० को आहरित कर बैंक में जमा मात्र किया गया है, इसका कोई उपभोग नहीं किया गया । विभागीय निर्देशानुसार 2-25 लाख रु० दिसम्बर में आहरित किये जायेंगे । इस विभाग के पास ~~अधुना~~ धान कमी होने के कारण वर्ष 87-88 हेतु केवल 3-60 लाख रु० का ही परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

वन विभाग

=====

7-10-0 :- जनपद झांसी में कुल वन क्षेत्र 32-5 हजार है० है, जो जनपद के सम्पूर्णा क्षेत्रफल का 7% है । 1986-87 में वन विभाग के लिये 24-80 लाख रू० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1987-88 हेतु निम्न चालू योजनाओं हेतु 19-90 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है । इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सामाजिक वानिकी हेतु धान उपलब्धि कराया जायेगा एवं सेक्टरल प्लान से भी इन दोनों मदों के अतिरिक्त धान उपलब्धि होगा ।

7-10-1 :- ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृक्षारोपण :- यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है । योजना का परिव्यय 15-00 लाख रू० प्रस्तावित है जिसमें से 50% राज्यांश 750-00 जिला योजना में रखा गया है । इससे 30 लाख नई पौध तैयार की जायेगी तथा 20 लाख का रख-रखाव होगा । एक लाख रू० राज्यांश पूंजीगत व्यय फेंसिंग एवं ट्री गार्ड्स पर व्यय हेतु रखा गया है ।

7-10-2 :- वन क्षेत्र में आवाबमन के सुलभा बनाने हेतु वन क्षेत्र में 26 हजार रू० की लागत से 2 पुलिया तथा 34 हजार रू० की लागत से दो रपटे नालों पर बनाने का प्रस्ताव है ।

11 वन रेंज मोंठ - एक रपटा

12 वन रेंज चिरगांव - एक रपटा

13 वन क्षेत्र मऊरानीपुर - एक पुलिया

14 ,, बबीना - एक पुलिया

निर्माण कार्य विभाग द्वारा टेण्डर आमंत्रित कर

जायेगा ।

7-10-3 :- वन मनोरंजन/चेतना केन्द्र की स्थापना :- योजना में कृषक सूचना केन्द्र, केण्टीन, चिकित्सालय, मृग बिहार एवं पवन चक्कीका निर्माण किया जा चुका है । 86-87 में बीज भण्डार, मौन पालन केन्द्र व वायोगैस का निर्माण कार्य होके । वर्ष 87-88 में निम्न कार्य प्रस्तावित है ।

॥ 2 ॥		अनुमानित लागत
॥ 1 ॥ शौचालय व स्नानागार - एक		25 हजार रु०
॥ 2 ॥ वानिकी संग्रहालय - एक		60 हजार रु०
॥ 3 ॥ मृग बिहार में श्रेड निर्माण - एक		25 हजार रु०
-----		
कुल 3 भवन		100-00 रु०
-----		

7-10-4 :-

आबादी से दूर स्थित वन क्षेत्र में वन कर्मियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 6 वन रक्षक चौकियों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

ब्लॉक	वन रेंज	निर्माण कार्य स्थल	वन चौकी सं०
1- गुरसरांच	गुरसरांच	मोती कटरा	1
2- बामौर	बामौर इकाई	डूड़ी	1
3- मोँठ	मोँठ	पनारी वीट कोयलारी ग्राम	1
4- मऊरानीपुर	मऊ	रेंज कम्पाउण्ड	1
5- बड़ागांव	झांसी	बनगांवा	1
6- चिरगांव	चिरगांव इकाई	पारौल वीट	1

7-10-5: वन कर्मचारियों को पेयजल सुविधा तथा टांगियां मजदूरों कृषकों को सुविधाएँ :-

॥ अ ॥ जंगलों में रोपणा, सीमांकन तथा पौधालय के कार्यों में लगे श्रमिकों व कर्मचारियों के विश्राम हेतु चिरगांव इकाई के छिरौना पौधालय, तथा मोँठ रेंज के कुम्हड़ार पौधालय क्षेत्र में एक-स्क लेवर हट बनाये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 55 हजार रु० की लागत आयेगी ।

॥ ब ॥ मऊरानीपुर रेंज में रोरा विश्राम गृह में बिजली लगाने हेतु 30 हजार रु० का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

॥ स ॥ झांसी रेंज में चिर रेंज परिसर में कर्मचारियों को पेयजल सुविधा हेतु एक हैण्डपम्प लगाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 15-00 हजार रु० का परिव्यय रखा गया है ।

7-7-6 :- सामाजिक वानिकी :- इस योजना के लिये वर्ष 87-88 के लिये 8 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है । इसके लिये जिला गम्य विकास अभिकरण एवं सेक्टोरियल प्लान से वित्त व्यवस्था प्रथम से की जायेगी ।

पंचायतराज  
=====

7-11-0 :-

जनपद में 602 ग्राम सभायें हैं । यह गांव सभायें अपनी निजी आय एवं सरकारी अनुदान के द्वारा सार्वजनिक हित के कार्य संचालित करती हैं । वर्ष 86-87 हेतु इस विभाग के कार्यक्रमों के लिये 7-46 लाख रु० के कार्यक्रम स्वीकृत किये गये थे । वर्ष 87-88 हेतु 8-50 लाख रु० के निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं ।

7-11-1 :-

प्रबंधकीय सहायता के अन्तर्गत ऐसे पंचायत उद्योग का चयन किया जाता है जिसका वार्षिक उत्पादन 50 हजार से एक लाख रु० के मध्य रहा है । वर्ष 1987-88 हेतु पंचायत उद्योग बामौर का चयन किया गया है जिसे 10 हजार रु० की प्रबंधकीय सहायता का प्राविधान किया गया है । इसके अतिरिक्त 5-5 हजार बबीना तथा मउरानीपुर को द्वितीय किस्त के रूप में देना प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत कुल 20 हजार रु० का प्राविधान किया गया है ।

7-11-2 पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु उन्हें अपनी आय वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन :-

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 6000 रु० का प्राविधान किया गया था । इसके अन्तर्गत जिले की 3 गांव सभाओं को गत 3 वर्षों में सबसे अधिक आय वृद्धि करने हेतु प्रथम पुरस्कार 3000 रु० द्वितीय 2000 रु० तथा तृतीय एक हजार रु० की दर से दिया जाता है । वर्ष 87-88 हेतु 6000 रु० का प्राविधान रखा गया है ।

7-11-3 ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता के लिये अनुदान :-

वर्ष 1986-87

में इस योजना के अन्तर्गत 3-50 लाख रु० का प्राविधान किया गया था । इसमें से 23 गांव सभाओं को 4 कि०मी० खड्जा निर्माण का लक्ष्य है । वर्ष 87-88 के लिये 3-50 लाख रु० का ही प्रस्ताव किया गया है ।

7-11-4 पंचायत भवनों का निर्माण :-

वर्ष 86-87 में 2-50 लाख रु० का प्राविधान रखा गया है । ग्राम सभायें 50% अनुदान देंगी । वर्ष 87-88 में 8 पंचायत भवनों के निर्माण करने हेतु 2-00 लाख रु० का प्राविधान किया गया है ।

7-11-5 :- हाट बाजार तथा फलों की स्थिति में सुधार हेतु गांव

सभाओं को अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 25 ह० रू० स्वीकृत हैं। हाट बाजार के चबूतरों का निर्माण हेतु 59.7 अनुदान दिया जाता है। 87-88 में 4 गांव सभाओं से हाट बाजार हेतु 30 ह० रू० का प्राविधान रखा गया है।

7-11-6 पंचायत उद्योगों की कार्यशाला का भवन निर्माण :- ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या हल करने एवं ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था सुधारने, ग्राम स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल की स्थायी खपत के उद्देश्य से और उपभोक्ताओं को उत्पादित माल सुलभ कराने के दृष्टिकोण से पंचायत उद्योगों की कार्यशालाओं का निर्माण आवश्यक है। इसके लिये 86-87 में 1 लाख रू० का परिव्यय स्वीकृत है जिससे पंचायत उद्योग मऊरानीपुर एवं बड़ागांव में कार्यशाला भवन का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 87-88 में पंचायत उद्योग मोठ एवं बबीना की कार्यशाला भवन का निर्माण हेतु एक लाख रू० का प्राविधान रखा गया है।

7-12-0

प्रादेशिक विकास दल

युवावर्ग कल्याण हेतु विभिन्न चालू कार्यक्रमों हेतु वर्ष 86-87 में 2 लाख रू० की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 87-88 हेतु निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित है।

7-12-1 स्वयं सेवकों का सुदृणीकरण :- अ। वर्दी व्यवस्था :- वर्ष 86-87 में इस कार्यक्रम हेतु 50 हजार रू० का परिव्यय स्वीकृत है जिससे 48 स्वयं सेवकों को 118 वर्दी सेट देने की कार्यवाही की जा रही है। 87-88 में 150 स्वयं सेवकों को 150 वर्दी सेट देकर शान्ति सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया जायेगा। जिसके लिये 200 रू० प्रति वर्दी सेट की दर से 30 हजार रू० का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

ब। प्रशिक्षण :-

उपरोक्त 150 स्वयंसेवकों को 15 दिन का सैनिक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। मार्ग व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक उपकरण की खरीद पर 15 रू० प्रति व्यक्ति के हिसाब से 15 दिनों के लिये 33,750 ह० रू० का प्राविधान प्रस्तावित है।





7-12-3 युवक मंगल दलों का सेमीनार :- इस मद में 6 हज़ार ₹ का प्राविधान 87-88 हेतु प्रस्तावित है ।

क्र.सं.	विवरण	संख्या	दर	कुल धनराशि
11	ब्लॉक स्तरीय सेमीनार	8	750 ₹ प्रति ब्लॉक प्रति सेमीनार	6,000
12	जिला स्तरीय सेमीनार	कुल एक	5000 ₹ प्रति सेमीनार	4,000
कुल व्यय				10,000

7-12-4 समाज सेवी कार्य, मेला, प्रदर्शनी, तीर्थयात्रा आदि :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवकों की ड्यूटी मेला तथा उत्सवों के अवसर पर लगाई जाती है जिसके लिये उन्हें ड्यूटी भत्ता देना प्रस्तावित है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन सफाई अभियान कार्यक्रम देवी आण्डाओं में समाज सेवा कार्य इनसे लिखा जाता है । इसलिये 8 विकास खण्डों हेतु 4 हज़ार ₹ का प्राविधान है ।

7-12-5 प्रकीर्ण व्यय :- प्रकीर्ण व्यय में 12 हज़ार ₹ का प्राविधान किया गया है ।

7-12-6 खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन :- विकास खण्ड/जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिये कुल 13 हज़ार ₹ का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7-12-7 ग्रासीणा क्षेत्रों में व्यायाम शाला को प्रोत्साहन :- वर्ष 87-88 हेतु विभागीय मापदण्डों के अनुसार एक लाख ₹ का परिव्यय प्रस्तावित है । साज सज्जा एवं उपकरण हेतु 25 हज़ार ₹ का परिव्यय एन०आर० ई०पी० से प्राप्त करने के निर्देश है ।

7-12-8 श्रमदान/प्रशिक्षण शिविर :- इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 87-88 के लिये 25 हज़ार ₹ का प्राविधान प्रस्तावित है ।

7-12-9 युवकों का तैराकी प्रशिक्षण :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय मानकों के अनुसार 10 हज़ार ₹ का परिव्यय प्रस्तावित है ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल परिव्यय 343-95 हज़ार ₹ प्रस्तावित है ।

ग्राम्य विकास विभाग सांख्यिक विकास  
ब्लॉक भवन

7-13-0 :- इस जनपद के 8 विकास खण्डों में से 3 विकास खण्ड क्रमशः बड़ागांव, बंगरा एवं वागौर ऐसे विकास खण्ड हैं जिसमें कार्यालय भवन तो है परन्तु खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य विकास कार्यकर्ताओं के रहने हेतु आवासों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह तीनों विकास खण्ड ग्रामी क्षेत्रों में स्थित हैं। गत वर्ष भी इनकी योजना प्रस्तुत की गई थी परन्तु शासन स्तर से इनकी स्वीकृति नहीं मिली। प्रति विकास खण्ड निम्न आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

आवास का प्रकार विकास खण्ड जहां निर्माण प्रस्तावित है।

	बड़ागांव	बंगरा	वागौर
1- ती०डी०ओ० टाइप	1	1	1
2- ए०डी०ओ० टाइप	8	8	8
3- मिनिस्ट्रियल टाइप	7	7	7
4- चतुर्थ श्रेणी टाइप	3	3	3

उपरोक्त 57 क्वार्टर के निर्माण हेतु भूमि विभाग के पास उपलब्ध है। भवनों का आकलन ग्रामीण अभिवर्धन विभाग से बनवा लिया गया है। रेखाकृति अनायुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास द्वारा स्वीकृत है। इन 57 क्वार्टरों की कुल लागत 36-53 लाख ₹00 आंकी गई है। वर्ष 87-88 हेतु कुल लागत का 40% के लगभग परिव्यय 15 लाख ₹00 स्वीकृत किया गया है।

क्षेत्रीय विकास  
=====

7-14-0 :- स्वीकृत ग्राम्य विकास :- वर्ष 1986-87 में इस कार्यक्रम हेतु 48-00 लाख ₹00 का परिव्यय शासन स्तर से राज्यांश स्वीकृत हुआ था। अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अभिकरण से 55-16 लाख ₹00 व्यय करने के अनुमान प्रस्तुत किये हैं। इसमें से 8-60 लाख ₹00 कार्यालय भवन निर्माण पर व्यय हुए हैं।

वर्ष 87-88 हेतु शासकीय मानकों के अनुसार 6 लाख ₹00 प्रति ब्लॉक की दर से भी 48 लाख ₹00 राज्यांश का परिव्यय रखा गया

१-० लाखों रु० अभिकरणों द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर स्टेर भवन/कार्यालय कक्षा एवं जिला कार्यालय भवन की पूर्ति में व्यय किया जाना प्रस्तावित है। भौतिक लक्ष्य जी०एन०-३ में दर्शाये गये हैं।

7-15-0 :- सूखोन्मुखा कार्यक्रम :- इस जनपद के 3 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिये 15 लाख रु० प्रति ब्लॉक की दर से 50% राज्यांश 22-50 लाख रु० रखा गया है। सेक्टरियल आवंटन विभागीय निर्देशानुसार रखे जायेंगे।

7-16-0 :- लघु सीमांत कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु आर्थिक सहायता :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 150 निःशुल्क बोरिंग, 12 चेकडेम, 3 तालाब निर्माण एवं 225 व्यक्तियों को अनुदान से लाभान्वित करने, 15000 मिनीकित बांटने तथा 600 है० क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 20 लाख रु० का लक्ष्य रखा गया है।

7-16-1 :- राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम :- वर्ष 86-87 में कुल 117-63 लाख रु० का प्राविधान शासन द्वारा सूचित किया गया था जिससे राज्यांश 58-81 लाख रु० था। इससे 4-86 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

वर्ष 87-88 में कुल 120-00 लाख रु० का परिव्यय प्राप्त होने की योजना है। जिससे 5-21 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

7-17-0 :- सहकारिता :- जनपद की अर्थ व्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र का विशेष महत्त्व है। निर्बल वर्ग को महाजनी ऋण से मुक्त करने, कृषकों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त अब सहकारिता क्षेत्र को उपभोक्ताओं तक उपभोक्ता सामग्री पहुंचाने का दायित्व भी सौंपा गया है। गत वर्ष सहकारिता विभागको जिला सेक्टर योजना से 404 हजार रु० रखा गया था।

वर्ष 87-88 की जिला योजना से सहकारिता विभाग हेतु

5-70 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-17-1 :- सहकारी ऋण एवं अधिऋण योजना :-

अ३ जिला सहकारी बैंक शाखाओं हेतु प्रबंधकीय अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक की शाखाओं को 8 हजार रु० प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष तक प्रबंधकीय अनुदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

जिसके अन्तर्गत ठहरौली स्थित शाखा को वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में दो किस्तें 16 हजार रु0 दिया जा चुका है । वर्ष 87-88 हेतु अन्तिम किस्त हेतु 8 हजार रु0 का प्राविधान है । गरौठा एवं मऊरानीपुर शाखाओं को वर्ष 86-87 में प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी जायेगी । वर्ष 87-88 में इन दोनों शाखाओं को द्वितीय किस्त उपलब्ध कराने हेतु 16 हजार रु0 का प्रस्ताव है । मानिक चौक अंगझांसी स्थित शाखाओं 87-88 में प्रथम किस्त दी जायेगी । इस प्रकार इस योजना हेतु 30 हजार रु0 का प्राविधान रखा गया है ।

ब। जिला सहकारी बैंक शाखाओं का बचीनीकरण :- इस योजना के अन्तर्गत 50 हजार रु0 प्रति शाखा की दर से एक बार सहायता दी जाती है । वर्ष 87-88 में यह अनुदान सहायता मानिक चौक अंगझांसी में नव प्रस्तावित शाखा, जिसकी स्थापना हेतु स्वीकृति नितेशक महोदय से प्राप्त हो चुकी है, के साज सज्जा हेतु 5 हजार रु0 उपलब्ध कराया जायेगा ।

स। निर्मल वर्ग अनु0 जाति/जनजाति के लोगों को अंग क्रय हेतु मध्य कालीन ऋण/अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत निर्मल वर्ग

अनु0जाति/जनजाति के 500 सदस्यों को समितियों के सदस्य बनाने हेतु अंग क्रय करने के लिये 100 रु0 प्रति की दर से 50 हजार रु0 का प्राविधान वर्ष 87-88 हेतु कराया गया है ।

7-17-2 :- कृषि विक्रय योजना :-

अ। प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमांत धान :-

वर्ष 86-87 में 11 समितियों को 15 हजार रु0 प्रति समिति की दर से कुल 165 हजार रु0 उपलब्ध कराया गया । वर्ष 87-88 में निम्न 20 समितियों को उर्वरक व्यवसाय हेतु 15 हजार रु0 प्रति समिति की दर से सीमांत धान देना प्रस्तावित है ।

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1- हसारी साधान   | 11- गोंठ कृषाक      |
| 2- चुरारा साधान  | 12- पूछ , ,         |
| 3- कुआगांव साधान | 13- रेवन , ,        |
| 4- बालौड साधान   | 14- मऊरानीपुर कृषाक |
| 5- टोड़ी फतेहपुर | 15- मठपुरा , ,      |
| 6- खेड़ैनी       | 16- रानीपुर , ,     |
| 7- स्किल         | 17- उल्दन क्षोत्रीय |
| 8- सेमरी कृषाक   | 18- बडगांव          |



12। स्कीकृत मार्जिन मनी ऋण योजना :- यह योजना वर्ष 85-86 से लागू की गई। पिछले वर्ष इस मद हेतु कोई धनराशि नहीं दी गयी थी।

अभी तक इस योजना में 20 आवेदन पत्र लगभग 16 लाख रु० के लम्बे पड़े हुए हैं। वर्ष 87-88 हेतु 5 लाख रु० की मांग प्रस्तावित की गई है।

7-17-3 3- मेले प्रदर्शनी :- वर्ष 86-87 में इस मद हेतु 25 हजार रु० का बजट रखा गया जो मुक्त हो गया है। वर्ष 87-88 हेतु 25 हजार रु० का प्राविधान किया गया है।

7-17-4 :- उद्योगता विकास कार्यक्रम :- इस योजना के अन्तर्गत भक्षुवी इच्छुक उद्योगपतियों को उनके उद्योगों के चुनाव, उद्योगों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने तथा विभिन्न संस्थाओं एवं संबंधित विभागों के संबंध में जानकारी दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

7-17-5 राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र :- जनपद झंसी में इस केन्द्र की स्थापना 6वीं योजनावधि में हुई थी।

वर्तमानस्थिति :-

1अ। केन्द्र में वर्कशाप, पात्रकार- उद्योगी हेतु शेड एवं प्रशासकीय भवन इत्यादि के साथ कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण का कार्य चलाया जा रहा है। जिसमें लगभग 100 प्रशिक्षार्थी अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

1ब। केन्द्र पर स्थापित 10 1दस। पात्रकार वर्कशेड सा०नि०वि० से हस्तगत कर लिया गया है एवं पांच पात्रकारों को शेडों का आवंटन कर दिया गया है जिसके लिये उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बैंकों से ऋण प्रदान करना स्वीकृत कर लिया है। केन्द्र में प्रथमवार 15 अगस्त 1986 से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। कच्चा माल बुन्देलखण्ड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

वर्ष 1987-88 के लक्ष्य :-

अवस्थापना व्यय :-

1- वेतन	62,500=00
2- मंडलाई भत्ता	55,000=00
3- यात्रा भत्ता	10,000=00
4- अन्य भत्ते	5,000=00
5- कार्यालय व्यय	40,000=00
6- मशीनों का रखरखाव, भट्टी निर्माण लोडिंग शेड	2,38,000=00

7- विज्ञापन	1 500=00
8- वाणिज्यिक प्रक्रिया	2, 50, 000=00
॥ कच्चा माल ॥	-----
	6, 62, 000=00
	-----

॥ 1 ॥ वाणिज्यिक प्रक्रिया के अन्तर्गत 20 फुटी नयी भट्टी निर्माण का लक्ष्य है जिससे पाटरो की उत्पादन लागत कम होगी एवं विकास की दर एवं लाभ में बढ़ोत्तरी की सम्भावना है । इस पर 1-80 लाख रु० व्यय का अनुमान है ।

॥ 2 ॥ केन्द्र में कोयले की सुरक्षा हेतु कोल बंकर की कमी है, जिसे बनाना नितांत आवश्येक है । इस पर 50 हजार रु० व्यय का अनुमान है ।

॥ 3 ॥ भट्टी पर लोडिंग ग्रेड बनावाने हेतु 8 हजार रु० का प्रस्ताव रखा गया है ताकि सैगर तथा लोज किया हुआ माल वर्षा के दिनों में सुरक्षित लोडिंग एवं फायरिंग का कार्य किया जा सके ।

॥ 4 ॥ चीनी भट्टी के वर्तन बनाने हेतु चरबना क्लेक तथा अन्य प्रकार के फायर केमीकल्स, क्रय हेतु 50 हजार रु० का प्राविधान रखा गया है ।

॥ 5 ॥ विद्युत् मद के लिये 15-00 हजार रु० प्राविधानित है ।

॥ 6 ॥ केन्द्र पर स्थित 12 फुटी डी०डी० क्लिन की फायरिंग पूरे वर्ष में लगभग 200 मी०टन० स्टीम कोल ग्रेड उ॥वी॥ की आवश्यकता होगी । जिस पर 1-77 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है ।

हथकरघा :- वर्ष 86-87 में इस विभाग के लिये 2-75-20 हजार रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । वर्ष 87-88 हेतु 271-60 रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-20-0 सडक एवं पुल :- जन्मद झांसी को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 36-40 लाख रु० का परिव्यय रखा गया था, जिससे 15 कि०मी० लेपन, 5 कि०मी० भट्टी का कार्य, 14 पुलियां तथा 7-00 कि०मी० सोलिंग स्तर तक के कार्य किये जाने का लक्ष्य है ।

वर्ष 87-88 में 21 कि०मी० लेपन स्तर तक का कार्य, 6 कि०मी० मध्य स्तर तक का कार्य तथा लघु सेतु बनाने का प्रस्ताव है । यह समस्त कार्य चालू कार्य है, जिनको इस वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है ।



इसके लिये 33-67 लाख रू० निर्माण लागत तथा 5-30 लाख रू० सेन्टेज चार्जेज कुल 38-97 लाख रू० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

7-21-0 पर्यटन :- इस वर्ष "स्थानीय पर्यटन विकास" कार्यक्रम के अधीन निम्न कार्यक्रमों के लिये परिव्यय रखा गया था ।

1अ॥ लक्ष्मीताल का विकास झांसी - प्रदूषण का रोकना :- वर्ष 86-87 में इस कार्यक्रम हेतु 2-50 लाख रू० दिया गया था । वर्ष 87-88 में 6-0 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है । प्रदूषण कार्य के अनुमान तैयार कराकर पर्यटन विभाग को भेजे दिये गये हैं ।

1व॥ मण्डी समिति झांसी से महाराजा गंगाधर राव की छतरी तक सड़क का निर्माण :- वर्ष 86-87 में 2-30 लाख रू० का परिव्यय रखा गया था जिससे यह कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।

1स॥ झांसी मण्डी समिति से नारायणा वाग तक के मार्ग का विद्युतीकरण

यह मार्ग मण्डी समिति के निकट स्थित बस स्टैण्ड से झांसी के आकर्षक पर्यटन स्थल नारायणा वाग, खाकी शाह के मजार की ओर जाती है । झांसी पर्यटन गृह में ठहरने वाले पर्यटकों के लिये मुख्य आकर्षण का केन्द्र है । यह सड़क नगरपालिका क्षेत्र से वाह्य सीमा पर स्थित है तथा सैलानियों का प्रमुखा आकर्षण केन्द्र है । नगरपालिका झांसी इसका विद्युतीकरण करने की स्थिति में नहीं है । इस संदर्भ में संबंधित विभाग ने नगरपालिका झांसी से वार्ता कर ली है । पर्यटन गृह झांसी में ठहरने वाले सैलानियों को आकर्षण प्रदान करने के दृष्टिकोण से यह योजना पर्यटन विभाग में अपने हाथ ले ली है । तथा इसके विद्युतीकरण के लिये 87-88 की योजना में 4-00 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है ।

7-22-0 सामान्य शिक्षा :-

1।॥ वेसिक शिक्षा :- जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 87-88 के लिये 19-105 लाख रू० का प्रस्ताव किया गया है । जिनके अन्तर्गत निम्न योजनाओं रखी गयी हैं ।

ग्रासीणा तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित जू० वेसिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु अनुदान :- सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में 3 भवन्हीन प्राइमरी विद्यालयों को बनाने हेतु शासन द्वारा 258-4 हजार रू० रखा गया था जो निर्माण एजेन्सी को दे दिया गया है ।

वर्ष 87-88 में 3 विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 258-4 हजार रु० का परिस्य विभागीय मानकों के अनुकूल प्रस्तावित किया जा रहा है ।

7-22-2 असाधारण समान्यता प्राप्त आशासकीय सी०वे० स्कूलों को अनुरक्षण  
अनुदान :- सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से अत तक कोई भी विद्यालय अनुदान सूची पर नहीं लिया गया है । पूर्व में आये 2 विद्यालयों को वचनबद्ध व्यय की धनराशि की मांग 2 लाख रु० की मांग की जा रही है ।

7-22-3 ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी०वे० स्कूलों के भवन निर्माण हेतु  
अनुदान :- वर्ष 1986-87 में इस योजना के अन्तर्गत एक विद्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी । वर्ष 87-88 हेतु भी एक विद्यालय भवन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

7-22-4 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जू० वे० विद्यालय खोलने हेतु अनुदान :-

वित्तीय अल्पता के कारण वर्ष 87-88 में नये विद्यालय खोलने के प्रस्ताव नहीं स्वीकृत किये जा रहे हैं, केवल 85-86 में खोले गये 2 विद्यालयों के वचनबद्ध व्यय को पूरा करने हेतु 42-0 हजार रु० की मांग की जा रही है ।

7-22-5 जू० वे० स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान साज सज्जा हेतु अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई । वर्ष 1986-87 में 17 विद्यालयों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 10 हजार रु० अनुमोदित किया गया था । इस वर्ष 87-88 हेतु भी 17 विद्यालयों को अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 हजार रु० की मांग प्रस्तावित है ।

7-22-6 ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्बल वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को पाठ्य पुस्तके वितरणार्थ हेतु  
प्रोत्साहन अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 10 हजार रु० की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिससे 100 छात्रों को पाठ्य पुस्तके निःशुल्क दी जा चुकी हैं । वर्ष 1986-87 में भी 100 छात्रों को लाभांशित करने हेतु व्यय अनुमोदित है । वर्ष 87-88 में भी 100 छात्रों को लाभांशित करने के आशय से 10 हजार रु० की धनराशि प्रस्तावित है ।

7-22-7 नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अंशकालिक कक्षाएँ खोलने के लिये अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत दही पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले गये केन्द्रों पर व्यय हेतु 7-16 लाख रु० की धनराशि की मांग की जा रही है ।

7-22-8 ग्रामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के सी०वे० स्कूल खोलने हेतु अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में खोले गये विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु वचनबद्ध धनराशि को शामिल करते हुए एक नया विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव रखा गया है । इस प्रकार कुल 379-1 हजार रु० का प्रस्ताव किया गया है ।

7-22-9 प्रत्येक जिले में जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुदृणीकरण :- इस मद में गत वर्ष 16 हजार रु० मांगा गया था । इस वर्ष भी उतनी ही धनराशि का प्रस्ताव है ।

7-22-10 प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6से 8 तक 15/- रु० प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति :- इस योजनाके अन्तर्गत वर्ष 86-87 में 220 छात्रों के लिये परिव्यय शासन स्तर पर से स्वीकृत किया गया था । वर्ष 87-88 हेतु भी 220 छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है ।

7-22-11 वेसिक स्कूलों के अध्यापकों को पु दक्षता पुरस्कार :- सातवीं पंच-वर्षीय योजनाके आधार वर्ष में 8 अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार स्वीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गयी । वर्ष 1986-87 में 8 अध्यापकों को पुरस्कृत करने हेतु धन सी० स्वीकृत हैं । वर्ष 87-88 में 10 अध्यापकों को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से 5 हजार रु० का प्रस्ताव किया गया है ।

7-22-12 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने तथा सी०वे० स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान :- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986-87 में 8 सी० वे० स्कूलों में एक बैंक खोलने हेतु स्वीकृति मिल चुकी है । वर्ष 87-88 में 3 सी० वे० स्कूलों में एक बैंक स्थापित करने हेतु 10 हजार रु० के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं ।

7-22-13 ग्रामीण क्षेत्रों में सी० वे० स्कूलों के लिये साज सज्जा हेतु अनुदान :- वर्ष 85-86 में 15 सी० वे० स्कूलों में साज सज्जा की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है । वर्ष 86-87 में भी 15 स्कूलों को साज सज्जा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । वर्ष 87-88 में 15 अन्य स्कूलों में साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 45 हजार रु० की मांग प्रस्तावित है ।

7-22-14 जूनियर वेसिक स्कूलों में शिक्षा सामग्री हेतु अनुदान :-

वर्ष 86-87 में 15 विद्यालयों में शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 87-88 में 15 अतिरिक्त विद्यालयों के शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 हजार रु० का परिव्यय प्रस्तावित है।

7-22-15 निर्मल वर्ग के भवच्चों को पोशाक देने की व्यवस्था :- वर्ष 85-86

में इस योजना के हेतु शासन स्तर से स्वीकृति न मिलने के कारण 87-88 में इस मद में कोई पैसा नहीं गांगा जा रहा है।

7-22-16 ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सीनियर वेसिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान :- इस योजना

के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 3 विद्यालयों को विज्ञान किट प्रदान करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। वर्ष 86-87 में 3 विद्यालयों को विज्ञान सज्जा हेतु विज्ञान किट प्रदान करने का प्राविधान है। वर्ष 1987-88 में भी 3 विद्यालयों को विज्ञान किट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 हजार रु० की राशि प्रस्तावित है।

7-22-17 अरेविक मदरसे को अनुरक्षण अनुदान :- वर्ष 1985-86 में

किसी भी अरेविक मदरसे को अनुरक्षण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 1986-87 में एक विद्यालय को अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है। 1987-88 में इस मद के अन्तर्गत 2 हजार रु० की व्यवस्था प्रस्तावित है।

7-22-18 माध्यमिक शिक्षा :- माध्यमिक शिक्षा की निम्न योजनाओं

हेतु परिव्यय वर्ष 87-88 हेतु स्वीकृत कर दिया गया है।

1. खेलकूद तथा योजना

परिव्यय ६० रु०।

११। खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के वार शैक्षिक कार्यक्रमों तथा पुस्तकों के कल्याण हेतु प्राविधान 17-00

१२। 30 मा० विद्यालय में बालचर योजना का प्रसार 2-00

१३। वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना 150-00

१४। सार्वजनिक पुस्तकालयों को विकास अनुदान 5-00

१५। संस्कृत पाठशाला विकास अनुदान 6-00

१६। २२० उ० वि० के भवनों का निर्माण एवं विद्युतीकरण तथा विशेष मरम्मत 8-00

इसमें क्रमांक 3 पर वर्णित प्रस्तकालय भवन शिक्षा विभाग के परिसर में निर्माणाधीन है जिसे पूरा करने के लिये एक लाख रु० का परिव्यय रखा गया है । 50 हजार रु० राजस्व व्यय है ।

7-23-0 खेलकूद :- खेलकूद विभाग के चालू कार्यक्रमों के लिये वर्ष 86-87 में 3-32 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत हुआ था जिसमें से 2-18 लाख रु० तरणाताल के निर्माण के लिये सार्नि०वि० को दे दिये गये हैं ।

वर्ष 87-88 में तरणाताल के कार्य को पूरा कराने के आशय से 10-00 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है । अब तक स्थानीय सार्नि० निर्माण विभाग को 12-18 लाख रु० प्रमुखा अभियंता के मध्यम से प्राप्त हो चुके हैं ।

शेष योजनायें चालू कार्यक्रमों की आपूर्ति हेतु परिव्यय रखा गया है । इस विभाग को 87-88 हेतु कुल 11-424 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

7-24-0 प्राविधिक शिक्षा :- वर्ष 86-87 में इस विभाग को 2-30 लाख रु० का परिव्यय चालू कार्यक्रमों के संचालन हेतु स्वीकृत किया गया था । वर्ष 1987-88 हेतु निम्न कार्यक्रमों के लिये 9-88 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

11 डाईवसी फाइड पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ करना :-

इस विभाग का यह चालू कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत छठी योजनावधि में 2-54 लाख रु० व्यय किया गया । 85-86 में इस विभाग के लिये जिला स्तर में तो वित्तीय प्राविधान स्वीकृत किया गया था, परन्तु शासन स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत न हो सकी । वर्ष 86-87 में पुनः 1-50 लाख रु० का प्राविधान किया गया है तथा इतना ही धान 87-88 के लिये प्रस्तावित है ।

12 साज सज्जा का आधुनिकीकरण :- 39 प्र० शासन द्वारा डिप्लोमा अभियंत्रण कोर्स के आधुनिकीकरण किये जाने के फलस्वरूप प्रयोग-शालाओं/वर्कशापों में आधुनिक उपकरण एवं यन्त्रों उपलब्ध कराने के अभिप्राय से इस कार्यक्रम हेतु 1-50 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है ।

131 पालीटेकनिक के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में स्थानीय पालीटेकनिक में चल रहे इलेक्ट्रानिक एक आटोमोबाइल कार्यक्रमों केलिये प्रथम भवन उपलब्ध न होने से शिक्षाण कार्य में काफी बाधा पडती है । यह मांग विगत वर्ष भी प्रस्तुत की गयी थी । इस वर्ष एक ट्रेड इलेक्ट्रानिकस हेतु 2 150 वर्गमीटर कारपेट एरिया के कमरे, 120 वर्गमीटर कारपेट एरिया के 2 क्लास रूम, 30 वर्गमीटर का स्टाफ रूम तथा 120 कारपेट एरिया का एक ड्राइंग हाल निर्माण हेतु किया जाना प्रस्तावित है । निर्माण हेतु प्रस्तावित कुल कारपेट एरिया 870 वर्गमीटर है । प्लिथ एरिया 1218 वर्गमीटर है जिसकी लागत 1250/- रु० प्रति वर्गमीटर की दर से 15-23 रु० आंकलित किया गया है । इसका 40% के लाभ का परिव्यय 6-10 लाख रु० 87-88 हेतु रखा गया है । भूमि विभाग के पास उपलब्ध है ।

131 पुस्तकालय का सुदृणीकरण :- गत वर्ष इस गद में 20 हजार रु० परिव्यय की स्वीकृत किया गया था । इसमें वर्ष 87-88 हेतु एफपीएसओ सिस्टम की किताबों के स्थानपर एमओएसओ सिस्टम की किताबों खरीदने के लिये 62-5 हजार रु० का परिव्यय रखा गया है ।

141 विद्यार्थियों को सुविधा :- संस्था में ठंडे पानी पीने के लिये कोई सुविधा इस समय नहीं है । विद्यार्थी सदैव इसकी मांग करते हैं । अतएव 87-88 में दो बाटर कूलर क्रय करने हेतु 16 हजार रु० का प्राविधान किया गया है ।

7-25-0 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य :- जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य की मुख्य चिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के अधीन कार्यरत एवं नवीन परियोजनाओं के लिये वर्ष 87-88 हेतु निम्न परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है ।

प्रस्तावित परिव्यय	चालू योजना हेतु परिव्यय हजार रु०	नई योजना हेतु परिव्यय हजार रु०
111 मुख्य चिकित्साधिकारी अधीन	4300-00	590-00
121 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी	823-00	120-00
योग	5123-00	710-00
या	कुल योग	5713-00

योजनावार विवरण एवं औचित्य

चालू योजना। मुख्य चिकित्साधिकारी।

7-25-1 PTO स्वा० केन्द्रों का भवन निर्माण :- वर्ष ७७-७८ में जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत केवल २ PTO स्वा० केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु धन मांगा जा रहा है। PTO स्वा० केन्द्र गुरसरांग जो कि वर्ष ७५-७६ में स्वीकृत हुई थी के लिये वर्ष ७७-७८ में ६-०० लाख रु० मांगा गया है। और आशा है कि वर्ष ७७-७८ में यह भवन बनकर पूर्ण हो जायेगा। अतः और धन की आवश्यकता नहीं होगी।

PTO स्वा० केन्द्र बड़ागांव में वर्ष ७५-७६ में भूमि विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वर्ष ७५-७६ एवं ७६-७७ में शासन द्वारा धन का आवंटन नहीं किया गया था। अब बड़ागांव में भूमि उपलब्ध हो गयी है तथा भूमि को विभाग ने हस्तगत कर लिया है। शासन के आदेशों के अनुसार एक PTO स्वा० केन्द्र पर लगभग १२-१३ लाख रु० व्यय होता है तथा ३ वर्षों में भवन पूर्ण हो पाता है। चूंकि प्रथम वर्ष में स्वीकृति का कुछ विलम्ब से प्राप्त होती है। अतः वर्ष ७७-७८ में बड़ागांव के लिये केवल २-०० लाख रु० इस आशय से मांगा जा रहा है कि वह उसी वित्तीय वर्ष में व्यय हो जायेगा।

7-25-2 उपकेन्द्रों का भवन निर्माण :- वर्ष ७७-७८ में १३ उपकेन्द्रों को भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। शासन के आदेशों के आधार पर एक लगभग एक लाख रु० की लागत आती है। इन १३ उपकेन्द्रों में पिछले वर्षों में प्रस्तावित कोई उपकेन्द्र सम्मिलित नहीं है और न ही पिछले वर्षों में प्रस्तावित उपकेन्द्रों के पूर्ण होने करने हेतु वर्ष ७७-७८ में धन का प्रस्ताव किया गया है।

प्रस्तावित उप केन्द्रों के नाम :- १। चमरगा, २। बलीना, ३। इमलिया, ४। बलीना, ५। छपरा, ६। कोछभांवर, ७। जरदो, ८। कोछभांवर, ९। चेलरा, १०। चिरगांव, ११। बरल, १२। चिरगांव, १३। बड़ौरा, १४। चिरगांव, १५। कुम्हार, १६। मोठ, १७। सिमिरिया, १८। मोठ, १९। बड़ोखरी, २०। मोठ, २१। रजपुरा, २२। बंगरा, २३। पड़रा, २४। बंगरा, २५। ककवारा, २६। मऊरानीपुर, २७। सियावली, २८। मऊरानीपुर, २९। ठकरवारा, ३०। मऊरानीपुर, ३१। भसनेह, ३२। गुरसरांग, ३३। गोरपुरा, ३४। गुरसरांग, ३५। वरगपुरा, ३६। वागौर।

7-25-3 नये प्रा० स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना :- वर्ष 87-88 में 5 नये प्रा० स्वा० केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रा० स्वा० केन्द्र 30,000 की जनसंख्या पर स्थापित होते हैं। तथा इनके अधीन 5-6 उपकेन्द्र होते हैं। वर्तमान में स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी एवं स्टेट आधुनिक डिस्पेंसरी को परिवर्तित करके नये प्रा० स्वा० केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जिससे कि वित्तीय भार कम हो जाता है। विभागीय मानकों के अनुसार एक नये प्रा० स्वा० केन्द्र की स्थापना पर लगभग 70-80 हजार रु० व्यय होता है। स्थापना वर्ष में केवल 6 माह के लिये धन का प्राविधान किया गया है।

वर्ष 85-86 एवं वर्ष 87-88 में स्वीकृत एवं स्थापित प्रा० स्वा० केन्द्र रखरखाव के लिये धन का प्राविधान किया गया है। प्रस्तावित नये प्रा० स्वा० केन्द्रों के नाम निम्न है।

111 रक्सा, 121 रेवन, 131 शहाजहांपुर, 141 ठहरौली, 151 रानीपुर

7-25-4 सासुदायिक प्रा० स्वा० केन्द्रों की स्थापना एवं भवन निर्माण :-

वर्ष 87-88 में दो सा० प्रा० स्वा० केन्द्रों की स्थापना एवं मऊरानीपुर के रखरखाव हेतु 3-95 लाख रु० का प्राविधान किया जा रहा है।

वर्ष 87-88 में प्रा० स्वा० केन्द्र चिरगांव के उन्नयन का प्रस्ताव रखा गया है। शासनादेशानुसार एक उच्चकृत प्रा० स्वा० केन्द्र के भवन निर्माण की लागत लगभग 47-00 रु० लाख आती है। एवं एक उच्चकृत प्रा० स्वा० केन्द्र का भवन निर्माण में लगभग 3-4 वर्ष लगते हैं। अतः चिरगांव में वर्ष 87-88 में निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु केवल 7-05 लाख रु० की मांग की गई है।

नई योजनाएँ

7-25-6 111 चीर घर का निर्माण :- वर्ष 87-88 में उच्चकृत प्रा० स्वा० केन्द्र पर पहले से स्वीकृत चीरघर के निर्माण के लिये धन का प्राविधान किया गया है। मऊरानीपुर एक तहसील स्तरीय चिकित्सालय है तथा पोस्ट मार्टम सेंटर है। चीरघर बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। जिसका निर्माण होना आवश्यक है। इसके भवन निर्माण हेतु 3-00 लाख रु० की मांग की गयी है।



7-25-76 121 अस्पतालों में विशिष्ट उपचार सेवाओं की व्यवस्था :-

वर्ष 87-88 में दो उच्चकृत प्रां. स्वा. केन्द्रों गुराणीपुर में दन्त सज्जाला की स्थापना हेतु धन का प्राविधान किया गया है। अभी तक जनपद में केवल जिला चिकित्सालय में ही यह सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस इकाई की स्थापना होना आवश्यक है।

60 हजार रु० का प्राविधान प्रस्तावित है।

131 शहरी/ग्रामीण होमोपैथिक चिकित्सा इकाई की स्थापना :-

वर्ष 87-88 में इस विभाग में शहरी/ग्रामीण होमोपैथिक चिकित्सा इकाई की स्थापना हेतु धन का प्राविधान किया गया है। इसकी स्थापना हेतु वर्ष 87-88 में धन का प्राविधान किया गया है। इसका विस्तार होगा। इसकी स्थापना हेतु स्थापना वर्ष में लगभग 30-40 हजार रु० व्यय होगा।

7-25-8 अस्पतालों में साज सज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री की

पूर्ति :-

इस जनपद में तीन प्रां. उच्चकृत प्रां. स्वा. केन्द्र कार्यरत हैं। जिसमें वर्ष 87-88 में केवल एक उच्चकृत प्रां. स्वा. केन्द्र गुराणीपुर में जनरेटर लगाने हेतु धन का प्राविधान किया जा रहा है। उच्चकृत प्रां. स्वा. केन्द्र गुराणीपुर एक तहसील स्तरीय चिकित्सालय है तथा इसके साथ एक पी०पी० सेण्टर एवं एक सहिना चिकित्सालय भी कार्यरत है। गुराणीपुर एक पोस्ट माटीम सेण्टर है। यह उच्चकृत प्रां. स्वा. केन्द्र इस समय लगभग चार प्रां. स्वा. केन्द्रों के मरीजों को विशेष चिकित्सीय सुविधाएँ प्रदान करता है। अतः यहां पर डीजल जनरेटर की व्यवस्था आवश्यक है। एक जनरेटर पर लगभग 2-30 लाख रु० आता है। जिसके 136-00 हजार रु० जनरेटर की लागत है एवं उसे 214-00 हजार रु० वेतन एवं रखरखाव की हेतु है।

**1568**  
**आयुर्वेदिक चिकित्सालय**

7-25-9 प्रदेश के गरीब क्षेत्रों में नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना :- वर्ष 1936-37 में प्रस्तावित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से प्रथम स्तर से केवल दो चिकित्सालयों गाय रसपुरा एवं धमना विकास छाण्डे चिरगांव की ही स्वीकृति प्रदान की गई है। विकास छाण्डेवार आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालयों की स्थिति निम्न प्रकार है।

ब्लॉक	क्रमांक चिकित्सालय/औषध संस्था
1- इलाहाबाद	1
2- गाय रसपुरा	1
3- धमना	1
4- चिरगांव	1
5- विकास छाण्डे	1
6- गुरसराय	2
7- मऊरानीपुर	2
8- मोठ	2

योग = 17

क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 37-38 में गाय मढ़िया, ग्राज वैदोरा एवं ग्राम राजापुर में नये चिकित्सालय/औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। प्रत्येक नये चिकित्सालय हेतु रु० 50 हजार प्रति चिकित्सालय की दर से एवं चालू चिकित्सालयों के रखरखाव हेतु 30 हजार रु० प्रति चिकित्सालय की दर से कुल 2-40 लाख रु० का परिकल्पना प्रस्तावित है।

7-25-10 शहरी क्षेत्रों में 25 शैयायुक्त नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना :- वर्ष 36-37 में जनपद के तहसील मुख्यालय मऊरानीपुर जो हरिजन वाहुल्य क्षेत्र है एवं 25 शैयायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 37-38 में जनपद के पिछड़ी जाति वाहुल्य क्षेत्र एवं पिछड़े कस्बे तरासागर में एक 25 शैयायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 87-88 हेतु चालू चिकित्सालयों के रखरखाव हेतु 2-50 लाख रु० तथा नये चिकित्सालय की स्थापना हेतु 1-50 लाख रु० का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार इस योजना के कुल 4-00 लाख रु० की मांग की गई है।

7-25-11 वर्तमान आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों तथा औषधालयों का प्रोन्नयन एवं उनकी स्थिति में सुधार :- इस योजना

के अन्तर्गत रु० 3000 प्रति ग्रामीण चिकित्सालय एवं 12-00 हजार प्रति नगरीय चिकित्सालय की र से अतिरिक्त औषधियां उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कुल 63 हजार रु० का कुल परिव्यय रखा गया है।

#### नई योजनाएँ

7-25-12 :- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण :- वर्ष 1986-87 में रक्सा ग्राम में एक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय खोला गया था। इस चिकित्सालय हेतु भवन बनाने के लिये विभागीय मानकों के अनुसार 3-00 लाख रु० की आवश्यकता होती है। भवन निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जायेगा। वर्ष 1987-88 हेतु केवल 1-20 लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का कुल परिव्यय 8-23 लाख है।

#### ग्रामीण पेयजल- ग्राम्य विकास विभाग

7-27-00 :- वर्ष 1986-87 में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत चल रहे "ग्रामीण पेयजल" कार्यक्रम हेतु जिला योजना से धन का प्राविधान किया गया था पर शासन स्तर से इस मद हेतु कोई प्राविधान नहीं किया गया। वर्ष 87-88 हेतु 2-50 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है जिससे 16 हैण्डपम्प लगाने का लक्ष्य है।

7-27-01 जल निगम :- इस विभाग द्वारा चालू योजनाओं हेतु कोई मांग नहीं रखी गयी है। जल निगम द्वारा ग्राम कोंडाभांवर में नल लगाकर जल आपूर्ति की नई योजना प्रस्तुत की है जिसकी कुल लागत 10 लाख रु० आंकलित की गयी है। इस ग्राम के पास लघु औद्योगिक आस्थान बन रहा है तथा यहां इन्जीनियरिंग कालेज निर्माण भी प्रस्तावित है।

7-28-0 ग्रामीण आवास-ग्राम विकास :- ग्राम्य विकास विभाग के ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2-0 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है ।

7-29-0 सूचना एवं श्रम कल्याण :- सूचना एवं श्रम कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 87-88 हेतु कोई परिव्यय नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

#### सेवायोजन

7-30- सेवायोजन कार्यालय का सुदृणीकरण :- इस विभाग को वर्ष 86-87 में कार्यालय सुदृणीकरण योजना के अन्तर्गत कार्यालय भवन निर्माण हेतु 4-0 लाख रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया था । जिला स्तर पर अभी तक भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धि सुनिश्चित न हो सकने के कारण वर्ष 87-88 में इस कार्य हेतु परिव्यय नहीं स्वीकृत किया गया है ।

वर्ष 1987-88 में इस विभाग के स्थानीय कार्यालय हेतु जीप की व्यवस्था किये जाने हेतु 1.20 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है । 1-00 लाख रु० जीप क्रय हेतु 8 हजार रु० का परिव्यय रखा गया है ।

#### शिक्षण प्रशिक्षण

7-30-0 1अ1 वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विस्तार सुदृणीकरण :- प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न ट्रेडों के लिये साज सज्जा उपलब्ध कराने हेतु 3-00 लाख रु० का प्राविधान रखा गया है । स्टैण्डर्ड टूललिस्ट के अनुसार आवश्यक सामग्री क्रय की जायेगी ।

2।व1 वर्तमान संस्थान के चारों ओर किसी भी प्रकार की चहारदीवारी न होने के कारण असुरक्षा की समस्या है । इसके लिये 16-0 लाख रु० की लागत आंकड़ित है । वित्त के अभाव में इस वर्ष 4-00 लाख रु० स्वीकृत किया गया है ।

#### हरिजन एवं समाज कल्याण

7-31-0 1अ1 अनुजाति/जनजाति का कल्याण :- हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित अनुजाति/जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न चालू कार्यक्रमों हेतु 3-36 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तुत है । इस वर्ष गृह निर्माण <sup>अनुजाति</sup> ~~अनुजाति~~ 1आवास नामक योजना के अन्तर्गत कोई परिव्यय इसलिये स्वीकृत <sup>नहीं</sup> किया गया है कि वर्ष 85-86, 86-87 में इसकी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं निर्गत की गई ।

7-31-1 समाज कल्याण :- समाज कल्याण विभाग की चालू योजनाओं हेतु वर्ष 87-88 में 1305-00 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है। इयमें निराश्रित विधवाओं का परिव्यय विशेष रूप से बढ़ाया गया है।

7-31-2 समाज कल्याण- पुष्टाहार :- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 86-87 की भांति ही 26-72 लाख रु० का प्राविधान रखा गया है।



## :: स्थानीय संसाधन ::

8-0 जनपद की आर्थिक तथा स्थानीय सिंचित संसाधनों की उपलब्धता एवं उनके प्रयोग पर निर्भर करती हैं। कृषि उत्पादन जनपद की कृषि भूमि, जलवायु एवं सिंचाई की संसाधनों पर निर्भर है। कच्चे माल की उपलब्धता पर कृषि/वनोपज पर आधारित उद्योगों का विकास निर्भर है। जनपद झांसी की भौगोलिक संरचना पठारी है। यहाँ मार, कावर, प्रडवा, एवं राऊड़ किस्म की मिट्टी पायी जाती है। मार, कावर एवं प्रडवा कृषि की दृष्टि से उपयुक्त हैं। परन्तु सिंचाई साधनों की कमी तथा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली कृषकों द्वारा कम अपनाने का कारण जनपद की कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो सका। नीचे के आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं।

8-1 भूमि उपयोगिता जनपद झांसी वर्ष 1983-84

<u>सद का नाम</u>	<u>क्षेत्रफल हेक्टेयर में</u>
1- भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदन क्षेत्र	492204
2- वन	32544
3- ऊसर एवं खेती के अयोग्य भूमि	31661
4- खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी जोने वाली भूमि	36168
5- कृषि योग्य बेकार भूमि	48292
6- स्थानीय चारागाह तथा अन्य चराई की भूमि	919
7- अन्य वृक्षों झाड़ियों प्राणों आदि के क्षेत्र जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।	2028
8- वर्तमान परती	19784
9- अन्य परती	17334
10- जोया गया वास्तविक क्षेत्र	203471
11- एक बार से अधिक बार जोया गया क्षेत्र	33736
12- सम्पूर्ण जोया गया क्षेत्र	337207

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनपद के कुल क्षेत्रफल में से केवल 62 प्रतिशत भाग में कृषि होती है। दोफराली क्षेत्रफल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल का मात्र 1-4 प्रतिशत है जो कृषि के पिछड़ेपन का द्योतक है। जनपद में ऊसर व खेती के अयोग्य भूमि तथा कृषि योग्य बेकार भूमि क्रमशः 7 व 9 प्रतिशत हैं।

वर्ष 83-84 में जनपद में कुल 90211 हेक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रोत्तों से सिंचाई की गयी। जो कुल कृषि क्षेत्र का 23-8% है। जनपद में 32544 हेक्टेयर क्षेत्र में वन हैं।

8-2 जनपद में वर्ष 1983-84 में खरीफ खाद्यान्न का कुल 56457 मी०टन उत्पादन हुआ जिसमें 44577 मी०टन केवल ज्वार 5613 मी०टन मक्का, 3213 मी०टन धान तथा 2590 मी० टन खरीफ दालें। वेष अन्य पदार्थ उगाये गये। रबी फसल में मुख्यतः गेहूं 184968 मी०टन, 55559 मी०टन चना, 17155 मी०टन अरहर, 15349 मी०टन मसूर का उत्पादन हुआ। रबी में कुल खाद्यान्न उत्पादन 33481 मी०टन रहा। तिलहन का कुल उत्पादन 5759 मी०टन रहा।

उत्पादन की दृष्टि से यह जनपद अपने प्रयोग से अधिक खाद्यान्न उपजाता है।

#### 8-3 भू-गर्भ जल की उपलब्धता:-

वर्ष 1981-82 के भूगर्भ जल सर्वेक्षण के आधार पर जनपद में 1549 हेक्टेयर मीटर जल उपलब्ध हैं। ब्रितियों से 23642 हेक्टेयर मीटर जल का उपयोग हो रहा है तथा 41507 हेक्टेयर मीटर जल का उपयोग अभी नहीं हो पा रहा है जिसे के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

#### 8-4 खनिज सम्पदा:-

जनपद में मोरम, ग्रेनाइट, पाइरोक्लाइट, बेरा सफ़ार, काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ग्रेनाइट व मोरम विकास खण्ड चंडागाँव एवं चानीना में, पाइरोक्लाइट एवं बेरा सफ़ार, तहसील झाँसी एवं विकास खण्ड मंगरा में पाया जाता है। ग्रेनाइट क्रानिंग हेतु जनपद में लगभग 38 छेद कार्यरत हैं। गढ़वाँ में पाइरोक्लाइट खनिज प्रारम्भ हो गया है।

#### 8-5 पशुधन:-

1982 की पशुगणना के अनुसार जनपद में पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है :-

1- गोवंशीय	368139
2- सहस्र वंशीय	101572
3- भेड़ें	64996
4- बकरियाँ	174403
5- धोड़े एवं टट्टू	463
6- सुअर	10006
7- अन्य पशु	39735
योग-	759314



8-6 मत्स्य:-

जनपद में पटुज, वडवार, पहाडी, जहूरा एवं पारीछा जलाशयों में मत्स्य पालन कार्य 6880 हेक्टेयर क्षेत्र में होता है। मत्स्य प्रक्षेत्र में वर्ष - 1985-86 में 1.20 लाख अंगुलिकाओं का उत्पादन किया गया।

8-7 जनशक्ति:-

वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 11.33 लाख व्यक्ति हैं जिनमें से 7.06 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4.27 लाख नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। पुरुष 6.06 तथा महिलायें 5.27 लाख हैं।

दीर्घकालीन विकास की रूपरेखा

91- जनपद-झाँसी प्रदेश के पिछड़े जनपदों में एक हैं। प्रति व्यक्ति आय, अस्थापना एवं सेवा सुविधाओं की उपलब्धता किसी जनपद के पिछड़ित अथवा पिछड़ा मानने के लिये मापदण्ड हैं। राज्य नियोजन संस्थान, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ०प्र० की बुलेटिन संख्या 87 जिता धरेलू शुद्ध उत्पादन उ०प्र० के अनुसार 1971 के भावों पर झाँसी प्रदेश के उन 19 जनपदों में से एक हैं जिनका प्रति व्यक्ति व उत्पाद्य एवं कुल उत्पादन में वृद्धि दर दोनों ही राज्य औसत से कम हैं।

जिला	प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद 10,000	कुल शुद्ध उत्पाद में वृद्धि दर प्रतिशत 1971-77	
		सभी खण्ड	कृषि एवं पशुपालन
1	2	3	4
राज्य औसत	325.82	1-3	1-1
झाँसी झाँसी एवं ललितपुर	295.74	0-9	1-8

9-2 जनपद झाँसी का प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद एवं कुल उत्पाद 1970-71 के भावों पर राज्य स्तर से कम हैं वही इसी प्रकाशन की तालिका 1-2 से स्पष्ट हो रहा है कि जनपद कुल उत्पाद्य एवं प्रति व्यक्ति उत्पाद दोनों की गति गिरावट की ओर है।

वस्तु उत्पादन संवर्ग से कुल एवं प्रति शुद्ध उत्पाद 1970-71 के भावों पर।

1970-71		1973-74		1974-75	
कुल उत्पादन कैरोड रु०	प्रतिव्यक्ति उत्पाद रु०	कुल उत्पाद कैरोड रु०	प्रतिव्यक्ति उत्पाद रु०	कुल उत्पाद कैरोड रु०	प्रतिव्यक्ति शुद्ध उत्पाद रु०
43-72	337-80	37-47	273-70	22-84	246-12
1975-76		1976-77			
कुल उत्पाद कैरोड रु०	प्रति व्यक्ति शुद्ध उत्पाद रुपया	कुल उत्पाद कैरोड रु०	प्रतिव्यक्ति शुद्ध उत्पाद रुपया		
28-20	298-10	28-48	295-74		

:- 1970-71, 73-74 तक के आंकड़े झाँसी ललितपुर संयुक्त जनपद के हैं।

यदि केवल झाँसी जनपद के 74-75, 75-76 व 76-77 के आंकड़ों को देखा जाय तो इससे स्पष्ट होता है कि जनपद का कुल उत्पाद तो बढ़ा है पर प्रति व्यक्ति उत्पाद घटा है। इसका मुख्य कारण झाँसी जनपद में जनसंख्या वृद्धि है। जो राज्य नियोजन संस्थान उ०प्र० के क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की जिलावार विकास संविदांक अगस्त 83 के प्रकाशन से स्पष्ट है कि -

जनसंख्या का घनत्व	1971-81 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि		नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत।
	सामान्य	अनुजाति	
राज्य 377	+ 25-49	26-44	17-95
बुन्देलखण्ड 185	+ 26-52	27-95	19-97
झारखी 226	+ 32-21	35-83	37-94

9-3 इसी पत्रिका में प्रकाशित कृषि उद्योग का अवस्थापना एवं निम्न सम्बन्धी प्रतिफल विकास सेक्टर जनगणना के पिछड़े पान को स्पष्ट करते हैं।

	कृषि गहनता 1980-81	वनक्षेत्र में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत।	प्रतिव्यक्ति कृषि उपज का मूल्य
राज्य	142-69	17-25	54-89	589-51
बुन्देलखण्ड	112-68	8-10	23-95	710-15
झारखी	114-27	6-60	29-28	573-74

	प्रति 100वर्ग कि०मी० क्षेत्र पर पक्का मार्ग कि०मी० 1982	विद्युत के कुल उपयोग में से कृषि उपयोग का प्रतिशत	प्रति 1000 जनसंख्या 1981	प्रति लाख जनसंख्या एलापैथिक चिकित्सा 1981
राज्य	21-8	28-04	26-90	2-87
बुन्देलखण्ड	16-0	32-60	33-31	3-20
झारखी	24-2	7-51	22-29	3-00

जनगणना की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार कुल श्रम शक्ति का 60-84 प्रतिशत भाग कृषि पर, निर्धर पाया गया और 5-18 प्रतिशत गृह उद्योग एवं उत्पादन व-व्यवस्था में।

9-4 उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जनगणना के विकास के लिये सुनिश्चित प्रयत्न किये जाना अति आवश्यक हैं। जनगणना के विकास के लिये 1990 तक के लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।-

क्रमांक	1981	1990
1	2	3
1- जनसंख्या	1133002	1475282
2- कर्मचारियों की संख्या	316481	436399
3- साक्षरव्यक्ति संख्या	415959	633131
4- बोया गया क्षेत्र हेक्टेयर	299871	384602

1	2	3
5- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	47297	80363
6- जल का क्षेत्र हे० हे०	27441	37399
7- श्रोतों की संख्या	153977	175210
8- श्रोतों के अन्तर्गत क्षेत्र	336807	340640
9- सुविधिसंचित क्षेत्र हेक्टेयर	87816	131016
10-सफल सिंचितक्षेत्र हेक्टेयर	89255	299871
11-कुल खाद्यान्न क्षेत्र हेक्टेयर	315027	427442
12-कुल वाणिज्यकफसलें हे०	3745	6924
13-अन्य उद्यानों का क्षेत्र हे०	2240	2790
14-कुल उर्वरक डिपों सं०	60	65
15-उर्वरक के लिये क्षेत्र हे० टन	6130	7630
16-कृषिअभियोगधान केन्द्र	7	9
<u>अवस्थाने एवं सेवायें</u>		
1- राष्ट्रीय मार्ग	137	-
2- प्रान्तीय मार्ग	78	930
3-अन्य पक्के मार्ग	561	-
4- प्रारम्भिक पाठशाला	917	1475
5- मिडिल स्कूल	215	250
6- उच्चतर माध्यमिक स्कूल	58	74
7- ग्रामीण जलपूर्ति	158ग्राम	100प्रतिष्ठित प्रभारग्रस्त ग्राम
8- विद्युत लाइनों की लम्बाई मी०	594	1332
9- ग्रामों का विद्युतीकरण	141	304

उत्पादन बढ़ाने के लिये उर्वरक का उपयोग खेती की पद्धतियों में सुधार उन्नतशील बीजों की आपूर्ति, दो फसली क्षेत्र में वृद्धि, कीटनाशक दवाओं का उपयोग करना आवश्यक है ।

9-5 कृषि के सम्बन्धीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यान, पशुपालन, वानिकी संबंधी कार्य हैं । जनसह के पशुधन में प्रतिक्रमजोर हैं तथा उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम है । इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है । ग्रामीण अंचल में स्थित कमजोर वर्ग की जनता के उत्थान हेतु ककरीपालन, सुअर पालन, भेड़ पालन एवं कुकुरट पालन विकास योजनाओं को प्रगति देने का कार्यक्रम है ।

9-6 कृषि उत्पादन में सुनिश्चित सिंचाई साधनों का सृजन करना अति आवश्यक है। मध्यम सिंचाई के अतिरिक्त सपरार एवं डोगरी बांध जनमत शक्ति में पूर्ण हैं। पर इनसे 86-87 में सिंचाई हो सकेगी। जनमत में एक रिपोर्ट सेटिंग इकाई की स्थापना की गयी है जो नलकूपों के डिद्रण के पूर्व भूमिगत जलस्तर का सर्वेक्षण पूर्ण कर जिला प्रशासन तथा सिंचाई विभाग को मार्ग दर्शन देते हैं। उस समय तक इस जनमत में 52 नलकूप डिद्रित किये जा चुके हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रम में भी ली रिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कोर प्रोजेक्ट द्वारा 29 चेक डैम बनाये जा चुके हैं। पम्पिंग सेट डीजल/विद्युत का बृहद कार्यक्रम चलाये जाने का प्लान बनाया जा रहा है। शासन का प्लान है कि जनमत में सिंचाई के साधनों का तीव्र गति से विकास किया जाय।

9-7 पशुपालन कृषि का सहायक एवं आवश्यक सह उद्योग है। जनमत में उद्योग पशुधन दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से निम्नस्तर का है। जनमत में एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त बकरीपालन को विशेष बर्दावा दिया जा रहा है। इस समय अच्छे नस्ल की बकरी जमुना भारी आगरा एवं हटावा जनमतों से मंगाई जाती हैं। क्रास ब्रीडिंग द्वारा स्थानीय जलवायु में "बकरी प्रजनन केन्द्र" स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। भेड़ पालन के विकास हेतु "ऊन ग्रेडिंग" स्थापित किया जा चुका है। सुअर पालन एवं कुक्कुट पालन का भी पर्याप्त विकास हो सकता है। स्थानीय तौर पर अण्डों की खपत इतनी अधिक मात्रा में होती है कि इनकी पूर्ति आंध्र प्रदेश से अर्द्ध मंगा कर की जाती है।

9-8 औद्योगिकरण विकसित अर्थव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। जनमत औद्योगिक दृष्टि से अति पिछडा है। इस समय वृहद एवं मध्यम उद्योगों में केवल केरिज एण्ड बैंगन रिपोरर वर्कशाप, देवी इलेक्ट्रीकल्स, सूती मिल, करारा इथ्स पाइप तथा स्लीपर कारखाना हैं। फैक्ट्री एक्ट में 37 उद्योग पंजीकृत हैं। जनमत में एक आर्डीनेल्स कारखाना, इन्डोगल्फ एक्सप्लोसिव, फटीलाइजरफैक्ट्री, ग्लैसों कम्पनी का दूख सुखाने तथा सोयाबीन से दूध बनाने का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। इती सड़क पर एक राज्यकीय प्रेस छापाखाना बन रहा है जो वर्ष 86-87 में कार्य करने लगेगा। कानपुर रोड पर कर बैदा मिल डाली जा चुकी है। स्ट्रील प्लांट, चीनी पात्र, डैन्डलूम वस्त्र, गौमवत्ती, सायुंन, तेलधानी, लकड़ी के फर्नीचर, बीडी बनाना, कम्बल के कालीन ढाल मिल, तीयेन्ट की जाली, आयुर्वेदिक दवाईयां, आटा व गन्नाले पीसना एवं सगरी पाट बनाना, अमरबत्ती बनाना, अल्यूनियम के ब पील के वर्तनों का बनाना पाइरोफ्लाइड ग्रेनाइट उद्योग आदि जनमत के प्रमुख उद्योग हैं।

### 9-9 विद्युत आपूर्ति:---

जनपद के कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिये बिजली की आपूर्ति विशेष महत्वपूर्ण है। पारीछा नामक स्थान पर भारी लागत से थरजल पावर स्टेशन निर्मित कर लिया गया है। तथा उसमें विद्युत उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 84-85 में बिजली का उपभोग निम्न प्रकार रहा -

<u>मद</u>	<u>प्रतिशत उपभोग</u>
1- धरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युत शक्ति	28
2- वाणिज्यिक प्रकाश	26
3- औद्योगिक विद्युत शक्ति	35
4- सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	1
5- सिंचाई एवं जल निस्तारण	8
6- विविध कार्य	2

9-10 ग्रामीण अंचल तक पहुंचने हेतु सड़कों की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मार्च 1982 तक जनपद में प्रति 100 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल पर 24-2 कि०मी० सड़कें आती हैं। 1990 तक 1500 से ऊपर के समस्त ग्राम तथा 1000-1500 के मध्य आवादी वाले 50 प्रतिशत ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिले में सड़कों का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है।

9-11 प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त वर्ष वर्ग 6-14 के बच्चों का शत प्रतिशत कक्षा प्रवेश तथा 15-35 वय वर्ग का 1990 तक नाममात्र फार्मल शिक्षा के माध्यम से आच्छादन के लक्ष्य रखे गये हैं।

9-12 1990 तक प्रति ग्राम अथवा प्रति 1000 की आवादी पर एक कम्युनिटी स्वास्थ्य स्वयं सेवक की नियुक्ति, 5000 जनसंख्या पर एक सब सेन्टर तथा 3000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

9-13 भूमिहीन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को सीलिंग एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का आवंटन तथा उसके विकास के लिये अनुदान दिया जाता है। आवास गृह निर्माण हेतु भूमि आवंटन हो रहा है। इस कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के लिये अनुदान की राशि बढ़ा दी गयी है।

### 9-14 पेयजल व्यवस्था:---

जनपद झांसी की पेयजल की समस्या प्रमुख रही है। जलनिर्माण, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जल निष्पत्ति के लिये प्रत्येक गाँव में एक सड़क बंधी है। जिले में सड़क बंधी गाँवों को सड़क द्वारा जोड़ने का लक्ष्य है।

9-15 सामान्य विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ हरिजन एवं निर्दलवर्ग का उत्थान, मलिन बर्ती पर्यावरण सुधार एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रमों को भी चलाया जा रहा है जनसंख्या के अनियमित विकास को रोकने के लिये परिवार कल्याण कार्यक्रम तीव्रगति से चलाया जा रहा है। वर्ष 1984-85 में जनपद ने प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अध्याय - 10-::: जिला योजना की पूर्वार्थे :::

10-0 वर्तमान मियोजन प्रणाली में उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग कर उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक विकास किया जाना सम्भव है। यहाँ पर पर्यावरण सुधार सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न कर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। मानव का शोषण भेदभाव की नीति, कृष्यता, अशिक्षा, पर्यावरण की कमी प्रकृत में बाधक सिद्ध होती हैं। जोदेश प्रदेश एवं जनपद की समस्याओं से निपटने के लिये विभिन्न योजना ओ चलाई जा रही हैं।

10-1 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 से 1955-56:---

राजनैतिक स्वतन्त्रता के आवश्यक तत्वों को रखते हुये तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, स्वाधीनता और प्रजातन्त्र के मूल्यों के आधार पर सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था की रचना करना जिससे रोजगार तथा उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि हो तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके।

2- द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-57 से 60-61:---

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिये आय में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना तथा मूल एवं आधारभूत अद्योगों पर वल देते हुये शीघ्र औद्योगिकरण करना था। रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर आय धन तथा आर्थिक साधनों के वितरण की असमानता को कम करने, राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि तथा जीवन स्तर में उन्नति, उत्पादन एवं विनियोगों में वृद्धि सम्भव नहीं है।

3- तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961-62 से 1965-66:---

तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कम से कम 5 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष करना। विनियोग का स्वल्प रेशा रबना जिससे इस प्रयास को वल मिलता रहे। खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर होना तथा निवेश की पूर्ति के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि करना रोजगार के अवसर में वृद्धि करना। आर्थिक संसाधनों के वितरण में समानता लाना तथा आय एवं धन के वितरण की असमानता को कम करना।

4- वार्षिक योजना	66-67
5- वार्षिक योजना	67-68
वार्षिक योजना	68-69

उपरोक्त वार्षिक योजना में रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि करना आर्थिक साधनों के वितरण में समानता लाना खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर होना

तथा उद्योग एवं निर्यात की पूर्ति के लिये कृषि उत्पादन में वृद्धि करना जिससे प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि सम्भव हो सके ।

5- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969-70 से 1973-74:--

इस योजना में भी

रोजगार उपलब्ध कराने में वृद्धि करना खाद्य पदार्थों में आत्म निर्भर होना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना तथा विनियोग का स्वरूप ऐसा रखना जिससे प्रगति को बल मिलता रहे । आर्थिक साधनों के वितरण में समानता लाना तथा आय और धन के वितरण की असमानता को दूर करना ।

6- पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-75 से 1978-79:--

राष्ट्रीय उद्देश्यों

तथा प्राथमिकताओं के अनुसार जिला योजना का निर्माण किया जाता है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये मुख्य उद्देश्य बेरोजगार को लाभ प्राप्त रोजगार उपलब्ध कराना, लघु कृषकों तथा ग्रामीण शिल्पकारों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, विद्युत सिंचाई, सड़क एवं जल सम्पूर्ति जैसी आधारभूत अवस्थापना का सुदृढीकरण, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति करना, विकासशील केन्द्रों तथा नगरीय क्षेत्र को विकसित करना, पिछड़े समुदायों के रहन-सहन रोजगार तथा शिक्षा के स्तर का सुधार, बढ़ती हुयी जनसंख्या की दर को कम करने हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसार करना है ।

7- वार्षिक योजना 1979-80:--

पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्रम वार्षिक

योजना में परिवर्तित हो गयी और इसी क्रम में वर्ष 1979-80 की वार्षिक योजना चली । इसका उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुरूप ही रहा है ।

8- छठी पंचवर्षीय योजना 1980-81 से 1984-85:--

वर्ष 1979-80 में

विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का सर्वेक्षण कर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थापना सुविधा की उपलब्धियों को आधार मानकर योजना आयोग में छठी पंचवर्षीय योजना की रणनीति एवं उद्देश्य का निर्धारण किया है । इस योजना का परिचय 1980-81 व 81-82 में राज्य स्तर से निर्धारित किया गया । स्थानीय क्षेत्रीय संस्थाओं के निराकरण हेतु आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने, योजनाओं को त्वरित कार्यान्वयन एवं अधिकतम लाभ हेतु वर्ष 82-83 में विकेन्द्रीकरण प्रणाली का शुभारम्भ किया गया इस प्रणाली के अन्तर्गत राज्य योजना बजट के कुल आवंटन की 30 प्रतिशत धनराशि जिले की स्थानीय आवश्यकता को देखते हुये निर्धारित की गयी । योजना का उद्देश्य:--

क- आर्थिक वृद्धि साधनों का उपयोग तथा उन्नत उत्पादकता विकास में वृद्धि ।

ख- आर्थिक एवं प्राबधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये आधुनिकता



की गति को सुदृढ़ करना ।

ग- गरीबी एवं बेरोजगारी के भार में प्रभावी कमी करना ।

ध- भारतीय राजा के उचित संरक्षण एवं उपयोग पर ध्यान देना ।

ड- सामान्य व्यक्तियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में गुणात्मक सुधार न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के द्वारा करना ।

च- आय एवं धन की असमानता कम करने के उद्देश्य से गरीबी के हित में सार्वजनिक नीतियाँ एवं प्रेरणाओं के वितरण के भेदभाव को सुदृढ़ करना ।

छ- सीमित परिवार के सिद्धान्त को स्वीकार कराकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की योजनाओं को प्रोत्साहन देना ।

ज- पर्यावरण एवं आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु प्रोत्साहन एवं सुरक्षा प्रदान कराकर अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना ।

झ- उपर्युक्त राजनीति द्वारा समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना ।

#### 10-2- जनपद की योजना के मूलभूत उद्देश्य एवं रणनीति:—

जनपद की योजना का मुख्य

उद्देश्य जनपद की आर्थिक सामाजिक एवं पर्यावरण की समस्याओं में जकड़े हुये नागरिकों को निकालना । जनपद शांसी की योजना के मुख्य उद्देश्य:—

1- जनपद के विकास की नीति आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के आधार पर बनायी गयी है । विकास कार्यक्रमों का लाभ सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के साथ-साथ कमजोर वर्ग जैसे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों तथा सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, निराश्रित महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्यक्रम तैयार किये गये हैं ।

2- आर्थिक उत्थान हेतु स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग वैज्ञानिक विविधियों से श्रेष्ठ, आवश्यक निवेश की पूर्ति का कार्यक्रम बनाया गया है । स्थानीय संसाधन जैसे भूमिगत जल, पशुशक्ति, मानव शक्ति का अधिकतम एवं संस्तुति विकास उपयोग सुनियोजित करके आर्थिक विकास किया जायेगा ।

3- शिक्षा, पर्यावरण के सुधार और सुविधाओं की सामान्य नागरिकों के प्रगति हेतु कार्यक्रम बनाये गये हैं ।

4- वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत अनुदान का प्राविधान किया गया है । बैंकों के माध्यम से ऋण की उपलब्धता की योजना बनायी गयी है ।

5- स्थानीय निगमों को स्वावलम्बी बनाने हेतु नागरिकों के सहयोग प्रदान कार्य का विशेष ध्यान दिया गया है ।

6- जनसंख्या की वृद्धि रोकने हेतु सीमित परिवार का कार्यक्रम एवं नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुये औषधियों को प्राविधान किया गया है ।

#### 10-3 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:—

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल, ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण, प्राथमिक आहार, सम्मिलित है । इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से समाज के सामान्य नागरिकों के साथ ही गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे लोगों का विशेष लाभ होगा ।

10-4 भूमिहीन मजदूरों एवं भूबन्हीन व्यक्तियों को गांव सभाओं एवं सीमित सें प्राप्त भूमि को भवन निर्माण हेतु आवंटित करने की सरकारी योजनाओं चलायी जा रही हैं। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट हरिजन वित्त निगम के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा पिछड़ी हुई जातियों को सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं।

10-5 इन योजनाओं की प्रगति में तीव्रता लाने हेतु समीक्षा कर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना:--

जिला योजना 85-86 सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वर्ष 85-86 की वार्षिक जिला योजना 3-68 करोड रुपयों की तैयार की गयी थी।

1986-87 हेतु 4.29 करोड रुपयों का परिव्यय स्वीकृत किया गया। वर्ष 1987-88 की योजना राशि 4.90 करोड रुपया निर्धारित की गई है।

:: राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ::

11-1 राष्ट्रीय सरकार ने जनमानस के निम्ने कृत्तिय न्यूनतम आवश्यकताओं निर्धारित की हैं, जिनमे पूरा करने के लिये शासन कटिबद्ध हैं । इत कार्यक्रम के अर्तगत 1- प्राथमिक शिक्षा 2- प्रौढ शिक्षा 3- ग्रामीण स्वास्थ्य 4- ग्रामीण पेरजन 5- ग्रामीण सड़के 6- ग्रामीण विद्युतीकरण 7- ग्रामीण निर्धनों के लिये आवास 8- पर्यावरण सुधार 9- पौष्टिक आहारआदि गढ़ें आती हैं । इन गढ़ों से सम्बन्धित सैक्टरों के लिये जिला योजना बनाते समय वित्तीय परिसीमा के अर्तगत प्रावधान किये जा रहे हैं । विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिये निम्न धनराशि परिव्यय के रूप में रखी गयी ।

सद	1982-83 व्यय	1983-84 व्यय	1984-85 व्यय	1985-86 व्यय
1- शिक्षा	2065.00	2244.00	2270.00	2242.00
2- स्वास्थ्य	3758.00	3572.00	3853.27	2929.00
3- जलसुधार्ति क- जल निगम	2005.00	2600.00	2587.88	300.00
ख- ग्राम्यविकास	240.00	20.00	250.00	---
4- सड़के	1128.00	2363.00	2770.00	3021.00
5- विद्युतीकरण	505.70	506.00	561.00	624.00
6- आवाससुधार्ति	43.70	100.00	113.00	153.00
7- मलिनबस्ती सुधार	-	-	-	-
8- पुष्टाहार	587.00	505.00	225.00	912.00
अ-समाजकल्याण ब-ग्राम्यविकास	60.2	61.00	56.00	-

:: पिछड़े समुदाय के लिये कार्ययोजना ::

12.0 जनपद झाँसी में 1981 की जनगणना के अनुसार हरिजन समुदाय की जनसंख्या 325,965 है जो कुल आबादी का प्रतिशत 27.7 है। जनपद के गुरतराय एवं मऊरानीपुर विकास खण्डों में कुल आबादी में से हरिजनों का प्रतिशत 35 है। विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

क्र.सं० विकास खण्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	कुल में अनुसूचित जाति का प्रतिशत
1- चिरगाँव	85,198	24,927	29
2- जोठ	96,458	29,314	30
3- गुरतराय	37,679	13,504	35
4- बागीर	25,420	8,404	33
5- मऊरानीपुर	76,247	26,704	35
6- बंगरा	87,603	28,335	32
7- बवीना	59,174	15,103	25
8- लड़ागाँव	79,432	23,724	30
नगरीय योग-	243,354	59,749	24
योग :-	1137,031	352,965	30

12.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक सामाजिक शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु कृत संकल्प है।

विभिन्न वर्षों में हरिजन एवं अनुसूचित जाति के एवं निर्बल वर्ग के कल्याण हेतु उपलब्ध कराये गये वित्तीय परिव्यय का विवरण निम्न प्रकार है :-

पद	वर्ष	1982-83	83-84	84-85	85-86	86-87
1- हरिजन एवं समाजिक कल्याण विभाग		849.00	784.00	628.00	666.00	700.00
2- एकलव्य ग्राम्य विकास		2855	3200	3200	3144	

नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित/पिछड़ी जाति को फीस माफी/छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकों सम्बन्धी सहायता प्रदान की जाती है ।

आर्थिक विकास:- अनुसूचित जाति के सदस्यों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही जनता के आर्थिक विकास के लिये "भूमिहीनों" को आवास भवनों हेतु अनुदान, सिंचाई साधनों के क्रय/निर्माण हेतु अनुदान, स्वभाव कम्पोनेन्स प्लान के अन्तर्गत सहायता, औद्योगिक सहायता एवं बैंकों से रास्त दर पर उधार हेतु ऋण सुविधा में उपसब्ध कराई जाती है ।

निराश्रित विधवाओं के पेंशन सहायता/निर्धन वर्ग की महिलाओं/बालकों को पुष्टाहार सहायता प्रदान की जाती है ।

अध्याय-13

13-0-0 :- जनपद झांसी की जिला योजना के अन्तर्गत मात्र 4,90,14 हजार रु० का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। परिव्यय का अधिकांश भाग जनपद स्थिति विभिन्न विभागों की चालू योजनाओं की कार्यक्रमां के लिये परिव्यय उपलब्ध कराने में देना, पर किन्हीं परिस्थितियों में तो चालू योजनाओं विस्तार एवं सुदृणीकरण के लिये धनीभाव के कारण विनियम प्रस्तावित नहीं की जा सकीं। इन परिस्थितियों के उपरान्त भी वर्ष 87-88 हेतु निम्न अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण नदी न. योजना प्रस्तावित की जा रही है।

पंचायत राज विभाग

13-1-1 - योजना का नाम- जिला स्तर पर पंचायत राज भवन का निर्माण :-

उद्देश्य :- उत्तर प्रदेश शासन पंचायत राज विभाग जिला मुख्यालय पर पंचायत राज भवन निर्माण कराये जाने के निर्देश हैं, ताकि पंचायत राज सम्मेलन, पंचायत गोष्ठियों के आयोजन हेतु स्थानाभाव न रहे।

योजना का परिव्यय :- जिला पंचायत राज भवन के निर्माण भूमि, जिला विकास कार्यालय के प्रांगण में ही नि:शुल्क उपलब्ध है। निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कराया जायेगा। प्रस्तावित भवन की लागत 5 लाख रु० आंकलित की गयी है। वर्ष 87-88 हेतु 2-0 लाख रु० का परिव्यय रखा गया है।

योजना का लाभ :- जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार के पंचायत सम्मेलन, गोष्ठियों, जिला स्तरीय पंचायत उद्योग संचालन हेतु स्थान उपलब्ध हो जायेगा।

ग्राम्य विकास विभाग

13-2-1 - योजना का नाम- आवास रहित विकास खण्डों में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना :-

उद्देश्य :- विकास कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये ग्रामीण अंचलों में स्थित विकास खण्डों में कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

योजना का स्वरूप एवं परिचय :- जनपद में इस समय 8 विकास खण्ड में 3 क्रमशः बड़ागांव, बंगरा, एवं बामौर में राजकीय आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। इन तीनों विकास खण्डों में निम्न आवास निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है।

11	बी०डी०ओ० टाइप आवास	3	प्रति ब्लॉक	1
12	ए०डी०ओ० टाइप आवास	24	,,	8
13	मिनिस्ट्रियल आवास	21	,,	7
14	चतुर्थ श्रेणी आवास	9	,,	3
कुल भवन		57	,,	19

इस कार्य हेतु भूमि बड़ागांव, बंगरा, एवं बामौर में उपलब्ध है। निर्माण कार्य का आंकलन ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से करा लिया गया है। कार्य भी यही एजेंसी करेगी। योजना की कुल लागत 36-55 लाख रु० आंकी गयी है। वर्ष 87-88 हेतु केवल 15-20 लाख रु० का प्राविधान प्रस्तावित है।

#### ग्रामीण एवं लघु उद्योग

13-3-1 - योजना का नाम- औद्योगिक संस्थान का रखरखाव, स्वतंत्र औद्योगिक फीडर की स्थापना :-

उद्देश्य :-

झांसी मुख्यालय के गवालियर रोड पर स्थित औद्योगिक आस्थान जनपद का सबसे पुराना आस्थान है। इसमें कार्यरत उद्यमियों की स्वतंत्र औद्योगिक फीडर की सुविधा उपलब्ध कराना।

योजना का परिचय :-

औद्योगिक फीडर की मांग विगत वर्षों से की गयी थी पर वित्तीय अल्पता के कारण इसे प्रस्तावित नहीं किया जा सका। वर्ष 87-88 हेतु 4 लाख रु० का परिचय प्रस्तावित है।

लाभ :-

औद्योगिक आस्थान स्थित 27 उद्योगों को इससे उत्पादन बढ़ाने में लाभ पहुंचेगा।

#### चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

वर्ष 87-88 हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत योजनाओं में से निम्न योजनाओं की संस्तुति की जा रही है।

13-4-1 योजना का नाम- चीर घर का निर्माण :-

योजना की स्थिति व रखरखाव :-

वर्तमान में तहसील मुख्यालय पर मऊरानीपुर में एक पुराना चीर घर पोस्ट मार्टम सेण्टर का कार्यरत है, जिसका लाभ मऊरानीपुर एवं गरौठा तहसील को मिलता है। यह चीर घर भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है। मऊरानीपुर में उच्चिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोंठ में भी पोस्ट मार्टम सेण्टर स्वीकृत कर दिया गया है।

वर्ष 1987-88 हेतु मऊरानीपुर स्थित चीर घर का नया भवन बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसके लिये भूमि उपलब्ध है। निर्माण कार्य विभागीय मानकों के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया जायेगा। योजना का परिव्यय 3 लाख रु० प्रस्तावित है।

योजना का लाभ :-

योजना का लाभ तहसील गरौठा तथा मऊ के नागरिकों को मिलेगा।

13-4-2 - उच्चिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें :-

उद्देश्य :-

ग्रामीण क्षेत्रों में दन्त चिकित्सा सुविधा का प्रसार।

स्थान व परिव्यय :-

वर्तमान में दन्त चिकित्सा सुविधा केवल जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध है। इसको ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने के आशय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर व मोंठ में दन्त चिकित्सा इकाई खोलना प्रस्तावित है।

योजना का परिव्यय 60 हजार रु० है।

लाभ :-

तहसील मोंठ, गरौठा एवं मऊरानीपुर की जनता लाभान्वित होगी।

13-4-3 - योजना का नाम- होम्योपैथिक चिकित्सा इकाईयों की स्थापना :-

उद्देश्य :-

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति का ग्रामीण अंचलों में प्रचार एवं प्रसार।

स्थल व परिव्यय :-

वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा केवल जिला मुख्यालय पर ही उपलब्ध है। वर्ष 87-88 में उच्चिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में एक होम्योपैथिक चिकित्सा इकाई स्थापित करने का लक्ष्य है, जिस पर 30 हजार रु० व्यय का अनुमान है।



लाभ :-

मऊरानीपुर की जनता को इसका लाभ मिलेगा ।  
13-4-4 योजना का नाम- उच्चिकृत प्रा० स्वा० केन्द्रों में जनरेटर की  
व्यवस्था :-

उद्देश्य :-

उच्चिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना ।

स्थल व परिव्यय :-

उच्चिकृत प्रा० स्वा० केन्द्र पर बड़े जनरल आपरेशन, एक्सरे सुविधा एवं परिवार कल्याण आपरेशनों के लिये विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊरानीपुर में जनरेटर की सुविधा 87-88 में 2 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है ।

लाभ :-

आपरेशन, एक्सरे, में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चितता का लाभ तहसील मऊरानीपुर व गरौठा क्षेत्र को मिलेगा ।

13-4-5 योजना का नाम- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण ।

उद्देश्य :-

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ जनता को पहुंचाना व स्टाफ को रहने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना ।

स्थल व परिव्यय :-

वर्ष 85-86 में स्वीकृत रु० चिकित्सालय हेतु भवन ग्राम रक्षा में स्टाफ क्वार्टर्स हेतु कुल लागत 3 लाख रु० 40 प्रतिशत रु० 1-20 लाख प्रस्तावित है ।

योजना का लाभ :-

ग्राम रक्षा के निवासियों को लाभ मिलेगा ।

जल निगम

=====

13-5-1 योजना का नाम- कोंछाभांवर पेयजल योजना :-

उद्देश्य :-

कोंछाभांवर एवं निकटवर्ती क्षेत्र को नल लगाकर पेयजल आपूर्ति ।

परिव्यय :-

योजना की लागत 10 लाख रु० वर्ष 87-88 का परिव्यय

7-50 लाख रु० ।

लाभ :- कोंछभांवर ग्राम की जनता को प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालेज व औद्योगिक आस्थान कान्पुर रोड के उद्योग एवं निवासी ।

सेवायोजन  
=====

13-6-1 - योजना का नाम- सेवायोजन कार्यालय का सुदृणीकरण ।

उद्देश्य :- सेवायोजन कार्यालय में जीप की व्यवस्था ।

परिव्यय :-

मद	व्यय ह० रु०	अनावर्तक
1- जीप की लागत	-	100-00
2- ड्राइवर का वेतन व भत्ते	4-50	-
3- ड्राइवर का यात्रा भत्ता	०-50	-
4- पी०ओ०एल० चार्जेज	3-00	-
योग	8-0	100-00

कुल लागत 108 हजार रुपये

लाभ :- सी०पी०एन० एक्ट के अन्तर्गत नियोजकों से सम्पर्क में सुविधा व अन्य राजकीय कार्य पर सफल निगरण ।

शिल्पकार प्रशिक्षण  
=====

13-7-1 - योजना का नाम- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान झांसी चहारदीवारी का निर्माण ।

उद्देश्य :- वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण भवन की सुरक्षा ।

स्थल व परिव्यय :-

वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के चारों ओर 2500 मीटर लम्बी चहारदीवारी बनाना प्रस्तावित है । इसकी लागत 16 लाख रु० आंकी गयी है । 1987-88 हेतु कुल 4 लाख रु० का प्राविधान है ।

लाभ :- औद्योगिक प्रशिक्षण भवन प्रांगण की सुरक्षा ।

योजना का वित्त पोषण

14-0 :- सचिव नियोजन, उ० प्र० शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 3/122/35-आ०-2/36 -192 दिनांक 3-3-86 में प्रसारित निर्देशानुसार जनसहभागी जिला योजना वर्ष 37-88 4,90,14 हजार रु० की तैयारी की गई। वर्ष 1986-87 में जिला योजना की धनराशि 4,29,99 हजार रु० की स्वीकृत की गई थी।

14-1 वर्ष 1937-88 में जिला योजना हेतु वित्त निम्न श्रोतों से उपलब्ध होगा।

श्रोत	विभाग	धनराशि रु०
1- राज्य आयोजनागत जिला सेक्टर	जिला योजनायें सम्मिलित समस्त विभाग	4,90,14-00
2- केन्द्रीय सहायता	1- कृषि	50-00
	2- कृषि विपणन	271-00
	3- भूमि सुधार	50-00
	4- पशुपालन	4-00
	5- मत्स्य	360-00
	6- वन	750-00
	7- क्षेत्र विकास	
	अ॥ ए० ग्रा० वि०	4800-00
	व॥ डी०पी०ए०पी०	2250-00
	स॥ ल०सी०कू०	2000-00
	8- राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम	6000-00
	9- सहकारिता	250-00
	10- उद्योग	100-00
	11- शिक्षा	716-00
		<hr/> 175,01-00 <hr/>
3- पंचायतें	पंचायत	1050-00
4- संस्थागत वित्त	समस्त सेक्टर	5,02,00-00

समाप्त



:: विकेन्द्रित जिला योजना 1987-88 ::

: जी०स०-1 :

: योजनावार व्यय/परिव्यय:

जनपद - झांसी

परिव्यय हजार रु० में

क्र०सं०	विभाग का नाम	1980-85	1985-86	1986-87	अनुमोदित परिव्यय		1986-87	अनुमानित व्यय		1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चालू एवं नई योजना:-												
1-	कृषि	1501-40	841-00	883-00	440-00	-	883-00	440-00	-	1050-00	765-00	-
2-	उद्यान	1265-10	360-40	703-00	200-00	-	703-00	200-00	-	840-00	350-00	-
3-	कृषि विपणन	--	--	124-00	124-00	-	124-00	124-00	-	271-00	271-00	-
4-	भूमि सुधार	611-00	8-00	50-00	--	-	50-00	--	-	50-00	--	-
5-	निली लघु सिंचाई	9258-50	2494-00	2385-00	--	-	2385-00	100-00	-	2950-00	100-00	-
6-	राजकीय लघु सिंचाई	17786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	-
7-	भूमि एवं जल संरक्षण	6089-00	1540-00	1600-00	--	-	1600-00	--	-	2500-00	--	-
8-	पशुपालन	1173-00	802-38	1081-00	--	-	1081-00	--	-	1050-00	550-00	-
9-	मत्स्य विकास	104-93	--	450-00	--	-	450-00	--	-	360-00	--	-
10-	वन 2706-	2706-00	2525-00	2340-00	1070-00	2240-00	2840-00	1070-00	-	1990-00	840-00	-
11-	पंचायत राज	835-00	752-00	746-00	350-00	746-00	746-00	350-00	-	856-00	450-00	-
12-	प्रादेशिक विकास दल	159-00	116-00	200-00	--	-	200-00	--	-	343-95	100-00	-

:: 2 ::

:: जी०एम०-1 ::

विकेन्द्रित जिला योजना 1987-88				जनपद-ह्रासी हजार रुमें।								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13-	ग्राम्य विकास ब्लाक भवन	--	--	--	--	-	--	--	-	1500-00	1500-00	-
14-	एकीकृत ग्राम्य विकास	2578-00	3144-00	4800-00	960-00	→210-	5516-00	860-00	-	4800-00	900-00	-
15-	सूखेन्मुख कार्यक्रम	5885-00	1800-00	1800-00	1530-00	-	2250-00	1912-50	-	2250-00	1912-50	-
16-	ल०सी०क०उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता	547-00	1200-00	2000-00	--	-	2000-00	--	-	2000-00	--	-
17-	सहकारिता	316-00	230-00	404-00	--	-	399-00	--	-	537-00	--	-
18-	विद्युत	256-00	624-00	887-00	--	-	887-00	--	-	--	--	-
19-	ग्रामीण एवं लघुउद्योगी	2258-25	867-72	1415-00	130-00	-	1415-00	130-00	-	2008-80	638-00	-
20-	सड़क एवं पुल	18200-00	3621-00	3640-00	3138-00	3137-00	3640-00	3137-00	3137-00	3897-00	3367-00	3367-00
21-	पर्यटन	--	--	480-00	480-00	-	480-00	480-00	-	1000-00	1000-00	-
22-	सामान्य शिक्षा	7288-00	2242-00	1987-00	672-40	1364-00	1987-00	672-40	1364-00	2095-50	692-40	1905-50
23-	खेलकूद	564-74	291-77	332-00	218-00	-	332-00	218-00	-	1152-40	1000-20	-
24-	प्राविधिक शिक्षा	490-70	--	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-
25-	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य:-											
	1- सी०एम०ओ	--	2031-00	3018-00	800-00	1258-00	3018-00	800-00	1258-00	4890-00	4287-00	4300-00
	2- आयुर्वेद	371-70	25-00	243-00	--	-	243-00	243-00	-	823-00	120-00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26-	जलसंभूति ग्राम्यवि०	1384-33	300-00	--	--	-	--	--	-	250-00	--	250-
27-	जल निगम	11017-00	750-00	750-00	750-00	-	750-00	750-00	750-00	750-00	750-00	750-
28-	ग्रामीण आवास ग्राम्य विकास	843-00	153-00	--	--	-	--	--	-	200-00	--	200-
29-	सूचना	--	50-00	--	--	-	--	--	-	--	--	-
30-	श्रम कल्याण	--	--	104-00	--	-	104-00	--	-	--	--	-
31-	सेवायोजना	--	--	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	100-00	100-00	-
32-	शिल्पकार प्रशिक्षण	113-00	--	400-00	--	-	400-00	--	-	700-00	700-00	-
33-	अनुजाति/जनजाति कल्याण I	663-30	222-00	700-00	--	-	700-00	--	-	386-00	--	-
34-	समाज कल्याण	2556-90	1731-20	1775-00	--	-	1725-00	--	-	1805-00	--	-
35-	पुष्पाहार समाज कल्याण	--	912-00	2622-00	--	2622-00	2622-00	--	2622-00	2622-00	--	2622-00
योग:-		106552-52	33221-00	42899-00	15341-40	9131-00	44010-00	15723-90	9131-00	49014-00	23179-65	13394-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नई योजनाएं:-												
1-	पंचायत राज	--	--	--	--	--	0	--	200-00	200-00	--	--
2-	ग्राम्य विकास विभाग [ब्लॉक भवन]	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--	--
3-	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--	--
4-	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	--	--	--	--	--	--	--	710-00	606-00	--	--
5-	जलनिगम	--	--	--	--	--	--	--	750-00	750-00	--	--
6-	सेवायोजन	--	--	--	--	--	--	--	108-00	100-00	--	--
7-	शिल्पकार प्रशिक्षण	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--	--
योग नई योजना:-												
		--	--	--	--	--	--	--	4068-00	3956-00	--	--



:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
=====

:: जी.एन.-2 ::  
=====

विभाग का नाम:- कृषि ।

:: हजार रु०में ::

:: जनपद - झाँसी ::

क्र०सं०	योजना	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय				
		1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1- चालू योजना:-</b>												
<b>1- प्रदेश के जेदानी भागों में बीज विधायन संयंत्र की स्थापना</b>												
		116-80	135-00	70-00	-	-	70-00	-	-	75-00	-	-
<b>2- प्रदेश के जेदानी भागों में गणात्मक बीजों के संवर्द्धन संग्रहण एवं वितरण की योजना</b>												
		1194-60	507-00	662-00	340-00	-	662-00	340-00	-	800-00	640-00	-
<b>3- केन्द्र द्वारा पुरो-निर्धारित दलहन फसल के उत्पादन की योजना</b>												
		20-00	91-00	41-00	-	-	41-00	-	-	50-00	-	-
<b>4- प्रदेश 1 के जेदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवाके सुदृढीकरण की योजना ।</b>												
		170-00	108-00	110-00	100-00	-	110-00	100-00	-	125-00	125-00	-
<b>योग:-</b>		1501-40	841-00	883-00	440-00	-	883-00	440-00	-	1050-00	765-00	-

विभाग का नाम- उद्यान एवं फल उपभोग विभाग उ०प्र० ।

[हजार रु०में]

:: जनपद- झांसी ::

क्र०सं०	योजना	1980-85	1985-86	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1- चालू योजना:-</b>												
<b>1-171 वर्तमान उद्यानों के सुधार की योजना</b>												
	उत्पादन एवं जीज विधायनहकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	108-00	31-90	240-00	200-00	-	240-00	200-00	--	400-00	300-00	-
<b>2- प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन एवं जीज विधायनहकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण</b>												
	उत्पादन एवं जीज विधायनहकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	555-00	162-20	150-00	--	-	150-00	--	-	100-00	--	-
<b>3- प्रदेश के पूर्ण एवं अर्ध-पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की योजना ।</b>												
	उत्पादन एवं जीज विधायनहकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	199-00	46-30	80-00	--	-	80-00	--	-	100-00	--	-
<b>योग चालू नई योजना:-</b>												
	उत्पादन एवं जीज विधायनहकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	862-10	240-40	470-00	200-00	-	470-00	200-00	-	600-00	300-00	-
<b>योग चालू नई योजना +</b>												
	उत्पादन एवं जीज विधायनहकाइयों की स्थापना एवं सुदृढीकरण	862-10	240-40	470-00	200-00	-	470-00	200-00	-	600-00	300-00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
1- सामुदायिक कल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढीकरण की योजना ।												
		40-00	9-00	22-00	-	-	22-00	-	-	25-00	-	-
2- खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना ।												
		363-00	112-00	211-00	-	-	211-00	-	-	215-00	-	-
योग चालू योजना कल संरक्षण :-												
		403-00	120-00	233-00	-	-	233-00	-	-	240-00	-	-
नई योजना:-												
		5-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग उद्यान एवं कल संरक्षण :-												
		1265-10	360-40	703-00	200-00	-	703-00	200-00	-	840-00	350-00	-

101  
 :: वाजनाधार व्यय /परिव्यय ::  
 =====

:: जी०स०-2 ::  
 =====

विभाग का नाम:- कृषि विभाग

॥ हजार रु०में ॥

:: जनपद - झांसी ::

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय			1985-86 वास्तविक व्यय			1986-87 अनुमानित परिव्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1- चालू योजना:-													
1-केन्द्र परोन्धारित योजना के अन्तर्गत कृषि उपज के अडारण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर गुंभीण गोदाओं के निर्माण हेतु राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की सहायता अनुदान:-													
	योग चालू योजना:-	--	124-00	124-00	124-00	--	124-00	124-00	--	271-00	271-00	--	
	योग चर्ई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	योग चालू + चर्ई योजना :-	--	124-00	124-00	124-00	--	124-00	124-00	--	271-00	271-00	--	

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

: जी०एन०-२ ::

विभाग का नाम:- भूमि सुधार ।

हजार. रुमें। :: जनसं-श्रृंखला ::

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित परिव्यय पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	1986-87 अनुमानित व्यय पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना:-

तीलिंग से प्राप्त  
भूमि आयुक्तियों  
की वित्तीय  
सहायता

611-00

8-00

50-00

--

--

50-00

--

--

50-00

--

--

नोट:-

कोई भी नयी योजना प्रस्तावित नहीं है ।

विभाग का नाम:- निजी लघु सिंचाई विभाग ।

हजार रु०में : जनपद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85	1985-86	1986-87	अनुसूचित परिव्यय		1986-87	अनुसूचित व्यय		1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	नूजीगत	न्यूनतम आवेयकता कार्यक्रम	कुल	नूजीगत	न्यूनतम आवेयकता कार्यक्रम	कुल	नूजीगत	न्यूनतम आवेयकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:- 111 अनुदान:-												
अ- लघु सिंचाई द्वारा सामान्य कृषकों को अनुदान सुविधा		6271-00	1594-00	1327-00	-	-	1267-00	-	-	1500-00	-	-
ब- ब्लॉकिंग युनिटों से कृषकों को गहरा करने की योजना		--	87-00	140-00	-	-	140-00	-	-	200-00	-	-
त- पठारी क्षेत्रों की टयूबवेल निर्माण		--	253-00	550-00	-	-	550-00	-	-	600-00	-	-
द- निःशुल्क बोरिंग में अन्तर को अनुदान		--	40-00	--	--	--	40-00	-	-	100-00	-	-
योग अनुदान:-		6271-00	1979-00	2017-00	-	-	2017-00	-	-	2400-00	-	-
12- बोरिंग गोदावनिकाय		779-00	200-00	--	-	-	100-00	100-00	-	100-00	100-00	-
13- अन्य व्यय		1208-50	275-00	322-00	-	-	322-00	-	-	350-00	-	-
14- संयंत्र एवं उपकरण		--	45-00	--	-	-	46-00	-	-	100-00	-	-
योग चालू योजना:-		9258-50	2494-00	2385-00	-	-	2385-00	100-00	-	2950-00	100-00	-
नई योजना:-		--	--	--	-	-	--	--	-	--	-	-
योग चालू *नई योजना:-		9258-50	2494-00	2385-00	-	-	2385-00	100-00	-	2950-00	100-00	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

:: जी०एन०-२ ::

विभाग कान:- राजकीय लघु विंचाई ।

[हजार रु०में]

:: छनपद - श्रांती ::

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित परिव्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमानित व्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	अनुमानित व्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	अनुमानित व्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	अनुमानित व्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1- चालू योजनाएं :-													
राजकीय नलकप [सामान्य कार्यक्रम]													
		11786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	-	-
योग चालू योजना:-													
		11786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	-	-
2- नई योजनाएं:-													
		--	--	--	--	-	--	--	-	--	--	-	-
योग नई + चालू योजनाएं :-													
		11786-00	5075-00	3850-00	3850-00	-	3850-00	3850-00	-	2000-00	2000-00	-	-

1121  
 :: योजनावार व्यय /परिव्यय ::

:: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- भूमि एवं जल संरक्षण ।

[हजार रु०में]

:: जनपद - झांसी ::

क्र०सं०	योजना	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय				
		1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम					
1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाएँ :-												
प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि-सं-जल-संरक्षण-की-योजना :-												
1-भूमि संरक्षण इकाई झांसी	6089-00	1540-00	1400-00	--	--	400-00	--	--	2000-00	--	--	
2-भूमि संरक्षण इकाई डी. पी. ए. पी. गुरसराय	--	--	200-00	--	--	200-00	--	--	500-00	--	--	
योग चालू योजना:-	6089-00	1540-00	1600-00	--	--	1600-00	--	--	2500-00	--	--	
2- नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
योग चालू & नई योजना:-	6089-00	1540-00	1600-00	--	--	1600-00	--	--	2500-00	--	--	

नोट:-

इस जनपद में दो इकाईयाँ कार्य करती हैं एक सामान्य इकाई, दूसरी डी. पी. ए. पी. इकाई. दोनों में परिव्यय का वित्तवारा उ०नि०भू०स० झांसी की संस्तुति एवं कार्य वितरण के आधार पर किया गया है ।



विभाग का नाम:- पशुपालन ।

हजार रु०में : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुज्ञेदित परिव्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना:-

1- पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार की योजना ।	372-20	96-80	41-60	-	-	41-60	-	7-	227-80	200-00	-5
2- खरपका, संहपका रोगों की रोकथाम	--	4-00	2-00	-	-	2-00	-	-	4-00	--	--
3- पशुधन प्रक्षेत्र पर पुनर्जनन कार्य हेतु सांडों के उत्पादन की योजना	--	65-00	30-00	-	-	30-00	-	-	50-00	50-00	--
4- प्रदेश में कु०ग० ट्राय का सुदृढीकरण एवं विस्तार की योजना	10-50	46-00	37-20	-	-	37-20	-	-	54-00	--	--
5- अतिहिंसी कुर्त वीर्य द्वारा कु०ग० कार्यक्रम के सुदृढीकरण की योजना	--	125-00	320-00	-	-	320-00	-	-	188-00	--	--
6- नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों के सुदृढीकरण की योजना	--	183-00	125-00	-	-	125-00	-	-	102-00	--	--
7- संयुक्त राष्ट्र चालू आवासेनिधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहा सं. कुक्कुट उत्पादन की योजना	17-50	4-00	4-00	-	-	4-00	-	-	4-00	--	--

कुल:-----2-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8- राजा में भंड व चकरी प्रजनन सुविधाओं के प्रसार की योजना	54-80	9-30	10-00	-	-	10-00	-	-	-	9-00	-	-
9- भंड प्रजनन सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ी- करण तथा स्वास्थ्य सेवाओं में जन श्रणीकरण तथा विनयन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं प्रचार की योजना	94-50	39-10	126-50	-	-	126-50	-	-	-	110-00	-	-
11- सुअर प्रजनन सुवि- धाओं का प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना	242-00	194-00	342-00	-	-	342-00	-	-	-	272-00	100-00	-
12- पशुधन विकास त्वधी प्रसार कार्यक्रम की योजना	9-40	12-78	13-70	-	-	13-70	-	-	-	8-00	-	-
13- चारा/चारा बीज चारागाहों के विकास की योजना	372-30	19-00	24-00	-	-	24-00	-	-	-	10-00	-	-
योग चालू योजनाएँ	1173-20	802-38	1031-00	-	-	1081-00	-	-	-	1050-00	100-00	-

विभाग का नाम:- मत्स्य पालन ।

हजार रुपें।

: जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुगोदित पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	परिव्यय	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	व्यय	1987-88 कुल	हेतु पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	प्रस्तावित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना :-												
	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	104-93	--	450-00	--	--	450-00	--	--	360-00	--	--
	योग चालू योजना :-	104-93	--	450-00	--	--	450-00	--	--	360-00	--	--
2- नई योजना:-												
	योग चालू + नई योजना:-	104-93	--	450-00	--	--	450-00	--	--	360-00	--	--

विभाग का नाम:- वन विभाग ।

हजार रु 0में।

: जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित पूँजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत	व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु	गृस्तापित पूँजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1- चालू योजनाएं:-</b>												
1-	ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्राप्ति का सुचारुकरण	1989-00	850-00	750-00	100-00	--	750-00	100-00	--	750-00	100-00	--
2-	संचार साधन	134-00	--	40-00	20-00	--	40-00	20-00	--	60-00	60-00	--
3-	वन अनोरजन विभा केन्द्र की स्थापना	240-00	--	100-00	30-00	--	100-00	30-00	--	100-00	100-00	--
4-	भवन	121-00	--	100-00	60-00	--	100-00	60-00	--	180-00	180-00	--
5-	वन कार्यचारियों को पेपजल विद्युत सुविधा तथा टो गिगा मजदूरी/कृषकों को सुविधाएं	172-00	35-00	50-00	30-00	--	50-00	30-00	--	100-00	100-00	--
6-	सांसाजिक बानिकी	--	710-00	1800-00	830-00	--	1800-00	830-00	--	800-00	300-00	--
7-	शहरी क्षेत्रों में सांसाजिक बानिकी	50-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>योग चालू योजना:-</b>		<b>2706-00</b>	<b>1595-00</b>	<b>2840-00</b>	<b>1070-00</b>	<b>--</b>	<b>2840-00</b>	<b>1070-00</b>	<b>--</b>	<b>1990-00</b>	<b>840-00</b>	<b>--</b>
<b>2- नई योजना:-</b>												
<b>योग चालू + नई योजना:-</b>		<b>2706-00</b>	<b>1595-00</b>	<b>2840-00</b>	<b>1070-00</b>	<b>--</b>	<b>2840-00</b>	<b>1070-00</b>	<b>--</b>	<b>1990-00</b>	<b>840-00</b>	<b>--</b>

विभाग का नाम:- पंचायतराज ।

[हजार रुपये] : जनपद - झांझी :

क्र०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	परिव्यय	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	हेतु पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	पुस्तकित पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाएँ :-												
	1-पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायकता	35-50	27-00	15-00	-	-	15-00	-	-	20-00	-	-
	2-पंचायतराज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु उन्हें आव. में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन ।	21-00	06-00	06-00	-	-	06-00	-	-	06-00	-	-
	3-गांधीय प्रयासों में स्वच्छता हेतु खड्जा तथा नाली का निर्माण ।	645-00	350-00	350-00	-	-	350-00	-	-	350-00	-	-
	4- पंचायत भवनों का निर्माण	83-50	250-00	250-00	250-00	-	250-00	250-00	-	200-00	200-00	-
	5- हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार हेतु याचिकाओं को अनुदान ।	50-00	69-00	25-00	-	-	25-00	-	-	30-00	-	-
	6- पंचायत उद्योगों की कार्य-शाला भवन निर्माण	--	50-00	100-00	100-00	-	100-00	100-00	-	50-00	50-00	-
	<b>योग चालू योजना:-</b>	<b>835-00</b>	<b>752-00</b>	<b>746-00</b>	<b>350-00</b>	<b>-</b>	<b>746-00</b>	<b>350-00</b>	<b>-</b>	<b>656-00</b>	<b>250-00</b>	<b>-</b>
2- नई योजना :- [जिला केन्द्र पर]												
	पंचायत भवनों का निर्माण	--	--	--	--	--	--	--	--	200-00	200-00	--
	<b>योग नई योजना:-</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>200-00</b>	<b>200-00</b>	<b>--</b>
	<b>योग चालू + नई योजना:-</b>	<b>835-00</b>	<b>752-00</b>	<b>746-00</b>	<b>350-00</b>	<b>--</b>	<b>746-00</b>	<b>350-00</b>	<b>--</b>	<b>856-00</b>	<b>450-00</b>	<b>--</b>

:: योजनाएं/परिचय ::

:: जी०एन०-२ ::

विभाग का नाम:- प्रादेशिक विकास दल ।

[हजार रु०में]

: जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित पूँजीगत	परिचय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत	व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	हेतु पूँजीगत	प्रस्तावित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाएं :-												
1-	स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण	--	38-00	50-00	--	--	50-00	--	--	109-95	--	--
2-	युवक संगल दलों को प्रोत्साहन	15-00	40-00	50-00	--	--	50-00	--	--	60-00	--	--
3-	युवक संगल दल सेमिनार	3-30	5-00	5-00	--	--	5-00	--	--	10-00	--	--
4-	सेवाज सेवा कार्य शिबिर	--	--	5-00	--	--	5-00	--	--	4-00	--	--
5-	प्रकीर्ण व्यय	0-20	4-00	10-00	--	--	10-00	--	--	12-00	--	--
6-	ग्रामीण युवकों को व्यवसायिक शिक्षण	8-30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7-	ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन ।	68-40	9-00	10-00	--	--	10-00	--	--	13-00	--	--
8-	ग्रामीण क्षेत्र में व्यावसायिक प्रोत्साहन	63-00	20-00	40-00	--	--	40-00	--	--	100-00	400-00	--
9-	प्रसदास कार्य	--	--	20-00	--	--	20-00	--	--	25-00	--	--
10-	युवकों का तैराकी प्रशिक्षण	00-80	--	10-00	--	--	10-00	--	--	10-00	--	--
योग चालू योजना:-		159-00	116-00	200-00	--	--	200-00	--	--	343-95	100-00	--
2- नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग नई + चालू योजना:-		159-00	116-00	200-00	--	--	200-00	--	--	343-95	100-00	--

1197  
 :: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
 =====

:: जी०स०-2 ::  
 =====

गाँव विभाग का नाम :- विकास विभाग, ब्लाक भवन		हजार रु में										
क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
1	2	3	4	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
योग चालू योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2- नई योजना:-												
जिला विकास कार्यालयों के विकास खण्डों में भवनों का निर्माण तथा विकृदीकरण हाथपासीय भवन		--	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--
योग नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--
योग नई + चालू योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	1500-00	1500-00	--

विभाग का नाम:- क्षेत्रीय विकास ।

₹हजार रुमें

: जनपद - झारखी :

क्र.सं०	योजना	1985-86	1985-86	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I- चालू योजना:-												
अ	एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम	12528-00	3144-00	4800-00	960-00	--	5516-00	860-00	--	4800-00	900-00	--
ब	लघु सिंचाई कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता	547-00	1200-00	2000-00	--	--	2000-00	--	--	2000-00	--	--
स	सूखान्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5895-00	1800-00	1800-00	1530-00	--	2250-00	1912-50	--	2250-00	1912-50	--



विभाग का नाम:- सहकारिता ।

हजार रुपों

: जनपद स्तरी :

क्र०सं०	योजना	1980-85	1985-86	1986-87 अनुसूचित परिव्यय			1986-87 अनुसूचित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवस्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवस्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवस्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-चालू योजनाएँ:-												
1- सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना:-												
अ-	जिला सहकारी बैंक की शाखाओं हेतु प्रबंधकीय अनुदान ।	32-00	-	24-00	-	-	24-00	-	-	32-00	-	-
ब-	जिला सहकारी बैंक की शाखाओं के नवीनीकरण हेतु ऋण	--	-	10-00	-	-	10-00	-	-	5-00	-	-
स-	नियमित ऋण में अतिरिक्त उ० ऋण पर अतिरिक्त फंड हेतु अनुदान	50-00	-	--	-	-	--	-	-	--	-	-
द-	अनुसूचितों के लोगों को सवि- रहित ऋण हेतु व्याज रहित ऋण	60-00	50-00	50-00	-	-	50-00	-	-	50-00	-	-
2- कृषि विज्ञान योजना 3-												
अ-	कृषि विज्ञान संस्थानों के खाद्यान्न व्यय- सहाय हेतु सार्वजनिक भूखंड	24-00	-	--	-	-	--	-	-	--	-	-
ब-	जिला सहकारी संघों को उपररक व्य- यसहाय हेतु सार्वजनिक भूखंड	--	105-00	165-00	-	-	165-00	-	-	300-00	-	-
स-	कृषि विज्ञान संस्थानों के मूल्य के उत्तार-चढ़ाव निधि हेतु अनुदान	--	-	5-00	-	-	--	-	-	--	-	-

कुल:- 2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3- सहकारी उपभोक्ता योजना:-												
अ- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता व्यवसाय हेतु कार्जिन बनी												
		150-00	75-00	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
योग चालू योजना:-												
		316-00	230-00	404-00	-	-	399-00	-	-	537-00	-	-
2- नई योजना:-												
योग चालू + नई योजना :-												
		316-00	230-00	404-00	-	-	399-00	-	-	537-00	-	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
=====

:: जी०एन०-2 ::  
=====

विभाग का नाम:- विद्युत ।

हजार रुपों।

जनसद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित परिव्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमानित व्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	हेतु प्रस्तावित परिव्यय सूजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना :-

ग्रामीण विद्युतीकरण राज्  
साजान्य कार्यक्रम ।

256-07	624-00	887-00	-	887-00	887-00	-	887-00	-	-	-	-	-
--------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

योग चालू योजना:-

256-07	624-00	887-00	-	887-00	887-00	-	887-00	-	-	-	-	-
--------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

2- नई योजना :-

--	--	--	-	--	--	-	--	-	-	-	-	-
----	----	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---	---

योग नई + चालू योजना:-

256-07	624-00	887-00	-	887-00	887-00	-	887-00	-	-	-	-	-
--------	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---	---	---

विभाग का नाम:- ग्रामीण एवं लघु उद्योग ।

हजार रु में।

: जनपद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1985-86		1986-87 अनुमानित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाएं:-												
लघु उद्योगों की सहायता :-												
1-	जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से मार्जिन बनी ऋण ।	535-00	200-00	100-00	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-
2-	एकीकृत मार्जिनबनी ऋण	--	--	400-00	-	-	400-00	-	-	500-00	-	-
3-	बैले/प्रदर्शनी	--	10-00	25-00	-	-	25-00	-	-	25-00	-	-
4-	उद्यमकता विकास प्रशिक्षण एवं शोध ग्रामीण उ०केन्द्र	--	19-35	36-00	-	-	36-00	-	-	50-00	-	-
5-	चीनीघात्र विकास केन्द्र झांसी	600-00	400-00	550-00	130-00	-	550-00	130-00	-	662-00	230-00	-
6-	हथकरघा अंश पूँजी ऋण	884-05	114-97	150-00	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-
7-	हथकरघाप्रसंधकीय सहायता	167-30	23-40	54-00	-	-	25-00	-	-	21-00	--	-
8-	हथकरघों का आधुनिकीकरण	112-90	100-00	100-00	-	-	100-00	-	-	100-00	-	-
योग चालू योजना:-		2299-25	867-72	1415-00	130-00	-	1415-00	130-00	-	1600-00	230-00	-
2- नई योजना:-												
औद्योगिक आस्थान		--	--	--	-	-	--	-	-	400-00	400-00	-
योग नई योजना:-		--	--	--	-	-	--	-	-	400-00	400-00	-
योग नई + चालू योजना:-		2299-25	867-72	1415-00	130-00	-	1415-00	130-00	-	2000-00	630-00	-

विभागा का नाम:- तार्वजनिक निर्माण विभाग ।

1 जनपद - झांसी ।

1 हजार रु० में ।

क्र०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित परिव्यय पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	अनुमानित व्यय पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	हेतु प्रस्तावित परिव्यय पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजना:-												
जिला एवं अन्य मार्ग हेतु निर्माण तथा												
मार्गों का पुनः निर्माण :-												
क- मार्गों का पुनः निर्माण:-												
1-	मुख्य जिला मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2-	अन्य जिला मार्ग	--	391-00	391-00	391-00	391-00	391-00	391-00	--	--	--	--
3-	ग्रामीण मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-	अन्य विभागों के मार्ग नहर पटवर्दी	--	290-00	290-00	290-00	290-00	290-00	290-00	--	--	--	--
योग पुनः निर्माण		--	681-00	681-00	681-00	681-00	681-00	681-00	--	--	--	--
ख- लघु हेतु :-												
1-	30मी० स्थान तक	--	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	1100-00	1100-00	1100-00	--
2-	ग्रामीण मार्ग न्यून आवाज	--	2056-00	2056-00	2056-00	2056-00	2056-00	2056-00	2267-00	2267-00	2267-00	--
कुल योग चालू योजना		8200-00	3327-00	3137-00	3137-00	3137-00	3137-00	3137-00	3367-00	3367-00	3367-00	--
अधिष्ठान व्यय:-		--	503-00	--	--	503-00	--	--	530-00	--	--	--
महा योग:-		18200-00	3147-00	3640-00	3137-00	3137-00	3640-00	3137-00	3897-00	3367-00	3367-00	--

विभाग का नाम:- सार्वजनिक निर्माण विभाग ।

हजार रु०में

:जनपद - झाँसी:

क्र०सं०	योजना	1980-85	1985-86	1986-87 अनुसूचित परिव्यय			1986-87 अनुज्ञानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजनाएँ:-

ग्रामीण मार्ग-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम:-

1-रक्षा राजापुर मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	50	50	50
2-रक्षा अम्बाबाघ मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	200	200	200
3-तिररधा लिंक मार्ग	--	--	15	15	15	15	15	15	--	--	--
4-रेवन-वेरवई मार्ग	--	--	15	15	15	15	15	15	--	--	--
5-दुगारा अभनपुर मार्ग	--	--	20	20	20	20	20	20	--	--	--
6-मथुरापुरा-गढ़ियाकाटक	--	--	--	--	--	--	--	--	105	105	105
7- पठा कटोरा मार्ग पर लघुसेतु का निर्माण	--	--	400	400	400	400	400	400	100	100	100
8-चिजना-झंगरा रोस्टेड मार्ग पर लघु सेतु	--	--	--	--	--	--	--	--	1000	1000	1000
9-बडागाँव भस्नेह मार्ग	--	--	150	150	150	150	150	150	--	--	--
10-तिररधा लिंक मार्ग	--	--	150	150	150	150	150	150	--	--	--
11-बकवाँ शाहजहाँपुर मार्ग	--	--	250	250	250	250	250	250	--	--	--
12-खैनी बाजौर मार्ग	--	--	56	56	56	56	56	56	300	300	300
13-बाजौर-गढ़वई मार्ग	--	--	56	56	56	56	56	56	--	--	--

कुल:-2-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14-गुरतरांच-जोठलिक मार्ग	--	--	--	19	19	19	19	19	19	--	--	--
15-,, ,, ,, ,,	--	--	--	20	20	20	20	20	20	--	--	--
16-समथर-पीपरी किला मार्ग	--	--	--	384	384	384	384	384	384	--	--	--
17-सेरसा केनाल घटरी	--	--	--	910	910	910	910	910	910	600	600	600
18-जोठ बंधरा, गुरतरांच 19कि०मी०	--	--	--	21	21	21	21	21	21	--	--	--
19-जोठ-भाडेर मार्ग	--	--	--	290	290	290	290	290	290	--	--	--
20-जोठ-बंधरा गुरतरांच 17 कि०मी०	--	--	--	220	220	220	220	220	220	--	--	--
21-ककवा शाहजहापुर मार्ग	--	--	--	110	110	110	110	110	110	--	--	--
22-बसोवई चेतना मार्ग	--	--	--	51	51	51	51	51	51	--	--	--
23-समथर-धोरका मार्ग	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1012	1012	1012
योग चालू योजना:-	1	20200	3447	3640	3137	3137	3652	3137	3137	3897	3367	3367

विभाग का नाम:- पर्यटन विभाग 1

[हजार रु०में] : जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित पूँजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमोदित पूँजीगत	व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	हेतु प्रस्तावित पूँजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1- चालू योजना :-</b>												
<b>स्थानीय पर्यटन विकास:-</b>												
अ	लक्ष्मीताल का विकास एवं जल प्रदूषण रोकना	--	--	250-00	250-00	--	250-00	--	--	600-00	600-00	--
ब	झंडी समिति झाँसी से महाराजा गंगाधरराव की छतरी तक सड़क निर्माण ।	--	--	230-00	230-00	--	230-00	--	--	--	--	--
स	झाँसी बड़ी समिति से नारायण बाग तक के मार्ग का विद्युतीकरण	--	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--
<b>योग चालू योजना:-</b>		--	--	480-00	480-00	--	480-00	--	--	1000-00	1000-00	--
<b>2- नई योजना:-</b>												
<b>योग चालू + नई योजना:-</b>		--	--	480-00	480-00	--	480-00	--	--	1000-00	1000-00	--



129  
 :: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
 =====

:: जी०एन०-2 ::  
 =====

विभाग का नाम:- साजान्य शिक्षा 2

[हजार रूपये]

: जनसद - इाती :

क्र०सं०	योजना	1985-86	1986-87	1987-88 अनुमोदित परिव्यय			1988-89 अनुमोदित व्यय			1989-90 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यक्ता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यक्ता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यक्ता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजनायें:-

शिक्षा विभाग :-

1- ग्रामीण तथा नगर में भवन रहित जूनियर पब्लिक स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान-60101001	713-00	253-00	258-00	258-00	258-00	258-00	258-00	258-00	258-00	258-00	258-00	258-00
2- अतिहायिक मान्यता प्राप्त असासकीय सी०वे०स्कूलों को अनुदान 60101005	794-00	174-00	190-00	--	190-00	190-00	--	190-00	200-00	--	200-00	200-00
3- ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी०वे०स्कूलों के भवन निर्माण हेतु अनुदान 60101005	1063	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00	157-00
4- ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित ज०वे०स्कूलों को खोलने हेतु अनुदान 60101006	1005-00	175-00	39-00	--	39-00	39-00	--	39-00	39-00	--	39-00	39-00
5- नगर क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं के ज०वे०स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101007	336-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

कुल: ----2----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6-	जनियर वेणुस्कूल में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान 60101007	30-00	--	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00
7-	गाामीण क्षेत्रों में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्मूल वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं हेतु प्रोत्साहन अनुदान 60101009	46-00	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00
8-	नगर एवं गाामीण क्षेत्र में बय वर्ग 6-14 के बच्चों के लिये अकादमिक कक्षाओं खोलने हेतु अनुदान 60101011	932-00	667-00	716-00	--	716-00	716-00	--	716-00	716-00	--	716-00
9-	गाामीण क्षेत्रों में बालक एवं बालिकाओं के ली० वेणुस्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101010	1441-00	520-00	379-10	157-00	222-10	379-10	157-00	222-10	379-10	157-00	379-10
10-	प्रत्येक जिले में जिला वेणु शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सुदृढीकरण 60101013	35-00	--	16-00	--	16-00	16-00	--	16-00	16-00	--	16-00
11-	प्रदेश के प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 15/= प्रति माह की दरसे 3 वर्ष के लिये योग्यता छात्रवृत्ति 60101017	82-00	27-00	30-00	--	30-00	30-00	--	30-00	30-00	--	30-00
12-	पेरिक स्कूल के अध्यापकों को दक्षता पुरस्कार 60101020	11-00	4-00	4-00	--	4-00	4-00	--	4-00	5-00	--	5-00

कुम्भा: ---3---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13-	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उप- लब्ध कराने तथा सी.वे.के. स्कूलों में पाठ्यपुस्तक स्था- पित करने हेतु अनुदान - 60101022	100-00	--	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00	10-00	--	10-00
14-	ग्रामीण क्षेत्र में सी.वे.के.स्कूलों को साज-सज्जा हेतु अनुदान 60101024	56-00	45-00	45-00	--	45-00	45-00	--	45-00	45-00	--	45-00
15-	जी.वे.के.स्कूलों में साज-सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान 60101025	98-00	--	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00
16-	निर्धन वर्ग के बच्चों को पोशाक की व्यवस्था 60101026	56-00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17-	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी.नि.ए.के.वि.के.स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान 60101034	60-00	15-00	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00	15-00	--	15-00
18-	अरेबिक मदरसों को अनु- रक्षण एवं विकास अनुदान 60108003	99-00	--	2-00	--	2-00	2-00	--	2-00	2-00	--	--
19-	खेलकूद तथा अन्य विद्यालयों के बाहर शैक्षिक-कार्यक्रमों तथा युवकों के कल्याण हेतु प्राविधान	34-00	15-00	17-00	--	17-00	17-00	--	17-00	17-00	--	17-00
20-	30मा.विद्यालयों से बाल- चर योजना का प्रसार	11-00	6-00	2-00	--	--	2-00	--	--	2-00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21-वर्तमान पाठ्यपुस्तकालयों का विकास तथा नये जिला पुस्तकालयों की स्थापना	250-00	150-00	150-00	100-00	--	--	150-00	100-00	--	150-00	100-00	--
22-सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास अनुदान	5-00	5-00	5-00	--	--	--	5-00	--	--	5-00	5-00	--
23-संस्कृत पीठशाला को विकास अनुदान	2-00	6-00	15-5	--	--	--	15-50	--	--	6-00	6-00	--
24-राज्य विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण तथा विशेष परम्परा	19-00	8-00	8-00	--	--	--	8-00	--	--	8-00	8-00	--
योग प्राथमिक:-	331-00	190-00	197-50	100-00	--	--	197-50	100-00	--	188-00	119-00	--
योग वैदिक प्राथमिक:-	7288-00	2242-00	2134-50	672-40	1364-00	2134-00	672-40	1364-00	2095-50	691-40	1905-50	--
2- नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग नई + चालू योजना:-	7288-00	2242-00	2134-00	672-40	1364-00	2134-00	672-40	1364-00	2095-50	692-40	1905-50	--



:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

:: जी०एच०-२::

विभाग का नाम:- प्राविधिक शिक्षा ।

₹हजार ₹०में₹

: जनपद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1880-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाएँ :-												
	1- पॉलीटेक्नीक का सुदृढीकरण	254-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-
	डा. देवसी फाउंड का कार्यक्रमों का प्रारम्भ करना											
	2- पॉलीटेक्नीको का विस्तार:-											
	11 साज-सज्जा की आधुनिकीकरण	211-00	-	60-00	60-00	-	60-00	60-00	-	150-00	150-00	-
	12 विद्यार्थियों को सुविधा	--	--	--	--	--	--	--	--	56-00	18-00	--
	13 पुस्तकालय का सुदृढीकरण	25-70	--	20-00	20-00	--	20-00	20-00	--	62-55	62-55	--
	14 विस्तार योजना के अन्तर्गत भवन	--	--	--	--	--	--	--	--	610-00	610-00	--
	योग चालू योजना:-	490-00	--	230-00	230-00	--	230-00	230-00	--	988-55	988-55	--
	2- नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	योग चालू + नई योजना:-	490-70	--	230-00	230-00	--	230-00	230-00	--	988-55	988-55	5

विभाग का नाम:- प्राविधि शिक्षा ।

हजार रु०में : जनपद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1880-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय कुल	पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल	पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय कुल	पूँजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनायें :-												
1-	पॉलीटेक्नीक का सुदृढीकरण	254-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-	150-00	150-00	-
डा. वैसी फाईड कार्यक्रमों का प्रारम्भ करना												
2-	पॉलीटेक्नीक का विस्तार:-											
11	साज-सज्जा की आधुनिकीकरण	211-00	-	60-00	60-00	-	60-00	60-00	-	150-00	150-00	-
12	विद्यार्थियों को सुविधा	--	--	--	--	--	--	--	--	16-00	16-00	--
13	पुस्तकालय का सुदृढीकरण	25-70	-	20-00	20-00	-	20-00	20-00	-	62-55	62-55	-
14	विस्तार योजना के अन्तर्गत भवन	--	--	--	--	--	--	--	--	610-00	610-00	--
योग चालू योजना:-		490-70	-	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-
2- नई योजना:-												
योग चालू + नई योजना:-		490-70	-	230-00	230-00	-	230-00	230-00	-	988-55	988-55	-

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
=====

: जी०एन०-२ :  
=====

विभाग का नाम :- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य ।

हजार रु०में

: जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित पूँजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत	व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु कुल	प्रस्तावित पूँजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1- चालू योजनाएँ :-												
1-	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	-	-	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	900-00	900-00	900-00
2-	उप केन्द्रों के भवन निर्माण	-	242-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	400-00	290-00	1000-00	1800-00
3-	नये प्रा०स्वा०केन्द्रों की स्थापना	-	-	130-00	-	130-00	130-00	-	130-00	500-00	-	500-00
4-	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	-	-	328-00	-	328-00	328-00	-	328-00	1100-00	1100-00	1100-00
5-	क्षयरोग निरीक्षक औषधियाँ	-	50-00	60-00	-	-	60-00	-	-	राज्य सेक्टर में हस्तांतरित		
6-	मेलरिया नियंत्रण	-	1697-00	1700-00	-	-	1700-00	-	-	-	-	-
7-	सब्जीडियरी हेल्थ सेन्टर	-	42-00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग सी०एम०ओ०की योजनाएँ-		-	2031-00	3018-00	800-00	1258-00	3028-00	800-00	1258-00	4300-00	3800-00	4300-00

--: आयुर्वेदिक :-  
=====

8-	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये आयु०एवं युनानी चिकि०की स्थापना	310-00	25-00	60-00	-	-	60-00	-	-	240-00	-	-
9-	शहरी क्षेत्रों में नये आयु०/युनानी चिकि०की स्थापना	-	-	150-00	-	-	150-00	-	-	400-00	-	-

क्रमशः ---2---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19-वर्तमान आर्यु/युनानी चिकित्सा तथा औषधालयों का प्रोन्नतयन एवं उनकी स्थिति में सुधार		60-80	--	33-00	--	--	33-00	--	--	63-00	--	--
योग आर्यु/युनानी:-		371-10	21-00	243-00	--	--	243-00	--	--	703-00	--	--
योग चालू योजना:-		371-00	231-00	3261-00	800-00	1258-00	3261-00	800-00	1258-00	5003-00	3800-00	4300-00
2-नई योजना:-												
1-चीरघर का निर्माण		--	--	--	--	--	--	--	--	300-00	300-00	--
2-अस्पतालों में विशिष्ट उपचार सेवाओं की व्यवस्था दन्त रूजालय		--	--	--	--	--	--	--	--	60-00	--	--
3-शहरी/ग्रामीण होस्पिटल औषधालयों की स्थापना		--	--	--	--	--	--	--	--	30-00	--	--
4-अस्पतालों में साजसज्जा एवं अन्य आवश्यक सामग्री डीजल जनरेटर की व्यवस्था		--	--	--	--	--	--	--	--	200-00	186-00	--
5-राजकीय आर्यु/युनानी चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण		--	--	--	--	--	--	--	--	120-00	120-00	--
योग नई योजना:-		--	--	--	--	--	--	--	--	710-00	606-00	--
योग नई + चालू योजना:-		371-00	231-00	3261-00	800-00	1258-00	3261-00	800-00	1258-00	5713-00	4406-00	4300-00



विभाग का नाम:- ग्रामीण हरिजन पेयजल ग्राम्य विकास विभाग ।

हजार रुपें।

: जनपद-झांसी:

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 कुल	अनुमोदित पूँजीगत परिव्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 कुल	अनुमानित पूँजीगत व्यय	अन्यतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 कुल	हेतु प्रस्तावित पूँजीगत परिव्यय	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
---------	-------	-----------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------	---------------------------------------	----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1- चालू योजना:-

ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना	1384-33	300-00	--	--	--	--	--	--	--	250-00	--	250-00
---------------------------	---------	--------	----	----	----	----	----	----	----	--------	----	--------

योग चालू योजना:-	1384-33	300-00	--	--	--	--	--	--	--	250-00	--	250-00
------------------	---------	--------	----	----	----	----	----	----	----	--------	----	--------

2- नई योजना :-

योग नई + चालू योजना:-	1384-33	300-00	--	--	--	--	--	--	--	250-00	--	250-00
-----------------------	---------	--------	----	----	----	----	----	----	----	--------	----	--------

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
-----

:: जी०एन०-2 ::  
-----

विभाग का नाम:- ग्रामीण आवास ग्राम्य विकास विभाग ।

[हजार रु०में]

: जनपद - झांसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1987-87 अनुमोदित कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	परिव्यय	1986-87 अनुमानित व्यय कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित कुल पूंजीगत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	परिव्यय
---------	-------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------	---------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

1- चालू योजना:-

ग्रामीण आवास		843-00	153-00	--	--	--	--	--	--	200-00	--	200-00
--------------	--	--------	--------	----	----	----	----	----	----	--------	----	--------

योग चालू योजना:-		843-00	153-00	--	--	--	--	--	--	200-00	--	200-00
------------------	--	--------	--------	----	----	----	----	----	----	--------	----	--------

2- नई योजना:-

योग नई + चालू योजना:-		843-00	153-00	--	--	--	--	--	--	200-00	--	200-00
-----------------------	--	--------	--------	----	----	----	----	----	----	--------	----	--------

:: योजनावार व्यय/परिव्यय ::

:: जी०एन०-2 ::

विभाग का नाम:- सूचना विभाग ।

॥ हजार रु०में ॥

: जनपद- झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुसूचित कुल पूंजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित कुल पूंजीगत	व्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित कुल पूंजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना:-

तहसील सूचना कार्यालयों  
की स्थापना

--

50,700

--

--

--

--

--

--

--

--

--

नोट:- वर्ष 1987-88 हेतु कोई योजना परिव्यय नहीं मांगा गया ।

141  
 :: योजनावार व्यय/परिव्यय ::  
 =====

:: जी०एन०-2 ::  
 =====

विभाग का नाम:- श्रम विभाग ।

[हजार रु०में]

: जनपद-झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85	1985-86	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना :-

1- नये श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना तथा निर्माण

-- -- 94-00 -- -- 94-00 -- -- -- --

2- अवसक्त बंधुआ श्रमिकों का पुर्निवास

-- -- 10-00 -- -- 10-00 -- -- -- --

योग चालू योजना:-

-- -- 104-00 -- -- 104-00 -- -- -- --

2-नई योजना:-

-- -- -- -- -- -- -- --

योग नई + चालू योजना:-

-- -- 104-00 -- -- 104-00 -- -- -- --

नोट:-

इस विभाग के झाँसी स्थिति अधिकारी ने कोई योजना माँग 87-88 हेतु प्रस्तुत नहीं की ।

विभाग का नाम:- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन

हजार रुमें

: जनपद-झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना:-

1- सेवायोजन कार्यालय का

सुदृढीकरण/भवन निर्माण

-	-	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	-	-	-	-	-
---	---	--------	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

योग चालू योजना:-

-	-	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	-	-	-	-	-
---	---	--------	--------	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---

2- नई योजना:-

सेवायोजन कार्यालय

का सुदृढीकरण/जीप

की व्यवस्था

-	-	-	-	-	-	-	-	-	100-00	100-00	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---

योग नई योजना:-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	100-00	100-00	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	--------	---	---

योग चालू + नई योजना:-

-	-	400-00	400-00	-	400-00	400-00	-	100-00	100-00	-	-	-
---	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	---	---

नोट:- निर्माण स्वतः सुविधा न हो पाने के कारण वर्ष 1987-88 हेतु परिव्यय नहीं रखा गया।

भूखण्ड विकास हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

विभाग का नाम:- शिक्षाकार प्रशिक्षण

₹ हजार रु० में

: जनपद - झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित कुल पूंजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1986-87 अनुमानित व्यय कुल पूंजीगत	1987-88 हेतु प्रस्तावित कुल पूंजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1987-88 हेतु प्रस्तावित कुल पूंजीगत	परिव्यय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालू योजना:-

वर्तमान प्रो०प०सं० का विस्तार एवं सुदृढीकरण	113-00	--	400-00	--	--	400-00	--	--	300-00	300-00	--
------------------------------------------------	--------	----	--------	----	----	--------	----	----	--------	--------	----

योग चालू योजना:-	113-00	--	400-00	--	--	400-00	--	--	300-00	300-00	--
------------------	--------	----	--------	----	----	--------	----	----	--------	--------	----

2- नई योजना:-

वर्तमान ओ०प०सं० में सबनों की बाँड डी बाल का निर्माण	--	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--
-----------------------------------------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----

योग नई योजना:-	--	--	--	--	--	--	--	--	400-00	400-00	--
----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----

योग नई + चालू योजना:-	113-00	--	400-00	--	--	400-00	--	--	700-00	700-00	--
-----------------------	--------	----	--------	----	----	--------	----	----	--------	--------	----



विभाग का नाम:- हरिजन एवं समाज कल्याण अनुजाति एवं पिछड़ी जाति कल्याण हजार रूपैः : जनपद- झारखण्ड

क्र.सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय		
				कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1- चालु योजना:-

1- अनुजाति शिक्षा:-

1.1 छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनुवर्तक सहा

अ- कक्षा 6 से 8 तक के अनुजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

1- निर्धनता के आधार पर	174-90	60-00	75-00	-	-	75-00	-	-	85-00	-	-
2- योग्यता के आधार पर	--	45-00	50-00	-	-	50-00	-	-	60-00	-	-

ब- कक्षा 1 से 5 तक के अनुजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

1- निर्धनता के आधार पर	--	35-00	40-00	-	-	40-00	-	-	43,00	-	-
2- योग्यता के आधार पर	--	35-00	40-00	-	-	40-00	-	-	43,00	-	-

1.2 अनुजाति के छात्रों को अपर-सुन्ती काफिट अनुदान -60-00 14-00 20-00 - - 20-00 - - 25-00 - -

1.3 पब्लिक क्लो में पढ़ने वाले मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति = -- -- 10-00 - - 10-00 - - 10-00 - -

1.4 बुक बैंक की स्थापना 21-90 5-00 5-00 - - 5-00 - - 7-00 - -

1.5 दशम एवं वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार 40-00 5-00 5-00 - - 5-00 - - 7-00 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	विभाग द्वारा सहायता प्राप्त प्रा०पा०पुस्तकालय एवं छात्रावास अनुदान	--	--	20-00	--	--	20-00	--	--	20-00	--	--
17	अनु०जाति के छात्रों की पाठ्य पुस्तकीय अनावर्ती सहायता											
	1- प्राइमरी स्तर पर											
	1- निर्धनता के आधार पर	--	--	6-00	--	--	6-00	--	--	7-00	--	--
	2- योग्यता के आधार पर	--	--	6-00	--	--	6-00	--	--	7-00	--	--
	12 विमुक्त जाति कल्याण:-											
	15 जुनियर हा०स्कूल स्तर तक											
	1- निर्धनता के आधार पर	--	1-00	3-00	--	--	3-00	--	--	3-00	--	--
	2- योग्यता के आधार पर	--	0-50	3-00	--	--	3-00	--	--	3-00	--	--
	1- प्राइमरी स्तर पर											
	1- निर्धनता के आधार पर	--	1-00	3-00	--	--	3-00	--	--	3-00	--	--
	2- योग्यता के आधार पर	--	0-50	3-00	--	--	3-00	--	--	3-00	--	--
8	विमुक्त जाति कुटीर उद्योग अनु०	42-00	--	31-00	--	--	31-00	--	--	35-00	--	--
9	विमुक्त जाति कृषि बाग-वानी	31-00	--	20-00	--	--	20-00	--	--	25-00	--	--
10	गृह निर्माण अदायगी आवास	87-5	--	360-00	--	--	360-00	--	--	--	--	--
	योग अनु०जाति कल्याण:-	463-30	222-00	700-00	--	--	700-00	--	--	386-00	--	--

विभाग का नाम:- जिला हरिजन एवं समाज कल्याण समाज कल्याण

हजार रु०में

: जनपद-झाँसी ।

क्र०सं०	योजना	1980-85	1985-86	1986-87 अनुदीर्घित परिचय			1986-87 अनुमानित व्यय			1987-88 हेतु प्रस्तावित परिचय		
		वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता का क्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
समाज कल्याण:-												
1-	नेत्रहीन बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान ।	110-00	144-00	149-00	-	-	149-00	-	-	180-00	-	-
2-	शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों को छात्र वृत्ति	--	--	20-00	-	-	20-00	-	-	20-00	-	-
3-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति	--	--	5-00	-	-	5-00	-	-	5-00	-	-
4-	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगवाने हेतु अनुदान ।	--	25-00	25-00	-	-	25-00	-	-	20-00	-	-
5-	निराश्रित विधवा अनुदान	172-90	888-00	930-00	-	-	930-00	-	-	1000-00	-	-
6-	मलिन बेहतर कालोनियों में शिक्षा शाला खोलना	--	--	50-00	-	-	--	-	-	--	-	-
7-	परियोजना कार्यक्रम	2274-00	674-20	596-00	-	-	596-00	-	-	600-00	-	-
योग समाज कल्याण:-		2556-90	1731-20	1775-00	-	-	1725-00	-	-	1805-00	-	-
2- नई योजना:-		--	--	--	-	-	--	-	-	--	-	-
योग चालू + नई योजना:-		2556-90	1731-20	1775-00	-	-	1725-00	-	-	1805-00	-	-

विभाग का नाम:- हरिजन एवं समाज कल्याण पुष्टाहार समाज कल्याण

हजार रुमें

: जनपद- झाँसी :

क्र०सं०	योजना	1980-85 वास्तविक व्यय	1985-86 वास्तविक व्यय	1986-87 अनुमोदित परिव्यय	1986-87 अनुमानित व्यय	1987-88 हेतु प्रस्तावित परिव्यय						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	कुल	पूँजीगत	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	

पूरक पुष्टाहार कार्यक्रम

समाज कल्याण

- 912-00 2622-00 - - 2622-00 - - 2622-00 - -

योग पुष्टाहार कार्यक्रम:-

- 912-00 2622-00 - - 2622-00 - - 2622-00 - -

विभागका नाम: कृषि:

जनपद झांसी

क्र.सं.	विवरण	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	छठी योजना वर्ष 1980-85 उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 86-87 लक्ष्य	अनामांकित उपलब्धि	वर्ष 87-88 लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	प्रदेश के मैदानी भागों में बीज विधायन संघों की स्थापना	कु0	3000	3000	10000	2000	5000	5000	5000
2.	प्रदेश के मैदानी भागों में गुणात्मक बीजों के सम्बद्ध संग्रहण एवं वितरण योजना	बी0कु0	1515	455	1000	600	500	500	500
क.	प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर 15 हाटोमटो का पवार प्रसार क्रय	संख्या	-	-	-	-	-	-	-1
ख.	प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर ट्रैक्टर गेरिज का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-1
ग.	प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर भूसा/गेन गोदाम का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-1
घ.	प्रक्षेत्र टाडा बमरौली पर सिंचाई नाली का निर्माण	मीटर	50	50	200	-	-	-	500
ड.	प्रक्षेत्र घिसौली पर ट्रैक्टर गेरिज का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	-
च.	प्रक्षेत्र घिसौली पर सिंचाई नाली निर्माण	मीटर	150	150	200	-	-	-	400
छ.	प्रक्षेत्र घिसौली पर भूसा/गेन गोदाम का निर्माण	संख्या	-	-	-	-	-	-	1
ज.	विकास खाण्ड बड़ागांव एवं बंगर के अन्तर्गत बरुआसागर एवं नकशार में राजकीय कुड़ा वोज भण्डार गृह का निर्माण 100मैटन क्षमता एवं 50 मैटन क्षमता	संख्या	-	-	-	2	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित दलहन फसल के उत्पादन की योजना								
॥क॥ दलहनी फसलो के प्रदर्शन	संख्या	570	570	815	210	200	200	200
4. प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कृषि रक्षा सेवा की योजना	संख्या							
॥क॥ विकास छाण्ड गुरसराय में कृषि रक्षा रसायन भण्डार गृह का निर्माण	संख्या	-	-	-	1	1	1	1

विभाग का नाम: उद्यान एवं फल उपयोग विभाग उ०प्र०

जनपद झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य	
		180-85 लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. वर्तमान उद्यानों के सुधार की योजना				इस योजना में एक लेखाकार तथा ट्रेक्टर ड्राइवर का पद स्वीकृत है, जिसके वेतन आदि के आहरण पद 50 हजार रु० व्यय होगा। वर्तमान उद्यानों के सुधार के अन्तर्गत पूंजीगत परिव्यय में निम्न कार्य आवश्यक हैं।					
				राजकीय उद्यान नारायण बाग झांसी का क्षेत्रफल 106 एकड़ है जिसकी शेष 2500 मीटर लम्बी ब्राउण्डी निर्माण अपेक्षित है इस पर विस्तृत कारण पूर्व में प्रेषित किये जा चुके हैं। इसके निर्माण हेतु ग्रामीण अभिवर्धन सेवा का आकलन 634 हजार का प्राप्त हुआ है।					
2. प्रदेश में आद्योगिक उत्पादन के सुदृढीकरण तथा बीज प्रोसेसिंग की स्थापना									
फलदार तथा शीभाकार पौधों का उत्पादन	सं०	1,00,000	14,50,300	12,50,000	1,26,400	1,65,000	1,70,000	1,80,000	
3. पिछड़े हुए अन्न क्षेत्रों में आद्योगिक विकास की योजना									
नये उद्यानों का रोपण	है०	250	276.80	250.00	51.75	50.00	55.00	60.00	
आलू के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	है०	100	185.50	100.00	51.50	30.00	30.00	35.00	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
मसाले के अन्तर्गत क्षेत्रफल	है०		250	322.47	500.00	50.9	50.00	50.00	55.00
शाकभाजी के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्रफल	है०		150	216.600	150.00	36.00	30.00	32.00	35.00

खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण  
केन्द्र की स्थापना :-

1. 24 सप्ताहीय वेकरी कुकरी तथा खाद्य संरक्षण का प्रशिक्षण	सं०		120	2100	60	33	60	50	30
2. 30 दिवसीय - पाककला, वेकरी तथा सम्मिलित कोर्स का प्रशिक्षण :	..		180	-	90	-	90	80	90

फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार  
एवं सुदृणीकरण की योजना :-

1. सामुदायिक फल संरक्षण	कि०ग्रा०	175000	158909	35000	26000	35000	35000	35000
2. फल संरक्षण प्रशिक्षण	संख्या	2350	2225	500	296	500	500	500

नोट: - 24 सप्ताहीय कोर्स के स्थान पर एक वर्षीय कोर्स हो जाने पर ।



भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -3

=====

विभाग का नाम: - कृषि विपणन

जनाद ब्लांसी

मद

इकाई

छठी योजना वर्ष  
1980-85सातवीं योजना  
1985-901985-86  
वास्तविक  
उपलब्धि

वर्ष 1986-87

वर्ष 1987-88

लक्ष्य

उपलब्धि

के प्रारम्भ का  
स्तर

लक्ष्य

अनुमानित  
उपलब्धि

लक्ष्य

1

2

3

4

5

6

7

8

9

चालू योजना :-राष्ट्रीय स्तर पर गोदामों  
का निर्माण

सं०

-

-

--

-

कृषि उत्पादन : मण्डी परिक्षेत्र मऊरानीपुर  
एवं चिरगांव में 500 मी०टन क्षमता वाले  
एक-एक गोदाम का निर्माण ।

कुल गोदाम - 2

भण्डारण क्षमता-1000मी०टन

नई योजना :-

शून्य

भूमि संधार -  
विभाग का नाम: - सीलिंग अनुभाग:

जनपद झांसी

सद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का उपलब्धि स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	
सीलिंग से प्राप्त भूमि आवंटियों के सहायता								
		आवंटियों की संख्या						
अ अनुजाति		1938	1938	1938	6	16	16	
ब जनजाति		683	638	638	2	4	4	

भागतक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

विभाग का नाम: - निजी लघु सिंचाई :-

जनपद झांसी

सद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

चालू योजनाओं की संख्या

1. सिंचाई कूप	संख्या	5020	5839	26804	842	800	800	850
2. रहट	..	2260	2332	11709	254	200	200	150
3. भूस्तरीय पम्पसेट	..	5730	6385	10239	1068	1000	1000	1000
4. नलकूप	..	400	541	562	132	100	100	120
5. बांधी निर्माण	हेक्टेअर में	133965	186032.5	—	53693	45000	45000	46000



विभाग का नाम: - भूमि एवं जल संरक्षण :

जनपद - झांसी

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
प्रदेश के मैदानी भागों में भूमि एवं जल संरक्षण की योजना ।								
अ) भूमि संरक्षण इकाई								
झांसी		6250	5735	-	379	1250	1250	1250
ब) भू.सं.अ. डी.पी.पी.								
झांसी		-	-	-	-	200	200	600
योग :-		6250	5735	-	379	1450	1450	1850

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-88
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवाओं में सुधार की योजना	सं०	862560	683560	-	160000	171000	171000	188000
2. पशुधन प्रक्षेत्र पर प्रजनन कार्य हेतु सांड़ों को उत्पादन की यों०	कि०मी०	-	-	-	-	-	-	2 नाली।
3. खुरपका, मुंहपका रोग की रोकथाम की योजना	सं०	-	-	-	2000	2000	2000	2000
4. प्रदेश में क०ग० के सुदृणीकरण की योजना	सं०	40500	40500	-	13800	13800	14650	15000
5. नये कुक्कुट प्रक्षेत्रों की स्थापना तथा वर्तमान कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृणीकरण की योजना	सं०	-	-	-	1	1	1	1
6. अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा क०ग० कार्यक्रम की सुदृणीकरण की यों०	केन्द्र	-	-	-	6	6	6	10
7. संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि के सहयोग से व्यवहारिक पुष्टाहार की योजना	विकास खण्ड	-	-	-	1	1	1	1

2.....



मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मत्स्य पालक								
<u>विकास भूमि करण :-</u>								
1. तालाबों का सुधार	है०	-	-	-	-	5.20	5.20	100
2. इन्पुदस		-	-	-	-	-	-	-
3. प्रशिक्षण	मत्स्य पालक संख्या	-	-	-	-	110	-	100



क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन प्रजातियों का वृद्धारोपण</b>								
अ-	रोपण	है०	1047	1047	-	-	-	-
ब-	भूमि सृजन	है०	347	347	-	-	-	-
स-	हवाई जहाज द्वारा बीज छिड़काव	है०	-	-	1185	1185	-	-
द-	1934 बीटिंग अपरुई	है०	-	-	297	297	297	297
ई	” ” ”	है०	-	-	300	300	300	300
फ-	पर्सरी में पौध उगाना	सं० लाख में	30.5	30.5	28.5	28.5	30	30
य-	अवशेष बची पौध को वर्ष भर रखरखाव	”	15.00	15.00	15.15	13.15	20 अनुमानित	20 अनुमानित
<b>2. संचार साधन :-</b>								
अ-	पुलिया निर्माण	सं०	7	7	-	-	1	1
ब-	रपटा		1	1	-	-	1	1
स-	सड़क निर्माण	मीटर में	160	160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3.	वन मनोरंजन/वन चेतना केन्द्रों की स्थापना								
अ-	कैटीन निर्माण	सं०	1	1	-	-	-	-	
ब-	मृग बिहार	सं०	1	1	-	-	-	-	
स-	भवन चक्की	सं०	1	1	-	-	-	-	
द-	चिड़ियाघर	सं०	1	1	-	-	-	-	
ई-	पौधशाला	सं०	1	1	-	-	-	-	
फ-	कृषक सुननाकेन्द्र	सं०	1	1	-	-	-	-	
ग-	बीज भण्डारण केन्द्र का निर्माण	सं०	-	-	-	1	1	-	
र-	वापोगैस	सं०	-	-	-	1	1	-	
ल-	मौन पालन	सं०	-	-	-	1	1	-	
व-	शौचालय एवं स्नानागार	सं०	-	-	-	-	-	1	
श-	वानिकी संग्रहालय	सं०	-	-	-	-	-	1	
द-	मृग बिहार में ग्रेड बनवाई	सं०	-	-	-	-	-	1	
4.	भवन								
अ-	वन रक्षक चौकी निर्माण	सं०	5	5	-	-	2	2	6
ब-	वाहर से आने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बिये ठहरने के लिये व्यवस्था	सं०	-	-	-	4	1	1	-
5.	वन कर्मचारियों को पेयजल विद्युत सुविधा तथा टांगिया मजदूर कृषकों को सुविधाएँ								
अ-	लेवर हाट निर्माण	सं०	7	7	1	1	2	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
व- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शौचालय निर्माण	सं०	-	-	3	3	-	-	-
स- कर्मचारियों को स्नान गृह का निर्माण	सं०	-	-	1	1	-	-	-
द- विजली व्यवस्था राौरा में	स्थान	-	-	-	-	-	-	राौरा में
र- हैण्ड पम्प लगाना	सं०	-	-	-	-	-	-	1
<b>6. सामाजिक वार्निकी</b>								
1. अधिष्ठाान	सं०	-	-	-	-	-	-	-
2. निर्माण कार्य								
क- पौधालय	नई पौध उगाना लाख में	-	-	-	-	10	10	10
ख- अग्रिम गिट्टी कार्य								
1. रेलवे लाइन	पं०कि०मी०/है०	-	-	20/6.6	20/6.6	20/6.6	20/6.6	30पं०कि०मी०
2. सडक के किनारे	-	-	-	10/6.5	10/3.3	-	-	50
3. वन भूमि	है०	-	-	70	70	258	258	300
4. ग्राम समाज	,,	-	-	-	-	50	50	-
ग- वृक्षारोपण								
1. रेलवे लाइन	पं०कि०मी०/है०	-	-	-	-	20/6.6	20/6.6	20पं०कि०मी०
2. सडक के किनारे	-	-	-	-	-	10/3.3	10/3.3	20
3. वन भूमि	है०	-	-	100	100	228	228	100
4. ग्राम समाज	,,	-	-	-	-	-	-	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
घ- भवन निर्माण								
प्रथम श्रेणी	संख्या	-	-	-	-	-	-	-
द्वितीय श्रेणी	"	-	-	-	-	-	-	-
तृतीय श्रेणी	"	-	-	-	-	-	-	5
चतुर्थ श्रेणी	"	-	-	-	-	-	-	2
3. मोटर गाड़ियां								
1. गाड़ियों का क्रय	"	-	-	2	2	-	-	-
॥ ट्रेक्टर ट्राली सहित ॥								
2. अनुरक्षण पेट्रोल आदि गाड़ियों की खारीद	"	-	-	2	-	2	2	-
च- मृत पौधों का बदलाव								
॥ वीटिंग अप कार्य ॥								
1. 1936 वरसात में रोपित मृत पौध का बदलाव								
अ- रेलवे लाइन	पं० कि०मी०	-	-	-	-	-	-	20
ब- सड़कों के किनारे	"	-	-	-	-	-	-	10
स- वन भूमि	है०	-	-	-	-	-	-	228
2. 1935 वरसात में रोपित मृत पौधों का बदलाव								
अ- वन भूमि	है०	-	-	-	-	-	-	100
ब- सड़कों के किनारे	पं० कि०मी०	-	-	-	-	-	-	10

विभाग का नाम: - पंचायतराज:  
जनपद झांसी ।

१६४१ भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-३  
=====

क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष		सातवीं योजना		1985-86 हास्तिक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 87-88 लक्ष्य
		1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	लक्ष्य		अनुमानित उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	पंचायत उद्योगों को तकनीकी तथा उद्योग प्रवर्धकीय सहायता	संख्या	3	3	3	3	2	2	1
2.	पंचायत राज संस्थाओं की आय में वृद्धि हेतु सहायता गांव सभा	„	15	15	15	3	3	3	3
3.	ग्रामीण पर्यावरण में स्वच्छता हेतु खड्गजा तथा नाली निर्माण	कि०मी०	20	14.6	14.6	5	4	4	5
4.	पंचायत भवनों का निर्माण गांव सभा	संख्या	17	11	11	10	10	10	12
5.	हाट बाजार तथा मेलों की स्थिति में सुधार हेतु गांव सभाओं को सहायक अनुदान	„	50	20	20	10	4	4	4
6.	पंचायत उद्योगों की कार्यालया भवन निर्माण	„	-	-	-	2	2	2	2
7.	जिला स्तर पर पंचायत भवन निर्माण	„	-	-	-	-	-	-	1
योग			85 20 कि०मी०	48 14.6 कि०मी०	49 14.6 कि०मी०	-	21 4 कि०मी०	21 4 कि०मी०	23 5 कि०मी०

सं. क्र.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90	1985-86	वर्ष 86-87		वर्ष 87	
		लक्ष्य	उपलब्धि	के प्रारम्भ का स्तर	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	स्वयं सेवकों का सुदृणीकरण	संख्या	-	-	80	80	118	118	150
2.	युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन	२२	15	15	40	40	50	50	60
3.	युवक मंगल दल सेमीनार	२२	9	9	9	9	9	9	9
4.	समाज सेवा कार्य मेला, प्रदर्शन, तीर्थयात्रा	२२	-	-	-	-	8	8	8
5.	प्रकीर्ण व्यय	रु०	2	2	4	4	10	20	12
6.	व्यवसायिक रोजगार	संख्या	8.3	8.3	-	-	8	8	8
7.	खेलकूद प्रतियोगिता	२२	45	110	9	9	9	9	9
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशाला प्रोत्साहन	२२	3	3	1	1	1	1	1
9.	श्रमदान प्रशिक्षण शिविर	२२	-	-	-	-	8	8	65
10.	युवकों का तैराकी प्रशिक्षण	२२	1	1	-	-	2	2	2

ब्लाक भवन

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1932-35 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1935-37 के प्रारम्भ का स्तर	1935-36 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1936-37 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1937-39 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विकास खाण्डों में आवासीय

भवनों का निर्माण सं० - - - - - 57

विकासखण्ड बडागांव,  
बागौर एवं मंगरा में  
19-19 आवासों का  
निर्माण/आंकलन संलग्न  
है ।

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर		1985-86 वास्तविक उपलब्धि		वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
स्कीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम		24000	20143	20143	प्रथम 2657 द्वितीय 2842	2249	2300	3000		
2. लघु सीमांत कृषक उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम										
1. लघु सिंचाई		x	x	x	=	-	-	-		
निःशुल्क दोरिंग		x	x	x	101	150	200	150		
2. चेकडेम		x	x	x	6	10	10	12		
3. तालाब		x	x	x	4	2	2	3		
4. बंधी					1	2	2	x		
2. अनुदान से लाभान्वित व्यक्ति		150	153	153	202	225	225	225		
3. मिनीकिट वितरण		8560	8560	8560	14067	15000	15000	15000		
4. भूमि सुधार	है०में	x	x	x	502	500	500	600		
5. नर्सरी स्थापनाउ		8	8	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		
3. सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम		1053	1053	1053	390	1575	1575	2280		



## सहकारिता

## भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3  
=====

सद	हकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना वर्ष 1985-90		1985-86 वास्तविक उपलब्धि		वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88
		लक्ष्य	उपलब्धि	के प्रारम्भ का स्तर		लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. जिला सहकारी बैंक की शाखाओं हेतु प्रवर्धकीय अनुदान		3	-	-	-	3 शाखाएँ		3		ठहरौली शाखा को तृतीय किस्त गरोठा एवं मुरानीपुर को द्वितीय किस्त तथा ग्रामिक चौक शाखा प्रथम किस्त कुल 32000/-
2. जिला सहकारी बैंक की शाखाओं का नवीनीकरण		-	-	-	-	2 रानीपुर गरोठा		2		ग्रामिक चौक शाखा
3. निर्वल वर्ग अनु जाति के लोगों को अन्न कृष हेतु ऋण अनुदान		500	100	-	500 सदस्य	500 सदस्य 100/- प्रति		500		500 सदस्य बनाने का लक्ष्य प्रत्येक सदस्य को 100/- तक सदस्य बनाने हेतु अन्न कृष करने के लिए धान उपलब्ध कराया जाएगा।
4. प्रारम्भिक कृषि त्रण समिति को उर्वरक व्यवसाय हेतु सीमांत धान		13	-	-	सात समितियों को 15000/- की दर से 105000/- रु० उपलब्ध कराया गया।	11 समिति		11 समिति		20 समितियों को 15000/- रु० प्रति समिति की दर से 3 लाख रु० उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय हेतु सीमांत धान	10	10	-	10 समितियों को 7500/- रु० प्रति समिति की दर से उपलब्ध कराया गया।	20 समिति	20 समितियों को 7500/- रु० प्रति 15000/- उपलब्ध कराया जा रहा है।	20 समितियों को 7500/- रु० प्रति समिति की दर से कुल 150000/- दिया जाना प्रस्तावित है।

विभाग का नाम: - विद्युत

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3 जनमद झांसी

क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्राम संख्या	-	172	200	36	-	-	-
2.	हरिजन वस्ती	-	149	150	46	-	-	-
3.	नलकूप	-	202	250	161	-	8-	-

गांधीजी एवं लघु: जनपद - झांसी  
उद्योग :-

१७११

भौतिक लक्ष्य उपलब्धि

जी.एन.-३

=====

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. औद्योगिक इकाईयों की स्थापना</b>								
१११. लघु/लघुत्तर	संख्या	400	819	1083	283	310	315	310
१२१. दस्तकारी	..	240	1326	2199	604	600	610	600
2. रोजगार	..	5000	7448	15420	1992	2150	2200	2150
<b>3. सहकारी समितियों का गठन</b>								
1. अवस्त्रीय	..	12	8	13	-	-	-	-
2. हस्तकला	..	6	7	22	-	-	-	-
<b>4. पंजीकरण</b>								
1. प्रस्तावित	..	930	1421	1882	347	-	375	-
2. स्थाई	..	420	819	1098	283	310	375	310
5. औद्योगिक आस्थान	..	1	-	-	-	-	-	-

विभाग का नाम: - राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र  
कोछाभावर, झांसी

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3

=====

सद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1930-35		सातवीं योजना 1935-40	1935-36 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1936-37	वर्ष 1937	वर्ष 1938
		लक्ष्य	उपलब्धि	के प्रारम्भ का स्तर		लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. केन्द्र की मशीनों की स्थापना	राजकीय पात्र केन्द्र, कोछाभावर झांसी	केन्द्र में वर्कशाप में सभी मशीनों की स्थापना		-	-	-	-	-
2. पात्रकार वर्कशेडों का निर्माण	..	निर्माणाधीन		सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हस्तगत कर लिया गया है एवं चार पात्रकारों को शेडों का आवंटन कर दिया गया है।	-	-	-	-
3. डी.डी. किल भट्टी का निर्माण एवं टेस्टिंग	..	-		-	-	-	-	20 डी.डी. का निर्माण प्रस्ताव
3अ- पात्रकारों का पंजीकरण	..	9		5	1	6	-	12
4. प्रशिक्षण	..	90		10	10	15	-	20
5. तकनीकी परामर्श	..	56		05	10	15	-	20
6. पात्रकारों को कच्चा माल उपलब्ध कराना एवं विक्री	..	वाणिज्य प्रक्रिया हेतु शासन से वजह उपलब्ध न होने के फलस्वरूप उत्पादन एवं विक्री नगण्य रही।		शासनद्वारा वित्तीय वर्ष में वजह अपेक्षित है जिसके लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।	-	2,00,000 रु का उत्पादन इकाइयों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5,00,000 रु एक इकाई द्वारा 32,000 रु उत्पादन प्रारम्भ हुआ।		2,50,000 रु

विभाग का नाम- हथकरघा, जनपद झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी. एन. -3

सद	खण्ड	छठी योजना वर्ष 1982-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. चालू योजना</b>								
1. हथकरघा संस० को अंश पूजा क्रम	सं०	65	73	73	8	10	10	10
2. हथकरघा संस० को प्रबन्धीय सहायता	सं०	45	51	51	13	10	10	11
3. हथकरघों का आधुनीकरण सं०		155	250	250	40	100	100	100
योग चालू योजना		268	374	374	61	120	120	120
<b>2. नई योजना</b>								
योग नई योजना		-	-	-	-	-	-	-
योग चालू + नई योजना		268	374	374	61	120	120	120

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ग्रामीण मार्ग :-

## 1. चालू योजनायें

कि०मी०	259.00	259.00	लेपित 259.00	लेपित 9.00	लेपन 15.0	15.00	लेपन स्तर	21.00
			वाटर	वाटर	वाउण्ड्री 326.00	वाउण्ड्री 57.00	मिदटी 5.00	5.00
			मिदटी 174.00	मिदटी 27.00	पुलिया 14.00	14.00	मध्य सतह	6.00
					सीलिंग 7.00	7.00	लघु सेतु	1

संगत योजनाओं  
में ॥

सद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. लक्ष्मी तालाब का विकास	तालाब संख्या	-	-	-	-	झांसी स्थित लक्ष्मी तालाब के प्रदूषण रोकने के लिये विस्तृत योजना बनाई गई है।		
2. सड़क निर्माण	कि०मी०	-	-	-	-	2	2	-
3. झांसी गण्डी समिति से नारायणा बाग तक सड़क का विद्युतीकरण	कि०मी०	-	-	-	-	2	-	3



1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. ग्रामीण क्षेत्र में सी.वे. स्कूलों को साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान 60101025	सं	50विधा.	69विधा.	65विधा.	15विधा.	15विधा.	15विधा.	15विधा.
15. जू.वे.स्कूलों में साज सज्जा तथा शिक्षण सामग्री हेतु अनुदान 60101025	,,	290 ,,	160 ,,	250 ,,	--	,, ,,	15 ,,	15 ,,
16. निर्दल वर्ग के बच्चों को पोशाक की व्यवस्था 60101026	,,	2000छात्र	1640छात्र	350छात्र	--	--	--	--
17. ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी.वे. स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार एवं विज्ञान सज्जा हेतु अनुदान 60108003	,,	20विधा.	20 विधा.	35 विधा.	3विधा.	3विधा.	3विधा.	3विधा.
18. अरेविक मटरसों को अनुरक्षण अनुदान 60108003	,,	2 ,,	1 ,,	2 ,,	--	1 ,,	1 ,,	1 ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. ग्रामीण क्षेत्र में छात्र संख्या में वृद्धि तथा स्थिरता हेतु निर्मल वर्ग के बालकों एवं बालिकाओं को पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु प्रोत्साहन अनुदान 60101009	₹	20000 छात्र	15333 छात्र	10000 छात्र	100छात्र	100छात्र	100छात्र	100 छात्र
3. नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र में वय वर्ग 6-14 बच्चों के लिए अकालिक कक्षाएँ खोलने हेतु अनुदान 60101011	..	575 केन्द्र	625 केन्द्र	पूर्व में खोले गये केन्द्रों पर व्यय हेतु ।				
9. ग्रामीण क्षेत्र में बालक एवं बालिकाओं के सी.वे. स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101010	..	31 विद्या.	6 विद्या.	40 विद्या.	3 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.
10. प्रत्येक जिले में जिला वे. शिक्षा अधीन कार्यालय का सुदृढीकरण 60101013	..	पखे/टी.	पखे/टी. ले.	ड्राइवर/टेलीफोन	-	ड्राइवर/टेलीफोन	ड्राइवर/टेलीफोन	ड्राइवर/टेलीफोन
11. प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 में 15/- रु० प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति 60101017	..	6 छात्र	65 छात्र	100 छात्र	220 छात्र	220 छात्र	220 छात्र	220 छात्र
12. वे. स्कूल में अध्यापकों को दक्षता प्रस्कीर 60101020	..	-	32 अध्यापक	40 अध्यापक	8 अध्यापक	8 अध्यापक	8 अध्यापक	8 अध्यापक
13. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने तथा सी.वे. स्कूलों में पाठ्य पुस्तक बैंक स्थापित करने हेतु अनुदान 60101022	..	150 विद्या.	108 वि.	40 वि.	-	8 विद्या.	8 विद्या.	8 विद्या.

क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना	1985-86	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987	
		लक्ष्य	उपलब्धि	के प्रारम्भ का स्तर	वास्तविक उपलब्धि	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र में भवन रहित जून्वेर विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु अनुदान 60101001	सं०	25 विद्या.	15 विद्या.	40 विद्या.	3 विद्या.	3 विद्या.	3 विद्या.	3 विद्या.
2.	असहायिक मान्यता प्राप्त अज्ञासकीय सी०वे० स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान 60101004	..	10 विद्या.	6 विद्या.	15 विद्या.	पूर्व के दो विद्यालयों को वेतन वितरण	पूर्व के दो विद्यालयों को वेतन वितरण		
3.	ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित जून्वेर स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101006	..	30 विद्या.	12 विद्या.	40 विद्या.	2 विद्या.	-	-	-
4.	ग्रामीण तथा नगर क्षेत्र के सी० वे० स्कूलों को भवन निर्माण हेतु अनुदान 60101005	..	17 विद्या.	13 विद्या.	20 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.	1 विद्या.
5.	नगर क्षेत्र में बालक तथा बालिकाओं के जून्वेर स्कूल खोलने हेतु अनुदान 60101007	..	5 विद्या.	1 विद्या.	5 विद्या.	-	-	-	-
6.	जून्वेर स्कूलों में विज्ञान शिक्षण में सुधार एवं विज्ञान साज सज्जा हेतु अनुदान 60101008	..	100 विद्या.	99 विद्या.	250 ..	-	17 विद्या.	17 विद्या.	17 विद्या.

विभाग का नाम: - खेलकूद विभाग: जनादर, झांसी ।

१७९१

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-३

=====

क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय अद्वितीय स्कूलों में खेलकूद केन्द्रों की स्थापना ।	सं० 1	1	2	2	2	2	2
2.	खेलकूद उपकरणों की सम्पूर्ति	..	-	-	-	-	-	-
3.	विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन	..	3	40	3	3	3	40
4.	क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण							
अ.	तरंगताल का निर्माण	-	-	-	-	-	-	1
ब.	क्रीड़ागणों का विकास समतलीकरण	-	-	-	-	-	-	स्टेडियम के शेष भाग का समतलीकरण ।

क्रम	काड	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>1. पाली टेकनिक का सुदृणीकरण</u>							
1.	डाटा प्रोसेसिंग कार्यक्रमों का प्रारम्भकरण	-	-	-	-	-	एक पाली टेकनिक
2.	इलेक्ट्रानिक अभियंत्रण हेतु एल.सी.डी./ अ-सी.डी. आर.सी. व टी.वी. लेवनिर्माण	-	-	-	-	-	एक 150 वर्गमीटर
ब-	एल.सी.डी. लेव व इलेक्ट्रानिक्स लेव	-	-	-	-	-	एक 150
स-	डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स लेव एवं एन.एफटी. लेव	-	-	-	-	-	एक 150
द-	इं.डी. लेव एवं इं.ड. कण्ट्रोल लेव	-	-	-	-	-	एक 150
घ-	क्लास रूम	-	-	-	-	-	दो 120
च-	स्टाफ रूम	-	-	-	-	-	एक 30
ल-	ड्राइंग हाल	-	-	-	-	-	एक 120
3.	साज सज्जा का आधुनीकरण	-	-	-	-	-	-
4.	पुस्तकालय सुदृणीकरण	-	-	-	-	-	-
5.	विद्यार्थियों को सुविधा-वाटर कूलर करना 180	-	-	-	-	-	दो

विभाग का नाम: - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य  
जनपद झांसी ।

1811

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3  
=====

क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य	
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	प्रा. स्वा. केन्द्रों का भवन निर्माण	सं०	6	2	4	-	2	1	1
2.	उप केन्द्रों का भवन निर्माण	..	40	32	139	8	4	4	18
3.	अति० प्रा०स्वा० केन्द्रों की स्थापना	..	2	2	25	2	3	3	5
4.	उच्चिकृत प्रा०स्वा० केन्द्रों का रखरखाव एवं भवन निर्माण	..	2	2	2	-	2	1	1
5.	उच्चिकृत प्रा०स्वा० केन्द्रों में जनरल टरो की व्यवस्था	..	-	-	3	-	-	-	1
6.	चीर गृह का निर्माण	..	-	-	2	-	1	-	1
7.	उच्चिकृत प्रा०स्वा० केन्द्रों में चिकित्सीय विशिष्ट सुविधाएँ	..	-	-	3	-	-	-	1
8.	होम्योपैथिक औषधालय की स्थापना	..	-	-	2	-	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	सं०	13	3	14	1	4	2	3
2. शहरी क्षेत्रों में 25 शैयायुक्त नये आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना	,,	1	-	-	-	1	1	1
3. वर्तमान आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा तथा नये औषधालय का प्रोन्नयन एवं उनकी स्थिति में सुधार	,,	-	14	14	-	15	15	17
4. राज्यकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण	,,	1	-	-	-	1	-	1

विभाग का नाम: - ग्राम्य विकास विभाग, झांसी ।

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-3  
=====

ग्रामीण पेयजल								
मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87	वर्ष 1987-88	
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ग्रामीण हरिजन  
पेयजल योजना

संख्या

91

102 कूप

13 कूप

100

-

-

16

26 है०प०

15 है०प०



मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88
		लक्ष्य	उपलब्धि			लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. हैण्डपम्प	ग्राम	--	382	204	235	88 नए हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्प के स्थान पर ॥ जिला योजना ॥ 70 ग्राम-11 हैण्डपम्प ॥ त्वरित कार्यक्रम ॥ 151 ग्राम-536 हैण्डपम्प ॥ तुरंत कार्यक्रम सेचुरेशन ॥ 7 ग्राम 70 हैण्डपम्प ॥ सूखा राहत ॥		
2. पण्डप	ग्राम	--	160	--	--	--	--	1 ग्राम

विभाग का नाम: - ग्राम्य विकास विभाग, झांसी

१४५१

भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

जी.एन.-३  
=====

निर्दल वर्ग आवास

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निर्दल वर्ग आवास	संख्या	378	378	400	76	--	--	100

क्र	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85		सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87		वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	लक्ष्य	उपलब्धि	3	4	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	5

चालू योजना :-

सेवायोजन कार्यालय का सुदृढीकरण भवन निर्माण

भवनसंख्या

—

--

एक भवन निर्माण

-

भूखण्ड प्राप्त किया जाना

एक भवन भूमि अध्याप्ति प्रक्रिया प्रगति में है।

भवन निर्माण

नई योजना :-

झांसी स्थित कार्यालय क्षेत्रीय है इसमें जीप की व्यवस्था का प्राविधान प्रस्तावित है। जीप के अनुमान एवं ड्राइवर का 6 माह का वेतन एवं आकस्मिक व्यय पी.ओ.डब्लू. के आगमन संलग्न है।

--

-

-

—

एक जीप

1878  
भौतिक लक्ष्य उपलब्धि

जी. एन. -3  
=====

विभाग का नाम: - प्रशिक्षण एवं सेवायोजन गिल्डकार प्रशिक्षण।

क्र.सं.	इकाई	छठी योजना वर्ष 1980-85 लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना 1985-90 के प्रारम्भ का स्तर	1985-86 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1986-87 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1987-88 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. चालू योजना :-

साज सज्जा की पूर्ति

वर्तमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के  
विस्तार एवं सुदृणीकरण

नई योजना  
=====

वर्तमान औ० प्र० संस्थान  
एवं भवनों की वाउण्ड्री  
वाल का निर्माण

वाउण्ड्री वाल. क्षेत्र 1005 एमx2एम  
x30एम =603 सौ एम

मद	इकाई	छठी योजना वर्ष 1930-35 लक्ष्य	सातवीं योजना 1935-40 के प्रारम्भ का स्तर	1935-36 वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 1936-37 लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	वर्ष 1937-38 लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8

चालू योजनाएँ :-

अ- अनु० जातियों का कल्याण

1. शिक्षा :-

1. छात्रवृत्ति माध्यम पुस्तकीय तथा उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता

क- जूनियर हाई स्कूल स्तर 6-8

1. निर्धनता के आधार पर	संख्या	-	1562	-	468	468	500
2. योग्यता के आधार पर	संख्या	-	-	-	208	208	225
ख- प्राइमरी स्तर 1-5							
1. निर्धनता के आधार पर	"	-	-	-	437	500	550
2. योग्यता के आधार पर	"	-	-	-	291	300	350
2. अनु० जातियों के छात्रों को लिये अमर चंटी कास्ट अनुदान	"	-	333	-	83	200	225
3. दशम/दशमोत्तर कक्षाओं की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण छात्रों को विशेष पुरस्कार	"	-	101	-	12	12	15

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग :-

१८९  
१२

	२	३	४	५	६	७	८	९
	संख्या							
४. लुक बैंक की स्थापना	२	---	४०	---	८	८	८	१०
५. अनकलीन प्रोफेशन जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विद्यार्थियों को पूर्ण दशम कक्षाओं में छात्रवृत्ति	२	---	---	---	७०	---	---	---
६. विभाग द्वारा सहायता प्राप्त पाठशाला, पुस्तकालय एवं छात्रावासों को सुधार/विस्तार	२	---	३	---	३	३	३	३

आर्थिक उत्थान :-

=====

७. कृषि वागवानी अनुदान	२	---	११६	---	---	१६	१६	१६
८. कुटीर उद्योग अनुदान	२	---	२५८	---	---	२४	२४	२४
३. स्वास्थ्य/आवास संबंधी अन्य योजनाओं :-								
१. गृह निर्माण	२	---	४१०	---	---	२००	२००	२००

अनु० जनजातियों का कल्याण :-

प्राइमरी स्तर १-५

१. निर्धनता के आधार पर	२	---	---	---	---	७५	७५	८०
२. योग्यता के आधार पर	२	---	---	---	---	५०	५०	६०

विमुक्त जातियों का कल्याण :-

=====

१. छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तकीय एवं उपकरण हेतु अनावर्तक सहायता ।

## हरिजन एवं समाज कल्याणः -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>क- जू० हाई स्कूल स्तर :</u>								
1. निर्धनता के आधार पर	संख्या	-	15	-	13	13	13	20
2. योग्यता के आधार पर	संख्या	-	-	-	8	12	12	14
<u>प्राइमरी स्तर 1-5</u>								
1. निर्धनता के आधार पर	संख्या	-	-	-	25	57	37	40
2. योग्यता के आधार पर	..	-	-	-	17	212	212	215
<u>विमुक्त जातियों का आर्थिक उत्थानः</u>								
1. कुटीर उद्योग अनुदान	..	-	73	-	-	64	64	70
2. कृषि वागवानी अनुदान	..	-	30	-	-	40	40	50
<u>स्वास्थ्य आवास :-</u>								
गृह निर्माण एवं ऋण अदायगी	..	-	35	-	-	200	200	-
<u>2. समाज कल्याण :-</u>								
1. नेत्रहीन, लधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांगों को अनुदान	..	-	246	-	246	270	270	280
2. शारीरिक रूप से अक्षम तथा हड्डी के रोग से ग्रस्त विद्यार्थियों को शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अनुदान	..	-	28	-	40	50	50	60

4.....

## हरिजन एवं समाज कल्याण :-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र	संख्या	-	-	-	12	12	12	14
4. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, सामान खारी देने हेतु अनुदान आश्रम पद्धति विद्यालय कबूतरा जाति बाल कल्याण	..	-	-	-	15	20	20	22
5. समन्वित बाल विकास परियोजना	..	एक	एक	-	एक संस्था	एक संस्था	एक संस्था	एक संस्था
6. शहरी ग्रामीण क्षेत्र की मलिन गेहलर कालोनिजों शिशुशालाओं को खोलना	..	-	-	-	2 केन्द्र		2 केन्द्र	2 केन्द्र
7. निराश्रित विधवाओं को सहायता अनुदान	..	-	275	-	1394		1500 विधवाएँ	1800
8. पुष्पाहार कार्यक्रम	..	-	30792	-	100000		250000	220000



NEPA DC

D03814

Sub. National Systems Unit,  
 National Institute of Education  
 Planning and Administration  
 17-A, Ansari Road, New Delhi-11001  
 DOC. No. 3814  
 Date: 10/6/87